महानगर नई दिल्ली सोमवार 12 अगस्त, 2019, रु. 5.00 (12 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

भारत ने अपनी ओर से रोकी समझौता एक्सप्रेस

पाक के एकतरफा फैसले की प्रतिक्रिया में उठाया कदम

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

भारत ने रविवार को घोषणा की है कि उसने अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा तक समझौता एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन बंद कर दिया है। इससे कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र में ट्रेन सेवाएं रोक दी थीं। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, 'अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस और दिल्ली लाहौर बस सेवा रोक दी है। पाकिस्तान ने बिना सूचना दिए यह फैसला लिया है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत को भी यह फैसला लेना पड़ा है।'

भारतीय रेलवे हर रविवार को दिल्ली से अटारी और अटारी से दिल्ली के बीच ट्रेन का परिचालन करता था

भारतीय रेलवे हर रविवार को दिल्ली से अटारी और अटारी से दिल्ली के बीच इस ट्रेन का परिचालन करता था जबकि पाकिस्तान में यह ट्रेन लाहौर से अटारी के बीच चलाई जाती थी। यात्री अटारी स्टेशन पर ट्रेन बदलते थे। विदेश मंत्रालय के बाकी पेज 8 पर

समझौता एक्सप्रेस

जम्मू-कश्मीर में हालात शांतिपूर्ण, लोगों की मदद में जुटी सरकार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

ईद-उल-अजहा के पहले घर-घर जरूरी सामान पहुंचाने के लिए जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने विशेष तैयारियां की हैं। सरकारी वाहनों में सब्जियां, अनाज व अन्य भोजन सामग्री पहुंचाई जा रही है। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक कश्मीर में पिछले छह दिनों से एक भी गोली नहीं चली है, हालात शांतिपूर्ण हैं। त्योहार से पहले यहां बैंक, एटीएम और कुछ बाजार खुले रहे और तमाम प्रतिबंधों में ढील दी गई ताकि लोगों को त्योहार की खरीदारी करने में आसानी हो। ईद के मद्देनजर करीब 300 टेलिफोन बूथ बनाए गए हैं, जिसके बाकी पेज 8 पर

पाक में उच्चायुक्त बिसारिया लौटे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त अजय बिसारिया देश लौट आए हैं। केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जा देने वाले संविधान बाकी पेज 8 पर

370 हटने से खत्म होगा आतंकवाद : शाह

चेन्नई, 11 अगस्त (भाषा)।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने से क्षेत्र में आतंकवाद का खात्मा होगा और क्षेत्र विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेगा।

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के दो साल के कार्यकाल पर एक किताब का यहां विमोचन करने के मौके पर शाह ने कहा कि उनका दृढ़ता से मानना था कि जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाया जाना चाहिए क्योंकि इससे देश को कोई फायदा नहीं था। उन्होंने कहा, 'मैं दृढ़ था कि अनुच्छेद 370 हटाया जाना चाहिए...अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कश्मीर में आतंकवाद खत्म होगा और वह विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा।' साथ ही कहा कि इस कदम के बाद क्या होगा इस बारे में उनके मन में जरा भी भ्रम नहीं था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा नीत सरकार ने इस देश को अनुच्छेद 370 से मुक्त कराया।

"मैं दृढ़ था कि अनुच्छेद 370 हटाया जाना चाहिए...अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कश्मीर में आतंकवाद खत्म होगा और वह विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। -अमित शाह

शाह ने जम्मू कश्मीर संबंधी विधेयक लाने के दौरान ऊपरी सदन में बने हालात से कुशलतापूर्वक निपटने के लिए राज्यसभा के सभापति नायडू को भी श्रेय देते हुए कहा कि उन्हें आंध्र प्रदेश के बंटवारे के दौरान बने हालात के दोहराने की 'आशंका' थी।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि सांसद होने के नाते उनके मन में जरा भी भ्रम नहीं था कि अनुच्छेद 370 को हटाया जाना चाहिए या नहीं। उन्होंने किताब विमोचन के दौरान भारतीय बैडमिंटन बाकी पेज 8 पर

पाक में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा क्षतिग्रस्त

लाहौर, 11 अगस्त (भाषा)।

पाकिस्तान के लाहौर शहर में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा को दो लोगों ने शनिवार को क्षतिग्रस्त कर दिया। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

19वीं सदी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले महाराजा रणजीत सिंह की नौ फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण लाहौर किले में जून में उनकी 180वीं पुण्यतिथि पर किया गया था। महाराजा रणजीत सिंह का 1839 में निधन हो गया था। कांसे से बनी इस प्रतिमा में महाराजा सिख पोशाक पहने, हाथ बाकी पेज 8 पर

पीओके में 150 आतंकियों के जुटने की खबर, सेना सतर्क

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

अनुच्छेद 370 के प्रावधान खत्म किए जाने के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी शिविरों को चालू किए जाने और घुसपैठ की फिराक में सीमा पर आतंकियों के जुटने का इनपुट खुफिया एजंसियों ने जुटाया है। इसके बाद नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सेना की अग्रिम चौकियों को हाई अलर्ट पर रहने के आदेश दिए गए हैं।

पीओके के कोटली, रावलकोट, बाघ और मुजफ्फराबाद में आतंकवादियों की गतिविधियां देखी गईं।

खबरें आई हैं कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में नियंत्रण रेखा और जम्मू-कश्मीर से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा पर दर्जन भर आतंकी शिविरों को फिर सक्रिय कर दिया गया है। पूरी तरह बंद कर दिए गए आतंकी शिविरों में पिछले सप्ताह के दौरान सक्रियता बढ़ गई है। खुफिया एजंसियों का इनपुट है कि पीओके के कोटली, रावलकोट, बाघ और मुजफ्फराबाद में आतंकी शिविर फिर सक्रिय कर दिए गए हैं। इसके मद्देनजर सेना एवं बाकी पेज 8 पर

सोनिया ने संभाली कमान, चुनावी राज्यों पर करेंगी मंथन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

कांग्रेस की नई अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी इसी सप्ताह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं संग बैठक कर विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में पार्टी की चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगी। महज डेढ़ साल के अंतराल के बाद दोबारा अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने वाली सोनिया के सामने चुनाव वाले इन राज्यों में पार्टी का नया नेतृत्व देने की चुनौती भी है।

कांग्रेस कार्यसमिति की शनिवार रात हुई बैठक में राहुल गांधी का इस्तीफा स्वीकार कर सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया जिसे उन्होंने थोड़ी हिचक के साथ स्वीकार कर लिया। सोनिया गांधी वर्ष 1998 से लेकर 2017 तक, करीब 19 साल के सबसे लंबे कार्यकाल तक कांग्रेस अध्यक्ष रहीं। उनके बेटे राहुल गांधी को दिसंबर, 2017 में पार्टी अध्यक्ष बनाया गया लेकिन उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद ही अपना इस्तीफा दे दिया। वे करीब डेढ़ साल तक इस पद पर रहे। इस प्रकार महज डेढ़ साल के अंतराल पर सोनिया गांधी फिर से पुरानी भूमिका में वापस आ गई हैं।

सूत्रों की मानें तो सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनने के बाद रविवार को किसी भी नेता से नहीं मिलीं। अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड रवाना होने से पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनसे मिलने जरूर उनके निवास पर पहुंचे लेकिन किसी अन्य पार्टी नेता की उनसे मुलाकात नहीं हुई। हालांकि कार्यसमिति के एक सदस्य ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष इसी सप्ताह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं संग देश के ताजा हालात में कांग्रेस की भूमिका को लेकर विचार विमर्श करेंगी और संगठन में नए सिरे से जान फूंकने की रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि खास तौर पर चुनाव वाले राज्यों में नेतृत्व को लेकर जल्दी फैसला लिए जाने की उम्मीद है।

झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं जबकि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित का देहांत हो चुका है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर को हटाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट लगातार सक्रिय है। ऐसे में बाकी पेज 8 पर

महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति

चार में से दो राज्यों में नए अध्यक्षों की होगी नियुक्ति जबकि हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन का दबाव

राहुल गए लेकिन कुर्सी पर जमी रहेगी उनकी युवा टीम - खबर पेज 8 पर

रतुल पुरी और उनके पिता का दिल्ली का बंगला, एफडीआइ राशि जब्त

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

आयकर विभाग ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी और उनके पिता के खिलाफ बेनामी संपत्ति रोधी कानून के तहत अपनी जांच के सिलसिले में दिल्ली के पॉश इलाके में स्थित 300 करोड़ रुपए के बंगले और चार करोड़ डॉलर (करीब 284 करोड़ रुपए) की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) राशि को जब्त किया। अधिकारियों ने रविवार को इस बारे में जानकारी दी।

अगस्ता वेस्टलैंड मामले में आयकर विभाग की कार्रवाई

अधिकारियों के मुताबिक, रतुल पुरी का यह बंगला लुटियन दिल्ली में एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर स्थित है और यह संपत्ति मोजर बेयर समूह की एक कंपनी रामा एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है, जिसके मालिक और प्रवर्तक रतुल पुरी के पिता दीपक पुरी हैं। इसके अलावा बेनामी संपत्ति रोधी कानून के तहत अस्थायी तौर पर चार करोड़ डॉलर की एफडीआइ राशि समेत संपत्ति की जब्ती की गई है। यह संपत्ति रतुल पुरी तथा दीपक पुरी के खिलाफ मामले से जुड़ी है।

रतुल पुरी के खिलाफ आयकर विभाग की इस तरह की दूसरी कार्रवाई है। आयकर विभाग अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआइपी हेलिकॉप्टर मामले के संबंध में धनशोधन के आरोपों की जांच कर रहा है। इससे पहले, दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को बाकी पेज 8 पर

अनुराग ने बंद किया ट्विटर अकाउंट

मुंबई, 11 अगस्त (भाषा)।

बॉलीवुड निर्देशक अनुराग कश्यप ने अपना आधिकारिक ट्विटर अकाउंट डिलीट (बंद) कर दिया है। फिल्मकार का कहना है कि उन्होंने माइक्रोब्लॉगिंग साइट छोड़ने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि उनके माता-पिता और बेटी को धमकियां मिल रही थीं।

कहा, बिना डर के बोल नहीं सकता, तो बोलूंगा ही नहीं

सोशल मीडिया पर सबसे मुखर माने जाने वाली बॉलीवुड हस्तियों में से एक कश्यप ने कहा कि यदि वह इस मंच पर अपने मन की बात कहने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, तो वह इसे छोड़ देंगे। उन्होंने कहा, 'जब आपके माता-पिता को फोन आने शुरू बाकी पेज 8 पर

मेट्रो कर्मचारी ने फेसबुक पर लाइव आकर की आत्महत्या

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

फर्श बाजार थाना क्षेत्र में दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के एक कर्मचारी ने फेसबुक पर लाइव आकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी युवक के दोस्तों ने रविवार सुबह करीब 9 बजे पुलिस को 100 नंबर पर फोन कर जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि शुभांकर चक्रवर्ती (27) का शव प्लास्टिक की रस्सी के सहारे पंखे की हुक से लटका हुआ था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए सब्जी मंडी शवगृह में रखवा दिया है। पुलिस का कहना है कि घटनास्थल से पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। इस कारण मौत के सही कारणों का पता नहीं चल सका है।

दोस्तों ने वीडियो देख पुलिस को दी जानकारी

पश्चिम बंगाल का रहने वाला था युवक

पुलिस ने बताया कि घटना की जानकारी शुभांकर के परिजनों को दे दी गई है। उनके आने के बाद शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। फिलहाल पुलिस शुभांकर के दोस्तों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है। जिला पुलिस के एक बाकी पेज 8 पर

सीबीएसई : कक्षा 10 और 12 का परीक्षा शुल्क दोगुना

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा शुल्क बढ़ाकर दो गुना कर दिया है। पहले विद्यार्थियों को पांच विषयों की परीक्षा के लिए 750 रुपए देने होते थे। बोर्ड ने इसे बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया है। विद्यार्थियों को अतिरिक्त विषय के लिए 150 रुपए के बजाय अब 300 रुपए का शुल्क देना होगा। एक अक्तूबर से 14 अक्तूबर के बीच हर विद्यार्थी से विलंब शुल्क के रूप में 2000 रुपए लिए जाएंगे।

सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज ने बताया कि बोर्ड बिना लाभ-हानि वाले सिद्धांत पर बाकी पेज 8 पर

750 रुपए देने होते थे पहले पांच विषयों की परीक्षा के लिए, अब 1500 देने होंगे

विद्यार्थियों को अतिरिक्त विषय के लिए पहले 150 रुपए देने होते थे, अब 300 रुपए का शुल्क देना होगा।

2016-17 में 470.90 करोड़ रुपए की बिक्री हुई | **बदला दौर** | 2018-19 में बिक्री 78.25 करोड़ रुपए रह गई

रुपए में चवन्नी भी नहीं रह गई डाक टिकटों की बिक्री

इंदौर, 11 अगस्त (भाषा)।

वाट्सऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया की लोकप्रियता के दौर में चिट्ठी-पत्री का चलन कम होता जा रहा है। हालत यह हो गई है कि डाक टिकटों की बिक्री में भारी गिरावट दर्ज की गई है।

सूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून के तहत मिले डाक विभाग के आधिकारिक आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं, जिनके मुताबिक टिकटों की बिक्री में साल-दर-साल गिरावट आती जा रही है। मध्य प्रदेश के नीमच निवासी आरटीआइ कार्यकर्ता द्वारा हासिल इन आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में डाक विभाग को टिकटों की बिक्री से मिलने वाला राजस्व इसके पिछले साल के मुकाबले 78.66 फीसद घटकर 78.25 करोड़ रुपए रह गया। वित्तीय वर्ष 2017-18 में डाक विभाग ने टिकट बेचकर 366.69 करोड़ रुपए कमाए थे। वित्तीय वर्ष 2016-17 में डाक विभाग ने टिकट बिक्री से अपने खजाने में 470.90 करोड़ रुपये जमा किए थे।

डाक विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि यह महकमा आम डाक टिकटों के अलावा राजस्व टिकट, फिलैटली (डाक टिकटों का शौकिया संग्रह) के टिकट और अन्य टिकट भी बेचता है। हालांकि, महकमे के सकल टिकट राजस्व में सबसे बड़ा हिस्सा डाक टिकटों का ही होता है।

367 करोड़ रुपए (लगभग) कमाए थे डाक विभाग ने टिकट बेचकर वित्तीय वर्ष 2017-18 में

डाक टिकटों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए डाक विभाग 'माय स्टाम्प' योजना चला रहा है। इसमें निजी पसंद पर आधारित डाक टिकटों की शीट है।

इंदौर के तिलक नगर स्थित डाकघर में पदस्थ एक वरिष्ठ पोस्टमैन ने बताया, 'एक जमाना था, जब हमारा थैला चिट्ठियों से ठसाठस भरा रहता था। इसमें निजी और सरकारी सब तरह की ढेरों चिट्ठियां होती थीं, लेकिन अब निजी पत्र कम ही देखने को मिलते हैं। इन दिनों हमारे थैले में अलग-अलग सरकारी विभागों और निजी कंपनियों की चिट्ठियों की भरमार होती है।' जनमानस पर संचार के आधुनिक साधनों के प्रभावों को लेकर मनोविज्ञानियों की भी नजर बनी हुई है। पेशेवर मनोविज्ञानी डॉ. स्वाति प्रसाद ने कहा, 'यह सच है कि हाथों से लिखी चिट्ठी पढ़कर मन में अपनेपन की अनुभूति होती है और अक्सर ऐसे पत्र से एक भावनात्मक याद जुड़ जाती है। लेकिन इस तेज रफ्तार दौर में सोशल मीडिया और तुरंत संदेश भेजने वाली सेवाओं का भी अपना महत्व है। सवाल बस इतना है कि आप संचार बाकी पेज 8 पर

"यह सच है कि हाथों से लिखी चिट्ठी पढ़कर मन में अपनेपन की अनुभूति होती है और अक्सर ऐसे पत्र से एक भावनात्मक याद जुड़ जाती है। लेकिन इस तेज रफ्तार दौर में सोशल मीडिया और तुरंत संदेश भेजने वाली सेवाओं का भी अपना महत्व है। सवाल बस इतना है कि आप संचार के साधनों का इस्तेमाल किस तरह करते हैं?

-डॉ. स्वाति प्रसाद, मनोविज्ञानी

वित्त मंत्री से मिले जायदाद कारोबारी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को रीयल एस्टेट क्षेत्र के प्रतिनिधियों व घर खरीदारों से मुलाकात की। प्रतिनिधियों ने बैठक में नकदी संकट, मांग में कमी व रुकी परियोजनाओं को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की। सरकार ने कहा कि वह जल्दी ही रीयल एस्टेट क्षेत्र को प्रभावित कर रही दिक्कतों को दूर करेगी। सीतारमण ने पहली मुलाकात क्षेत्र के दो शीर्ष संगठनों क्रेडाई और नारेडको के साथ की। दूसरी मुलाकात घर खरीदारों के प्रतिनिधियों से की। इसमें उन्होंने रीयल एस्टेट क्षेत्र को प्रभावित कर रही दिक्कतों व समाधान पर चर्चा की। बैठक में आवासीय एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर व आर्थिक मामलों, राजस्व, आवास, सीबीडीटी, कॉरपोरेट मामलों व रेरा के शीर्ष अधिकारी भी शामिल रहे।

बैठक के बाद पुरी ने मीडिया से कहा– रीयल एस्टेट उद्योग के साथ बैठक में सार्थक चर्चा हुई। हमने कई मुद्दों पर बातचीत की, कई मामलों को स्पष्ट किया। सरकार इन मुद्दों का आने वाले दिनों में समाधान निकालेगी। उन्होंने कहा– घर खरीदारों, रुकी परियोजनाओं आदि की जो भी समस्याएं हैं, हम इनका समाधान निकालने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कई घर खरीदारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कुछ मामलों में निर्णय भी आए हैं। इस कारण यह बेहद जटिल है। क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं, हम उनका समाधान निकालेंगे। फोरम फोर पीपुल्स कलेक्टिव एफर्ट्स के अध्यक्ष अभय उपाध्याय ने कहा कि परियोजनाओं में देरी से देश भर में पांच लाख से अधिक उपभोक्ता प्रभावित हैं। उन्होंने इन परियोजनाओं को पूरा करने व घर खरीदारों को राहत देने के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का एक कोष बनाने की मांग की। जेपी समूह के घर खरीदारों ने वित्त मंत्री को बताया कि प्रवर्तकों के पास इतनी सारी जमीनें व यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना जैसी अन्य संपत्तियां होने के बाद भी ये परियोजनाएं पूरी नहीं हो रही हैं।

क्रेडाई के अध्यक्ष सतीश मगर ने कहा कि सरकार ने रीयल एस्टेट उद्योग को प्रभावित कर रहे मुद्दों के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। जबकि नारेडको के अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी ने कहा कि चूंकि अर्थव्यवस्था के साथ ही रीयल एस्टेट क्षेत्र संकट से गुजर रहा है, ऐसे में हम उत्साहित हैं कि वित्त मंत्री ने हमारे साथ बैठक की। उधर, एक रिपोर्ट में अनुमान व्यक्त किया गया है कि भारत में हो रहे आर्थिक बदलाव, कामगारों की संख्या में वृद्धि व बढ़ते शहरीकरण से अगले दशक में रीयल एस्टेट क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ेंगे। क्रेडाई और सीबीआरई की यहां रीयल एस्टेट सम्मेलन में जारी संयुक्त रिपोर्ट में यह जानकारी देते हुए कहा गया है कि आने वाले समय में भारत में आवासीय क्षेत्र, कार्यालय, खुदरा व वेयरहाउस के क्षेत्र में संपत्तियों की मांग में वृद्धि देखने को मिलेगी।

सीबीआरई ने रिपोर्ट में कहा कि साथ में काम करने, साथ में रहने, छात्रों के लिए आवासीय सुविधाओं और रीयल एस्टेट इंवेस्टमेंट ट्रस्ट जैसी नई संपत्ति श्रेणियों की अगुवाई में 2030 तक रीयल एस्टेट क्षेत्र तेजी से वृद्धि करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक कार्यालय से संबंधित संपत्ति का आकार बढ़कर एक अरब वर्गफुट पर पहुंच जाएगा व इसमें आठ–10 फीसद हिस्सेदारी लचीले कामकाजी क्षेत्र की होगी। 2030 तक खुदरा दुकानों का स्टॉक 12 करोड़ वर्गफुट और भंडारण स्टॉक 50 करोड़ वर्गफुट पर पहुंच जाएगा।

ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप आपराधिक इरादे से लगाए गए : अरोड़ा

कोलकाता, 11 अगस्त (भाषा)।

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सुनील अरोड़ा ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से छेड़छाड़ के आरोप बहुत अनुचित हैं और ये एक आपराधिक इरादे से लगाए जाते हैं।

अरोड़ा ने आइआइएम–कलकत्ता के वार्षिक 'बिजनेस कान्क्लेव' में शनिवार को कहा कि मशीनों में यदाकदा खराबी आ सकती है, जैसा अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरणों में आती है लेकिन इससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा, 'खराबी, छेड़छाड़ से बहुत अलग है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। यदि आप ऐसा कहते हैं तो आपका कोई आपराधिक इरादा है जो हमें खराब लगता है।' अरोड़ा ने कहा कि दो अत्यंत प्रतिष्ठित सार्वजनिक कंपनियों ने ईवीएम डिजाइन की है। उन्होंने कहा, 'ईवीएम को एक सुरक्षित माहौल में बनाया गया था और प्रतिष्ठित संस्थानों के एमेरिटस प्रोफेसरों ने पूरी प्रक्रिया की निगरानी की।' अरोड़ा पश्चिम बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जूरिडिकल साइंसेज और आइआइएम (कलकत्ता) द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए शहर में थे। उन्होंने इस ओर इशारा करते हुए कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद ही ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप लगाए। उन्होंने कहा, 'यह बहुत अनुचित है। जब आप हारते हैं तो मशीन को निशाना क्यों बनाना?' उन्होंने कहा, 'आरोप चुनाव आयोग और वोटिंग मशीन बनाने वालों की ईमानदारी पर सवाल उठाते हैं।

दक्षिण–पश्चिम भारत में बाढ़ और बारिश से 183 की मौत

शाह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया

तिरुवनंतपुरम/मुंबई, 11 अगस्त (भाषा)।

कई दिनों से बारिश से बेहाल केरल में रविवार को भले ही वर्षा में कमी आई लेकिन इससे जुड़ी घटनाओं में 72 लोगों की मौत और कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में भी 111 लोगों की जान चली गई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को कर्नाटक के बाढ़ प्रभावित बेलगावी जिले और महाराष्ट्र के सांगली और कोल्हापुर जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि शाह चेन्नई से एक विशेष विमान से बेलगावी में सांब्रा हवाई अड्डे पहुंचे और सेना के एक हेलिकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित कुछ इलाकों का सर्वेक्षण किया।

कर्नाटक में सभी नदियां उफान पर हैं। बेल्लरी जिले में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर हंपी रविवार की सुबह एक जलाशय से 1.70 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद डूब गया। अधिकारियों के अनुसार हंपी से पर्यटकों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। कर्नाटक में अप्रत्याशित बाढ़ के चलते पिछले हफ्ते से अब तक 31 लोगों की जान चली गयी और 17 जिलों के 80 तालुकों में चार लाख लोग विस्थापित हो गए।

केरल में 2.27 लाख से अधिक लोगों ने 1,551 राहत शिविरों में शरण ली है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने रविवार को अधिकारियों के साथ मिलकर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की और बाद में संवाददाताओं से कहा कि आठ अगस्त से वर्षाजनित घटनाओं में मरने वालों की संख्या 72 हो गई है। कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को उड़ान परिचालन बहाल हो गया। रनवे पर पानी भर जाने के कारण हवाई अड्डा दो दिनों से बंद था।

भारतीय मौसम विभाग ने भारी वर्षा अनुमान के मद्देनजर कन्नूर, कसारगोड और वायनाड के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। रविवार सुबह आठ बजे तक कोझिकोड के वडकारा में सर्वाधिक 21 सेंटीमीटर वर्षा हुई। त्रिशूर के कोडंगल्लूर में में 19.9 सेंटीमीटर और मलप्पुरम के पेरिंथलमन्ना में 13.8 सेंटीमीटर बारिश हुई। विजयन ने कहा कि बड़े बांधों में जलस्तर अब चिंता का विषय नहीं है। सबसे अधिक प्रभावित वायनाड में गुरुवार को बड़ा भूस्खलन हुआ था और आठ व्यक्ति अब भी लापता हैं। उनकी तलाश जारी है।

विभिन्न स्थानों पर सेना, नौसेना, तटरक्षक बल, एनडीआरएफ, पुलिस, स्वयंसेवक और मछुआरे बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। दक्षिण रेलवे ने रविवार को मेंगलुरु–तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस, मवेली एक्सप्रेस, मालाबार एक्सप्रेस, कन्नौर–एर्नाकुलम इंटरसिटी एक्सप्रेस और एर्नाकुलम बंगलुरु इंटरसिटी एक्सप्रेस समेत 10 ट्रेनें रद्द कर दीं।

रेलवे ने कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल में राहत सामग्रियों की ढुलाई पर किराया माफ करने की घोषणा की है। इन राज्यों में दस लाख से अधिक लोगों को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए उनके घरों से अन्यत्र ले जाना पड़ा। पश्चिमी महाराष्ट्र के पांच जिलों में एक हफ्ते में वर्षा जनित घटनाओं में करीब 35 लोगों की मौत हो गई। उनमें वे 17 लोग भी हैं जो गुरुवार को सांगली में ब्रह्मनाल गांव के समीप नौका के पलटने से डूबकर मर गए थे।

महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से अबतक चार लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उनके अनुसार 69 तहसील में 761 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। गुजरात के कई हिस्सों में अब भी भारी वर्षा का दौर जारी है जिससे वर्षा जनित घटनाओं में मरने वालों की संख्या 31 हो गआ है।

उनमें सौराष्ट्र में शनिवार से जान गंवाने वाले 12 लोग भी शामिल हैं। गुजरात के मध्य भाग, सौराष्ट्र व कच्छ क्षेत्रों के कई हिस्सों में पिछले तीन दिनों से जबर्दस्त वर्षा हो रही है।

नेशनल कांफ्रेंस के गिरफ्तार नेता सागर को यूपी स्थानांतरित किया गया

श्रीनगर, 11 अगस्त (भाषा)।

जम्मू कश्मीर में कुछ दिन पहले गिरफ्तार नेशनल कांफ्रेंस के नेता और पूर्व मंत्री अली मोहम्मद सागर को रविवार को उत्तर प्रदेश की एक जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

कैदियों को जम्मू कश्मीर से बाहर की जेलों में भेजने की केंद्र सरकार की योजना के तहत सागर राज्य से भेजे गए मुख्य धारा के पहले नेता हैं। एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें बरेली की जेल में स्थानांतरित किया गया है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर से अब तक 46 बंदियों को अन्य राज्यों में स्थानांतरित किया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने समस्या पैदा करने के संदेह में शुक्रवार को 20 बंदियों को श्रीनगर से आगरा पहुंचा दिया था जबकि गुरुवार को 25 ऐसे लोगों को दूसरी जगह ले जाया गया था। सरकार के जरिए किए गए संवैधानिक बदलावों के मद्देनजर एहतियात के तौर यह कदम उठाया गया था। सागर को पांच अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के साथ गिरफ्तार किया गया था।

सीएपीएफ अधिकारियों ने शाह को लिखा पत्र, भेदभाव खत्म करने की मांग

नई दिल्ली, 11 अगस्त (भाषा)।

सीएपीएफ के कई अधिकारियों ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और अपने सेवा लाभों को प्राप्त करने में आइपीएस अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कथित भेदभाव को खत्म करने के लिए उनसे हस्तक्षेप करने की मांग की है।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के अधिकारियों ने एक सोशल मीडिया अभियान शुरू कर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया आदेश और केंद्रीय कैबिनेट से इसे मंजूरी मिलने के बावजूद उनका मुख्यालय उन्हें संगठित सेवा लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया में बाधा डाल रहा है। साथ ही, भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) अधिकारियों की संख्या घटा कर निगरानी स्तर पर अधिक पदों को आवंटित करने में भी अवरोध पैदा किया जा रहा है। शाह को भेजे पत्रों में सीएपीएफ अधिकारियों ने वांछित कार्रवाई के लिए उनसे हस्तक्षेप करने की मांग की है, ताकि उनके भर्ती नियम में संशोधन हो और एक संगठित केंद्रीय सेवा के लिए वैधता की तर्ज पर एक नयी कैडर समीक्षा हो।

नए भर्ती नियमों को बनाए जाने से इन अधिकारियों को निगरानी रैंक में अधिक पद प्राप्त होंगे, जिसे अभी मुख्य रूप से आइपीएस अधिकारी देखते हैं।सीआरपीएफ कैडर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'अधिकारियों ने मंत्री से अनुरोध किया है कि हाल ही में घोषित उनके वाजिब सेवा लाभ उसी तरह से सुनिश्चित किया जाए, जिस तरह से अनुच्छेद 370 पर एक साहसिक फैसले की घोषणा का क्रियान्वयन किया गया।'

उन्होंने कहा कि अधिकारी शाह को सीधे पत्र लिख रहे हैं क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बावजूद इन बलों के मुख्यालय उन्हें पूर्ण लाभ प्रदान करने वाली कार्यवाही को या तो धीमी गति से कर रहे हैं या उन्हें पूरा करने को अनिच्छुक हैं। दरअसल, यह प्रतिनियुक्ति पर इन बलों में शामिल होने वाले आईपीएस अधिकारियों की करियर संभावनाओं को प्रभावित करेगा।

वहीं, सीएपीएफ में कैडर अधिकारियों के लिए इन कार्यवाहियों को देख रहे एक वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी ने उनकी दलीलों का खंडन करते हुए कहा कि भर्ती नियमों की समीक्षा फौरन नहीं की जा सकती क्योंकि कुछ स्पष्टीकरण अपीलें सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। उन्होंने कहा, 'आइपीएस एक केंद्रीय सेवा है और उसका एक अखिल भारतीय सेवा स्वरूप है। इसे केंद्रीय सेवाओं में उनकी कैडर क्षमता के मुताबिक पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिए जाने की जरूरत है।'

कांग्रेस ने केंद्र पर बाढ़ सहायता में भेदभाव का लगाया आरोप

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

कांग्रेस ने रविवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्यों को बाढ़ सहायता देने में भेदभाव कर रही है।

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने दावा किया कि केंद्र ने केरल को 3,000 करोड़ रुपए की बाढ़ सहायता दी है जबकि वहां पिछले वर्ष बाढ़ से 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने में भी भाजपा भेदभाव की राजनीति कर रही है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई बाढ़ नहीं आई थी, फिर भी उसे पिछले वर्ष 200 करोड़ रुपए की सहायता दी गई जबकि साल–दर–साल बाढ़ की मार झेलने वाले असम को महज 250 करोड़ रुपए की सहायता मिली। उन्होंने दावा किया कि पूर्वोत्तर राज्य ने 3,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की सहायता राशि मांगी थी।

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I, Aarti Tandan W/o Vishal Bhakhri R/o JU-1D Pitampura Delhi-110034. have changed my name to Aarti Bhakhri for all purposes. 0040507414-7

I, NAVIN S/o Bhola Datt R/o AF-16C Shalimar Bagh Delhi-110088,have changed my name to NAVIN KHULBE for all purposes. 0040507414-8

I, Krishan Kumar Mahto S/o Sehdev Mahto R/o.H.No.170,Peer Mohalla, Aali Village, Sarita Vihar, N.Delhi-110076, have changed my,Daughter's name From Soni to Sony Kumari permanently. 40507467

वर्गीकृत

Change of Name

I, Deepak Kumar S/O Motilal born on 22.08.1988 residing at SA-12 Sanjeeva Town Kochpukur 700156, have changed my name to Deepak Motilal Kumar vide affidavit dated 7.8.2019 sworn before notary S. Chaudhuri Bidhannagar court. 50153238

PUBLIC NOTICE

I, JC-698431X Sub Shravan Kumar Mishra Son of Shri Rajbahor Mishra R/o Vill Khaira PO Bichharahta Teh Hanumana Distt Rewa, MP, declares that the name of my wife in my service record is Gita Devi as per No. 1, TT Bn Prt-II Order No. 243/90 and date of birth as per service record is 01.07.1973 which is incorrect. The Correct Name is Geeta Mishra and Date of birth is 01.01.1973 as per the Adhar Card & other records which are to be corrected in my service record.

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

फार्म नं. आईएनसी–26

(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 के कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले
और
प्रिंस डेनिम्स लिमिटेड
(CIN: U74999DL2005PLC143550)
जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं. **94, पॉकेट नं.13, सेक्टर–24, रोहिणी, नई दिल्ली–110085** में है, के मामले में
....**आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता**
एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, जो विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेतु **22 जुलाई, 2019** को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय को **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"राजस्थान राज्य"** में बदलने हेतु पारित किया गया।
यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो, तो वे इसका कारण देते हुए आपत्ति शपथपत्र में उल्लेख करते हुए जिसमें उनके हित/विरोध के आधार हों, एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निदेशक शिकायत फार्म दर्ज करें या क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कम्प्लैक्स, नई दिल्ली –110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय **94, पॉकेट नं. 13, सेक्टर–24, रोहिणी, नई दिल्ली–110085** पर इस सूचना के प्रकाशन के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।
कृते **प्रिंस डेनिम्स लिमिटेड**
दिनांक: 10 अगस्त 2019 राम बाबू बंदोला (निदेशक)
स्थान: नई दिल्ली डीआईएन: 03247409

UPVAN BUILDERS LIMITED
CIN No.: U45201DL1989PLC037107
Regd. Off: F-67, Dilshad Colony, East Delhi, Delhi 110095 (India)
Contact No: +91 9810320500
Email: vkjain@upvantech.com

प्रारूप संख्या आईएनसी– 26
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिये समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
केन्द्रीय सरकार के समक्ष प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र
कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (a) के मामले में
और
उपवन बिल्डर्स लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय- **F-67, दिलशाद कॉलोनी, ईस्ट दिल्ली, दिल्ली- 110095 इंडिया स्थित हैं, मे मामले में,**
याचिका करता आम जनता को यह नोटिस दी जाती है कि केंद्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.)" से "हरियाणा राज्य" में स्थानांतरित करने के लिये बुधवार, तारीख अगस्त 10, 2019 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष संकल्प के सन्दर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रारूप फाइल कर MCA-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी–2 विंग, दूसरा फ्लोर, पं. दीन दयाल अन्तोदया भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते हैं या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजेंगे:
"F-67, दिलशाद कॉलोनी, ईस्ट दिल्ली, दिल्ली–110095 इंडिया"
कृते एवं हित
उपवन बिल्डर्स लिमिटेड
हस्ता./–
दिनांक: 12 अगस्त, 2019 वीरेन्दर कुमार जैन
स्थान: नई दिल्ली निदेशक
DIN: 03197073

VAT D1 Form Lost

This is to inform that the VAT D1 No. 235 of Rs 2,23,34,577 for FY 2015-16 (Invoice Dt 31.03.2016) From issued by M/s Exide Industries Limited in the name of M/s Hindustan Zinc Limited have been misplaced and not traceable. If found, inform to Hindustan Zinc Limited, Core-6, 1st Floor, Scope Office Complex, 7 Lodhi Road, New Delhi-110 003.

फार्म नं. आईएनसी–26

(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 के कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले
और
श्री बालाजी आरसी कोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
(CIN:U24100DL2012PTC237800)
जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं. **पार्ट डी–48, गली नं.9, चन्दर लोक कॉलोनी, मंडोली, दिल्ली–110093** में है, के मामले में
....**आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता**
एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, जो विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेतु **15 जुलाई, 2019** को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय को **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** में बदलने हेतु पारित किया गया।
यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो, तो वे इसका कारण देते हुए आपत्ति शपथपत्र में उल्लेख करते हुए जिसमें उनके हित/विरोध के आधार हों, एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निदेशक शिकायत फार्म दर्ज करें या क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली –110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय **पार्ट डी–48, गली नं.9, चन्दर लोक कॉलोनी, मंडोली, दिल्ली–110093** पर इस सूचना के प्रकाशन के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।
कृते **श्री बालाजी आरसी कोटर्स प्राइवेट लिमिटेड**
दिनांक: 10 अगस्त 2019 सुशांत पांडेय (निदेशक)
स्थान: दिल्ली डीआईएन: 07550223

फार्म नं. आईएनसी–26

(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 के कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले
और
शिखर प्रोजेक्ट्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U67120DL1995PTC241843)
जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं. **पार्ट डी–48, गली नं.9, चन्दर लोक कॉलोनी, मंडोली, दिल्ली–110093** में है, के मामले में
....**आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता**
एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, जो विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेतु **05 अगस्त, 2019** को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय को **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** में बदलने हेतु प्रस्ताव किया गया।
यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो, तो वे इसका कारण देते हुए आपत्ति शपथपत्र में उल्लेख करते हुए जिसमें उनके हित/विरोध के आधार हों, एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निदेशक शिकायत फार्म दर्ज करें या क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली –110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय **पार्ट डी–48, गली नं.9, चन्दर लोक कॉलोनी, मंडोली, दिल्ली–110093** पर इस सूचना के प्रकाशन के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।
कृते **शिखर प्रोजेक्ट्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड**
दिनांक: 10 अगस्त 2019 सुशांत पांडेय (निदेशक)
स्थान: दिल्ली डीआईएन: 07550223

रजनीकांत ने कश्मीर पर उठाए गए कदम के लिए की शाह की तारीफ

चेन्नई, 11 अगस्त (भाषा)।

मशहूर फिल्म अभिनेता रजनीकांत ने जम्मू–कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की रविवार को प्रशंसा की और नरेंद्र मोदी–शाह की जोड़ी को कृष्ण और अर्जुन जैसा बताया।

रजनीकांत ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पर एक किताब के विमोचन के मौके पर यहां कहा, 'मिशन कश्मीर के लिए अमित शाह को मेरी ओर से हार्दिक बधाई।' उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह भगवान कृष्ण और अर्जुन की तरह हैं।

संजीव चतुर्वेदी को मुआवजे का भुगतान किया

नई दिल्ली, 11 अगस्त (भाषा)।

केंद्र ने उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा अगस्त 2018 में जारी आदेश का अनुपालन करते हुए आइएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को 25 हजार रुपए मुआवजे का भुगतान कर दिया है। अदालत ने इस वर्ष जून में अवमानना नोटिस जारी किया था।

चतुर्वेदी ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के समक्ष एक मामला दायर किया था। चतुर्वेदी ने कैट में यह मामला 2015–16 में एम्स, नई दिल्ली द्वारा उनके मूल्यांकन रिपोर्ट में प्रतिकूल प्रविष्टि करने को लेकर दायर किया था, जहां उन्होंने 2012 से 2016 तक मुख्य सतर्कता अधिकारी के तौर पर कार्य किया। कैट ने मामले की सुनवाई जुलाई 2017 से करनी शुरू की थी। कैट अध्यक्ष ने दिल्ली स्थित कैट की प्रधान पीठ में चतुर्वेदी द्वारा दायर कार्यवाही पर रोक लगा दी थी, जो कि नैनीताल में कैट की एक खंडपीठ के समक्ष लंबित थी। जब चतुर्वेदी ने मूल्यांकन रिपोर्ट को चुनौती देते हुए नैनीताल पीठ के समक्ष एक अर्जी दायर की तो उनके पक्ष में एक अंतरिम आदेश पारित किया गया। उसके बाद केंद्र कैट की प्रधान पीठ के पास पहुंचा था और उससे मामले को नैनीताल से दिल्ली हस्तांतरित करने को कहा था।

कैट अध्यक्ष ने नैनीताल में दो सदस्यीय पीठ के समक्ष लंबित कार्यवाही पर छह सप्ताह के लिये रोक लगा दी थी। कैट ने इसके साथ ही चतुर्वेदी को एक नोटिस जारी किया था। भारतीय वन सेवा (आइएफएस) अधिकारी ने कैट अध्यक्ष के आदेश को गत वर्ष उत्तराखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी। अदालत ने कैट अध्यक्ष के आदेश को रद्द कर करते हुए कहा था कि केंद्र और एम्स का रुख अधिकारी के खिलाफ प्रतिशोधी था।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालय : एम–2, प्रथम तल, साउथ एक्सटेंशन, पार्ट–2, नई दिल्ली–49
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट–IV (नियम 8 (1) देखें)

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, साउथ एक्सटेंशन पार्ट–2, नई दिल्ली शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना, दिनांक **07/02/2019** जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदार: मैसर्स एस.ए. ट्रेडर्स, मालिक– मोहम्मद शादाब अंसारी एवं गारंटर – श्रीमती हमीदा बेगम,** को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.39,51,157/– (उनतालिस लाख इक्यावन हजार एक सौ सत्तावन रूपये मात्र) 07.02.2019 को, भावी ब्याज एवं आकस्मिक शुल्क के साथ,** 07.02.2019 से प्रभावी उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। **कर

मौसम

तापमान	नई दिल्ली
अधिकतम–37.0 डि.से.	सूर्योदय– 5:49
न्यूनतम– 27.2 डि.से.	सूर्यास्त– 19:05

सजावट स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगे के रंग में रंगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन।

जेटली की हालत स्थिर

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली,11 अगस्त।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की स्थिति लगातार स्थिर बनी हुई है। अस्पताल से जुड़े सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। यहां नेफ्रोलाजी, प्लमोनरी मेडिसिन, एंडोक्राइन व कार्डियोलॉजी के विशेषज्ञ डॉक्टरों का दल इनका इलाज व निगरानी कर रहा है। उपराष्ट्रपति वैंकेया नायडू सहित कई नेता जेटली का हालचाल जानने के लिए एम्स पहुंचे थे। जेटली को सांस लेने में तकलीफ और बेचैनी की शिकायत के बाद शुक्रवार सुबह एम्स के सघन निगरानी कक्ष (आइसीयू) में भर्ती कराया गया था। अस्पताल ने बताया कि उनकी हालत अब स्थिर बनी हुई है।

सूत्रों के मुताबिक, उनके सभी अहम अंग उम्मीद के मुताबिक काम कर रहे हैं। हालांकि अस्पताल ने जेटली के स्वास्थ्य का कोई नया बुलेटिन न तो शनिवार को और न ही रविवार को जारी किया है। जेटली लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। उनका वजन कम करने के लिए एक निजी अस्पताल में पहले बेरियाट्रिक सर्जरी की गई थी। मधुमेह से पीड़ित जेटली का एम्स में गुर्दे का प्रत्यारोपण भी किया गया था।

छात्राओं को सम्मानित करेंगे एबीवीपी और डूसू

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) विभिन्न रचनात्मक क्षेत्रों व पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को 13 अगस्त को उत्तरी परिसर में 'स्वयंसिद्धा' कार्यक्रम में सम्मानित करेगा। साथ ही इस कार्यक्रम में फेस पेंटिंग, एकल नृत्स, समूह नृत्य, रंगोली बनाना, गायन और फैशन शो जैसी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। कार्यक्रम में प्रतियोगिताओं में विजेताओं के लिए कुल 62500 धनराशि पुरस्कार राशि के रूप में दी जाएगी।

'स्वयंसिद्धा' कार्यक्रम की आयोजन समिति की संयोजिका महामेधा नागर ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्राएं ऑनलाइन या मोबाइल के माध्यम से पंजीकरण करा सकती हैं।

'क्या ट्रैफिक पुलिस को ड्यूटी पर पेयजल और शौचालय सुविधा मिलती है'

नई दिल्ली, 11 अगस्त (भाषा)।

हाई कोर्ट ने पुलिस से पूछा

दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस आयुक्त से पूछा है कि क्या ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को कार्य स्थल पर पेयजल, शौचालय और चिकित्सा जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर के पीठ ने कहा कि ये न्यूनतम सुविधाएं हैं जिनकी मांग जनहित याचिका के माध्यम से ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के लिए की गई है।

पीठ ने पुलिस आयुक्त को मामले में हलफनामा दाखिल कर अदालत की ओर से पूछे सवालों का जवाब 27 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई से पहले देने को कहा। पीठ का यह निर्देश पुलिस की ओर से मामले में दाखिल हलफनामे के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि वह ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को पानी का बड़ा और छोटा जग उपलब्ध करवाती है। अदालत एनजीओ लीगल फोरम फॉर वुमेन की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों को पेयजल, शौचालय और चिकित्सा सुविधा देने की मांग की गई है।

दिल्ली पुलिस
शांति सेवा न्याय

सार्वजनिक सूचना

मानव रहित हवाई वाहनों की उड़ान पर प्रतिबंध

- मानव रहित हवाई वाहनों (यू ए वी) / मानव रहित विमान प्रणाली (यू ए एस), पैरा ग्लाइडर्स, पैरा मोटर्स, हैंग–ग्लाइडर्स, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट्स, रिमोट कन्ट्रोल संचालित एयरक्राफ्ट्स, गर्म हवा वाले गुब्बारे, छोटे आकार के इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट्स, क्वाडकॉप्टर्स **15.08.2019 तक** उड़ाना सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंधित हैं। इस संदर्भ में विशेष रूप से निषेध आदेश जारी किया गया है।
- **इस आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति आपराधिक अभियोग के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।**

आम जनता, दुकानदार, स्टॉकिस्ट, शौकीन एवं पेशेवर इत्यादि सभी से निवेदन किया जाता है कि निषेध आदेश का पालन करें।

DP/9135/19

तुरंत पुलिस सहायता के लिए कॉल करें 100 | पुलिस को सूचना देने के लिए कॉल करें 1090

दिल्ली पुलिस
शांति सेवा न्याय

स्वतंत्रता दिवस समारोह
यातायात निर्देशिका

13 अगस्त 2019 को फुल ड्रेस रिहर्सल

लाल किले के आसपास यातायात प्रतिबंध

निम्नलिखित सड़कें 04:00 बजे से 10:00 बजे तक सामान्य यातायात के लिए बंद रहेंगी और केवल लेबल लगे वाहनों को ही प्रवेश दिया जाएगा:

- दिल्ली गेट से छत्ता रेल तक नेताजी सुभाष मार्ग
- जीपीओ दिल्ली से छत्ता रेल तक लोथियान रोड
- एच.सी. सेन मार्ग से यमुना बाजार चौक तक एस.पी. मुखर्जी मार्ग
- फाउंटेन चौक से लाल किले तक चांदनी चौक रोड
- रिंग रोड से नेताजी सुभाष मार्ग तक निषाद राज मार्ग
- एसप्लंडे रोड और इसके लिंक रोड से नेताजी सुभाष मार्ग
- राजघाट से वाई–प्वाइंट–हनुमान सेतु तक रिंग रोड

04:00 बजे से 10:00 बजे तक निम्नलिखित सड़कों पर जाने से बचें

ऐसे वाहन जिन पर रिहर्सल के लिए पार्किंग लेबल नहीं है, वे तिलक मार्ग, मथुरा रोड, बी.एस.जेड मार्ग, सुभाष मार्ग, जे.एल. नेहरू मार्ग और निजामुद्दीन पुल एवं आई.एस.बी.टी ब्रिज के बीच रिंग रोड पर जाने से बचें और सुझाए गये मार्ग पर जाएं।

उत्तर–दक्षिण पहुंच

विकल्प–1 : अरबिन्दो मार्ग–सफदरजंग रोड–मदर टैरेसा क्रीसेंट–पार्क स्ट्रीट–मंदिर मार्ग–पंचकुईयां रोड–रानी झांसी फ्लाईओवर होते हुए उत्तर दिल्ली में अपने गंतव्य तक आवागमन।

विकल्प–2 : कनॉट प्लेस–मिन्टो रोड–भवभूति मार्ग–अजमेरी गेट–श्रद्धानंद मार्ग–लाहौरी गेट चौक–नया बाजार–पीली कोठी–एस.पी. मुखर्जी मार्ग होते हुए उत्तर दिल्ली में अपने गंतव्य तक आवागमन।

विकल्प–3 : रिंग रोड आईएसबीटी (कश्मीरी गेट)–शालीमार बाग बाईपास रोड (अपर रिंग रोड)–आईपी एस्टेट फ्लाईओवर और इसके विपरीत आवागमन।

विकल्प–4: निजामुद्दीन पुल से यमुना पार–पुस्ता रोड–जी.टी. रोड और आई.एस.बी.टी पार करते हुए उत्तर दिल्ली में अपने गंतव्य तक आवागमन ।

पूर्व पश्चिम कॉरीडोर:

रिंग रोड पहुंचने के लिए डी.एन.डी–एनएच24–विकास मार्ग–शाहदरा ब्रिज एवं वजीराबाद ब्रिज खुला रहेगा।

विकास मार्ग–डीडीयू मार्ग–भवभूति मार्ग–डी.बी.जी रोड–बुलवर्ड रोड–रानी झांसी फ्लाईओवर–डी बी जी रोड–पंचकुईयां रोड खुले रहेंगे।

04:00 बजे से 10:00 बजे तक शांतिवन की ओर गीता कॉलोनी ब्रिज बंद रहेगा।

इसी तरह आई.एस.बी.टी कश्मीरी गेट से शांतिवन की तरफ और आईपी फ्लाईओवर से राजघाट की तरफ लोअर रिंग रोड पर ट्रैफिक की अनुमति नहीं होगी।

लोगों को सलाह दी जाती है कि अंतिम वक्त में भीड़भाड़ एवं असुविधा से बचने के लिए उचित समय पर पहुंचे।

साइनेज

सभी महत्वपूर्ण चौराहों पर लाल किले के लिए जाने वाले वाहनों के मार्गदर्शन के लिए पर्याप्त जानकारी के लिए साइनेज प्रदर्शित किये जाएंगे।

वाणिज्यिक वाहनों एवं अंतर्राज्जीय बसों के आवाजाही पर प्रतिबंध

1. 00:00 बजे अर्धरात्रि से **13.08.2019 को 1100 बजे तक** निजामुद्दीन पुल एवं वजीराबाद पुल के बीच सामान ढोने वाले वाहनों को चलने की अनुमति नहीं होगी।
2. 00:00 बजे अर्धरात्रि से **13.08.2019 को 11:00 बजे तक** महाराणा प्रताप आई.एस.बी.टी और सराय काले खां आई.एस.बी.टी के बीच अंतर्राज्जीय बसों को चलने की अनुमति नहीं होगी।

प्रतिबंधित सड़कों के अलावा शहरी बसों की आवाजाही पर प्रतिबंध

डीटीसी सहित स्थानीय बसें 0000 बजे अर्धरात्रि से **13.08.2019 को 11:00 बजे तक** रिंग रोड पर आई.एस.बी.टी से एनएच–24/एनएच 'टी' प्वाइंट (निजामुद्दीन खत्ता) के बीच नहीं चलेंगी और उपलब्ध वैकल्पिक मार्ग से चलेंगी।

लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली मेन रेलवे स्टेशन पर सामान्यतया समाप्त होने वाली बसें नियमनुसार रोक/मार्ग परिवर्तित कर दी जाएंगी:

1) दक्षिण और पश्चिम दिल्ली से आने जाने वाली बसों के लिए जे.एल. एन मार्ग पर रामलीला ग्राउंड के सामने तक। पैदल यात्री नुक्कड फैज बाजार और सुभाष मार्ग के रास्ते लाल किले तक जाएं।
2) आई.एस.बी.टी पुल के रास्ते उत्तर, उत्तर पश्चिम एवं पूर्वी दिल्ली से आने जाने वाली बसें के लिए मोरी गेट और तीस हजारी तक। पैदल यात्री पुल डफ्फरिन और एस.पी. मुखर्जी मार्ग के रास्ते लाल किले तक जाएं।
3) रिंग रोड की ओर से उत्तर दिल्ली से आने वाली बसों के लिए महाराजा अग्रसेन पार्क के सामने बुलवर्ड रोड पर । पैदल यात्री लोथियान रोड–छत्ता रेल– एन एस मार्ग होते हुए लाल किले तक जाएं।

सामान्य बस सेवा 11:00 बजे से बाद पूर्ववत की जाएगी।

महत्वपूर्ण स्थानों पर कैसे पहुंचे:

1) **पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन**
क) **पश्चिम से दक्षिण दिल्ली:** मदर टेरेसा क्रीसेंट–पार्क स्ट्रीट–मंदिर मार्ग–पंचकुईयां रोड–रानी झांसी मार्ग–आजाद मार्केट–बुलवर्ड रोड–मोरी गेट–पुल डफ्फरिन–एस पी मुखर्जी मार्ग होते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचे।
ख) **उत्तरी दिल्ली से:** मोरी गेट–पुल डफ्फरिन–एस पी मुखर्जी मार्ग होते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचे।
2) **नई दिल्ली रेलवे स्टेशन :** यहां कोई प्रतिबंध नही है।
3. **आई.एस.बी.टी कश्मीरी गेट**
क) नई दिल्ली से दक्षिण दिल्ली: मदर टेरेसा क्रीसेंट–पार्क स्ट्रीट–मंदिर मार्ग–पंचकुईयां रोड–रानी झांसी फ्लाईओवर–बुलवर्ड रोड
ख) उत्तरी दिल्ली से: यहां कोई प्रतिबंध नही है।
4) **जे पी एन अस्पताल:** यहां कोई प्रतिबंध नही है।
5) **कस्तूरबा अस्पताल:** अजमेरी गेट–अजमेरी बाजार–चौक हौज काजी–चावड़ी बाजार–चौक बडशाबुल्ला–उर्दू बाजार

DP/9138/19

पुलिस आयुक्त, दिल्ली को ई–मेल करें cp.amulyapatnaik@delhipolice.gov.in | लिखें : पुलिस आयुक्त, दिल्ली को पोस्ट बॉक्स नं. 171, जीपीओ, नई दिल्ली पर

ट्रैफिक प्रहरी बनें। ऐप डाउनलोड करें App Store Google Play 24 घंटे यातायात हेल्पलाईन: 1095, 011–25844444 (तुरंत पुलिस सहायता के लिए 100 नम्बर पर कॉल करें)

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	36.2 डि.से.	36.2 डि.से.	34.9 डि.से.	35.8 डि.से.
न्यूनतम	27.6 डि.से.	27.6 डि.से.	27.6 डि.से.	27.6 डि.से.

डीयू : स्नातक प्रबंधन पाठ्यक्रमों के दाखिले अटके

विश्वविद्यालय प्रशासन प्रवेश की दूसरी सूची जारी नहीं कर पाया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के स्नातक प्रबंधन पाठ्यक्रमों के दाखिले अटक गए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन इन पाठ्यक्रमों में दाखिले की दूसरी सूची तक जारी नहीं कर पाया है। पहली सूची 5 अगस्त को जारी की गई थी। डीयू की ओर से जारी बीएमएस, बीबीए (एफआइए) और बीए (ऑनर्स) बिजनेस अर्थशास्त्र में दाखिले के लिए परिवर्तित कार्यक्रम के मुताबिक 9 अगस्त को दूसरी सूची जारी की जानी थी लेकिन 11 अगस्त की देर रात तक सूची जारी नहीं की गई।

डीयू के दाखिला पोर्टल पर जारी सूचना के मुताबिक बीएमएस, बीबीए (एफआइए) और बीए (ऑनर्स) बिजनेस अर्थशास्त्र पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए जारी होने वाली दूसरी सूची में विलंब होगा। सूचना के मुताबिक दूसरी सूची 10 अगस्त शाम तक जारी होनी थी लेकिन पोर्टल पर इस तरह की कोई सूची उपलब्ध नहीं है। गौरतलब है कि डीयू प्रशासन इन तीनों पाठ्यक्रमों के दाखिलों को लगातार आगे बढ़ाता रहा है। एक बार तो योग्य विद्यार्थियों की सूची जारी करने के बाद वापस ले ली गई थी और फिर उसे बाद में संशोधन के बाद जारी किया गया। पहले 24 जुलाई को जारी सूचना के मुताबिक इन तीनों पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए पहली सूची 26 जुलाई को आनी थी लेकिन वह नहीं आई। इसके बाद नए दाखिले कार्यक्रम के लिए 28 जुलाई की तिथि तय की गई। एक अगस्त को पोर्टल पर फिर से सूचना आई कि दाखिलों के कार्यक्रम को एक बार फिर से टाल दिया गया है। इसके बाद 2 अगस्त को पहले जारी योग्यता सूची को हटा लिया गया। 3 अगस्त को फिर से नया दाखिला कार्यक्रम जारी किया गया जिसके मुताबिक पहली सूची 5 अगस्त को आनी थी। पहली सूची तय तिथि को जारी की गई और उसके आधार पर दाखिले भी हुए। दूसरी सूची 9 अगस्त को आनी थी लेकिन किन्हीं कारणों से फिर से दूसरी सूची को टाल दिया गया है। अब देखना है कि दूसरी सूची कब आएगी और स्नातक प्रबंधन पाठ्यक्रमों के दाखिले कब तक पूरे होंगे।

डीयू की ओर से जारी बीएमएस, बीबीए (एफआइए) और बीए (ऑनर्स) बिजनेस अर्थशास्त्र में दाखिले के लिए परिवर्तित कार्यक्रम के मुताबिक 9 अगस्त को दूसरी सूची जारी की जानी थी लेकिन 11 अगस्त की देर रात तक सूची जारी नहीं की गई

स्वतंत्रता दिवस पूर्वाभ्यास से बाधित रहेगा यातायात

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के मद्देनजर फुल ड्रेस रिहर्सल पर लाल किला और उसके आसपास यातायात बाधित रहेगा। लोगों को असुविधा से बचाने के लिए कुछ मार्गों में फेरबदल किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने समारोह स्थल लाल किला के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं।

मंगलवार 13 अगस्त को सुबह 4 से 10 बजे तक दिल्ली के कई इलाके में यातायात की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, जबकि लाल किला क्षेत्र में यातायात पूरी तरह प्रतिबंध रखा गया है। शांति वन के पास गीता कॉलोनी पुल से यातायात पूरी तरह बंद होगा। जिन गाड़ियों में अनुमति के स्टीकर लगे होंगे उन्हें आने-जाने की अनुमति दी जाएगी। दिल्ली यातायात पुलिस के संयुक्त आयुक्त मीनू चौधरी ने बताया कि व्यावसायिक ट्रांसपोर्ट और अंतरराज्यीय बसें जो निजामुद्दीन पुल और वजीराबाद पुल के बीच चलती हैं उसे रात 12 बजे से ही सुबह 11 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है।

तैयारी लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले तैयारी के दौरान अभ्यास करते स्कूली बच्चे।

रैपिड रेल स्टेशनों पर हादसों को रोकने के लिए लगेंगे दरवाजे

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

तेज रफ्तार चलने वाली रैपिड रेल गाड़ियों के स्टेशनों पर खुदकुशी और अन्य दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने रैपिड रेल ट्रांजिट कॉरिडोर के सभी स्टेशनों पर 'प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स' (पीडीएस) लगाने की योजना बनाई है।

रेल रैपिड ट्रांजिट प्रणाली (आरआरटीएस) की कार्यकारी एजंसी एनसीआरटीसी ने कहा कि इससे 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली रेलगाड़ी में यात्रियों के चढ़ने और उतरने के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित होगी साथ ही भीड़ प्रबंधन भी होगा। ट्रेन के आगे कूद कर खुदकुशी करने की घटनाओं के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने भी कई स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर लगाए हैं। एनसीआरटीसी तीन प्रस्तावित आरआरटीएस कॉरिडोर दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ- दिल्ली-गुरुग्राम-अलवर और दिल्ली-सोनीपत-पानीपत तीन लाइनों पर काम कर रहा है। एनसीआरटीसी के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुधीर शर्मा ने कहा कि हाल के दिनों में हमने दुर्घटनावश पटरियों पर यात्रियों के गिरने, पटरियों को अनधिकृत रूप से पार करने और खुदकुशी करने के मामले देखे हैं। इसलिए हर एक आरआरटीएस स्टेशनों पर पीडीएस लगाने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि पीडीएस प्लेटफॉर्म और पटरियों पर अवरोध की तरह काम करेंगे, जिससे स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन में भी मदद मिलेगी। पीडीएस लगाने से स्टेशन पर ट्रेन को तेज गति से आने और जाने में सुविधा होगी।

दहेज की मांग पूरी न होने पर दिया तीन तलाक

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

राजधानी में शनिवार को तीन तलाक देने का मामला सामने आया है। दहेज की मांग पूरी न होने पर गांधी नगर में एक युवक ने अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया। साथ ही अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता अपने परिवार को लेकर गांधी नगर थाने पहुंची। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर द मुसलिम वुमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज) एक्ट 2019 के तहत आरोपी पति आरिफ मलिक (22) के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शाहदरा की जिला पुलिस उपायुक्त मेघना यादव ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस के मुताबिक, गाजियाबाद के लोनी निवासी 20 साल की बबली की शादी दिसंबर 2014 में गांधी नगर में रहने वाले आरिफ मलिक से हुई थी। पीड़िता का आरोप है कि शादी से पहले आरिफ ने खुद को एमबीबीएस डॉक्टर बताया था। परिवार ने दहेज में अच्छा खास सामान देने के साथ ही पांच लाख रुपए नकद दिए थे। शादी के बाद बबली को पता चला कि आरिफ एक झोलाछाप डॉक्टर है लेकिन उस समय न तो बबली और न ही उसके परिजनों ने आरिफ को कुछ बोला। वहीं, आरिफ और उसका परिवार बबली के परिवार से और दहेज देने की मांग करने लगे। पिछले काफी वक्त से आरिफ बबली के परिजनों से एक कार देने की मांग कर रहा था। रोजाना दहेज की मांग से परेशान होकर आठ महीने पहले बबली अपने मायके में जाकर रहने लगी। शनिवार को आरिफ ने अपने ससुराल वालों को फोन करके बबली को वापस भेजने के लिए कहा। परिजन उसे गांधी नगर ले आए। यहां पहुंचते ही आरिफ ने दोबारा से कार की मांग कर दी।

पीड़िता ने जब पति से कहा कि उसकी यह मांग कभी पूरी नहीं होगी तो उसने कहा अगर ससुराल वाले मांग पूरी नहीं करते हैं तो वह बबली को तलाक दे देगा। आरिफ ने बबली को तीन तलाक देकर मायके वापस चले जाने के लिए कह दिया। परिजन बबली को लेकर तुरंत थाने गए और मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस का कहना है कि मामले में पूछताछ की जा रही है।

- पति ने खुद को बताया था एमबीबीएस डॉक्टर, पर था झोलाछाप
- आरोपी और उसका परिवार पीड़िता से लगातार दहेज देने की मांग करते थे

खबरों में शहर

दलित विमर्श के समापन पर पुस्तक का लोकार्पण

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, जनपथ में आयोजित दो दिवसीय दलित विमर्श पर 'सामाजिक राष्ट्रीयता: संदर्भ दलित' नामक संकलित पुस्तक का रविवार को लोकार्पण किया गया। केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने इसका लोकार्पण किया। इसका संपादन केंद्र सरकार के पूर्व राज्य मंत्री प्रो संजय पासवान ने किया है। इसमें 40 लेखों का संग्रह है जिसमें शोधार्थी, शिक्षार्थी और विद्यार्थी तीनों के विचार शामिल किए गए हैं। इससे पहले रविवार को 'नवाचार' और 'पत्रकारिता' विषय पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। रविवार को केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति के जय प्रसाद, जेएनयू के प्रो यगित चिन्ना राव, नागपुर विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त श्रीपाद भालचंद जोशी, आयकर विभाग के प्रधान आयुक्त एस कृष्णा, ज्ञानेश्वर मुले, वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव और दलित चिंतक पत्रकार एसएल दुसाध सहित अन्य लोगों ने अपने विचार रखे। वाराणसी के कबीर चौरा से आए ताना-बाना की टीम ने भी इस मौके पर अपनी प्रस्तुति दी। वक्ताओं ने दलित आंदोलन पर प्रकाश डालते हुए इसे वृहद रूप में उचित समय और प्लेटफार्म पर फैलाने की बात कही। उनका मानना था कि पुराने रटे-रटाए विचारों से अलग हटकर देश की मुख्यधारा को विषयों में शामिल करते हुए अपनी बातें सम्यक तरीके से रखीं जाएं। चुनौतियां सभी क्षेत्रों में हैं और इन चुनौतियों पर कैसे विजयी प्राप्त की जा सकती है इसके गुण-दोष पर भी चर्चा हुई।

550वें प्रकाशपर्व पर पौधारोपण का आयोजन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 अगस्त

सिखों के पहले गुरुनानक देव के 550वें प्रकाशपर्व के उपलक्ष्य में दिल्ली में एक नई हरित क्रांति की शुरुआत करने के लिए एक महा पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी राजधानी दिल्ली के लोगों को प्रकृति से जोड़ने, पर्यावरण को सुधारने, पानी और हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक मेगा पौधरोपण अभियान चलाएगी। कॉलेजों में छात्रों को प्रोजेक्ट रपट में पौधा तैयार करने की जिम्मेदारी व श्रद्धालुओं को प्रसाद में पौधे देंगे। दिल्ली के सभी ऐतिहासिक गुरुद्वारों और सिख संस्थाओं के परिसरों में चालू मानसून सीजन के दौरान नीम, बेर, जामुन जैसे एक लाख पौधे पर्यावरण प्रेमी लगाएंगे। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह जानकारी दी।

कनाडा दूतावास का अधिकारी बताकर ठगी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

उत्तम नगर थाना क्षेत्र में कनाडा दूतावास का अधिकारी बताकर एक शख्स से ठगी का मामला सामने आया है। शख्स से ठग ने 87,258 रुपए ठग लिए। कनाडा का वीजा बनवाने का झांसा देकर ठगी की गई है। पीड़ित सुनील कुमार शास्त्री की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है।

जानकारी के मुताबिक, सुनील कुमार शास्त्री परिवार के साथ श्याम पार्क, नवादा इलाके में रहते है। सुनील ने पुलिस को बताया कि 15 जुलाई को वह नौकरी के लिए जॉब.कॉम पर ऑनलाइन आवेदन भेज रहा था। इसके दो दिन बाद एक फोन आया कि आपका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। आपको एक लिंक में प्रश्न पत्र भेज रहे है। उनका उत्तर देकर भेज दें। सुनील ने प्रश्नों के उत्तर देकर भेज दिए। इसके बाद फोन आया कि आपका कनाडा की कंपनी में चुनाव हो गया है, आप वीजा के लिए आवेदन कर दो। इसके बाद एक और नंबर से फोन आया जिसमें अपने आप को कनाडा दूतावास का अधिकारी बताया गया। कहा गया कि आपके कनाडा वीजा की फीस के लिए 25 हजार रुपए खाते में जमा करवा दें। इसके दो दिन बाद 63285 रुपए मांगे गए। पीड़ित ने खाते में रुपए भेज दिए। इसके बाद यात्रा भत्ता के नाम पर तीन लाख रुपए की मांग की गई। इसके बाद वह उनके द्वारा बताए गए पते पर पहुंचा तो वहां कोई नहीं मिला। फिर इसकी शिकायत पुलिस को दी। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों के बारे में पता लगा रही है।

सीबीआइ अधिकारी के घर चोरी के आरोप में गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

गोविंदपुरी थाना क्षेत्र में एक सीबीआइ अधिकारी के घर बीते दिनों चोरी हो गई थी। घटना के समय अधिकारी ऋषिकेश राज अपनी पत्नी को बिहार में प्रशासनिक सेवा का परीक्षा दिलवाने ले गए थे। लौटे तो उन्हें घटना का पता चला था। दर्ज शिकायत के आधार पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से लाल कुआं निवासी शहजाद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध हालत में दिखने वाले युवक को गोविंदपुरी में गश्त कर रही पुलिस टीम ने दिखा। पुलिसकर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की, तो वह उन्हें देखकर भागने लगा। लेकिन तीनों पुलिसकर्मियों ने उसका पीछाकर धर दबोचा। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सीबीआइ अधिकारी के घर चोरी का अपराध कबूल कर लिया। इसके अलावा उसके खिलाफ लाल कुंआ इलाके में चोरी के करीब 16 और गोविंदपुरी इलाके में करीब सात मामले पहले से दर्ज थे।

'पूर्व की सरकारों ने अनधिकृत कॉलोनियों को नजरअंदाज किया'

नई दिल्ली, 11 अगस्त (भाषा)।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के गांवों और अनधिकृत कॉलोनियों की आवश्यकताओं को जानबूझकर नजरअंदाज करने के लिए पूर्व की सरकारों की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व की सरकारों ने केवल राजनीति की।

केजरीवाल ने मुंडका विधानसभा क्षेत्र में 1.65 करोड़ लीटर के भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन के शुभारंभ के मौके पर यह टिप्पणी की। इस बूस्टर पंपिंग स्टेशन के जरिए 14 गांवों और 27 अनधिकृत कॉलोनियों में पानी की आपूर्ति होगी। केजरीवाल ने कहा कि हमारी पार्टी महज सात-आठ साल पहले बनी थी।

हमने केवल चार साल में आपको पानी दिया, सड़क और नालियों का निर्माण कराया। क्या 70 साल में वे नहीं कर सकते थे? वे कर सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे याद है कांग्रेस और भाजपा अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने और विकास कार्यों का वादा करके वोट मांगती थी। लेकिन, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने बस राजनीति की और भ्रष्टाचार में डूबे रहे।

दिल्ली मेरी दिल्ली

चुनाव की घोषणा

लोकसभा चुनाव संपन्न होते ही अचानक आम आदमी पार्टी (आप) के नेता का बयान आया कि केंद्र सरकार हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र के साथ दिल्ली विधानसभा के चुनाव तय समय से कुछ महीने पहले करवाएगी। भाजपा के नेता सफाई देते रहे लेकिन दिल्ली की 'आप' सरकार पूरी तरफ चुनावी मोड में आकर दनादन घोषणाएं करने लगी। 'आप' के नेता अब केंद्र सरकार पर काम न करने देने का आरोप लगाने के बजाए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रियों से मिलकर दिल्ली के लिए योजनाएं पास करवाने में लग गए हैं। पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं को मेट्रो और दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बसों में मुफ्त यात्रा करवाने की घोषणा की। घोषणा पर अमल होने से पहले पिछले चुनाव के तर्ज पर दो सौ यूनिट हर महीने खपत करने वाले उपभोक्ता को फ्री बिजली देने की घोषणा कर दी। 'आप' पर चुनावी वायदों को पूरा न करने के आरोप लग रहे हैं इसलिए उसके बाद मुफ्त वाईफाई और सीसीटीवी लगवाने की घोषणा भी कर दी। लगता यही है कि मुख्यमंत्री अपनी ओर से चुनाव की घोषणा कर चुके हैं। शुक्रवार को भाजपा ने चुनाव होने वाले राज्यों के पदाधिकारियों की घोषणा की। इसके बाद फिर से 'आप' में सक्रियता बढ़ गई है।

अपनों के खिलाफ विरोध

अब तो यह सवाल गंभीरता से उठाया जाने लगा है कि क्या कांग्रेस के ही नेताओं ने अपनी पार्टी को खत्म करने की ठान ली है। कहा जा रहा है कि शीला दीक्षित को लोकसभा चुनाव लड़वाना और उनकी हार का जश्न मना कर पार्टी के बड़े नेताओं ने जता दिया कि वे शीला दीक्षित के खलिफ थे। शीला दीक्षित चाहती थीं कि लोकसभा चुनाव में वे पार्टी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करें और कुछ महीने बाद वे विधानसभा चुनाव लड़ सकें। उनके विरोधियों ने तरह-तरह के मूद्दे बनाकर उन्हें कमजोर किया। यह जगजाहिर था कि उनके ही विरोध के कारण कांग्रेस का 'आप' से चुनावी गठजोड़ नहीं हो पाया। लोकसभा चुनाव में 'आप' से बेहतर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया लेकिन कांग्रेस के नेता इस माहौल में भी एक दूसरे को निबटाने के अभियान में लगे हुए हैं।

कचौड़ी की 'रेट लिस्ट'

मंदिर, प्रसाद और कचौड़ी। यह तीनों एक ही जगह उपलब्ध हैं। दरअसल पिछले दिनों नेहरू प्लेस स्थित भैरों मंदिर में दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालु यहां प्रसाद वाली दुकानों की जगह कचौड़ी वाले व्यवसायी को देखकर चौंक गए। हुआ यूं कि हाल ही में यहां एक कचौड़ी वाले ने अपनी दुकान लगानी शुरू कर दी है। लोगों को लगा कि शायद भंडारे का आयोजन है। जब लोग वहां लाइन में लगे तो दुकानदार ने उन्हें रेट बता डाले। लाइन छोटी हो गई। सरकारी जमीन पर बैठे कचौड़ी वाले ने भी सुधार किया। अब वहां कचौड़ी की 'रेट-लिस्ट' टांग दी गई है। लोगों को अब समझने में देर नहीं लगती कि भंडारा नहीं यह दुकान है। हालांकि अभी यह समझने में देर है कि इस दुकान के पीछे किसकी दुकान चल रही है, कहीं मंदिर वाले बाबा की तो नहीं!

पुलिस की बेबसी

राजधानी में बदमाशों के हौंसले किस कदर बुलंद हैं। समय-समय पर इसका नजारा देखने को मिलते रहता है। बीते दिनों दक्षिण पूर्वी दिल्ली में भी एक ऐसा ही वाकया देखने को मिला, जब क्षेत्र का एक बीट कांस्टेबल शराब तस्करी की सूचना पर अपने इलाके में पहुंचा। उसने तस्करों के बारे में जानकारी मांगी तो कुछ महिलाएं उसके पीछे पड़ गईं। वर्दी में होने के बावजूद पुलिसकर्मी इतना बेबस नजर आ रहा था, मानों२ कोई साधारण व्यक्ति हो। एक महिला ने तो चप्पल निकाल ली और पुलिसकर्मी को चप्पल मारने की कोशिश करने लगी। पर समय रहते पुलिसकर्मी पीछे हट गया। बावजूद इसके महिलाएं और बदमाश के परिजन इतने बेखौफ थे कि वह पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी करते दिखे। पुलिसकर्मी को जब लगा कि वह लोगों के बीच फंस गया है और उसकी जान पर बन आई है तो उसने अपनी सर्विस पिस्तौल निकाली और हवा में एक गोली चलाई। बावजूद इसके जब लोग नहीं माने तो पुलिसकर्मी वहां से भाग खड़ा हुआ और अपनी जान बचाई। इसी प्रकार बीते दिनों दो पुलिसकर्मियों ने जब एक मोटरसाइकिल सवार युवकों को रोका तो वे उसके साथ गोली-गलोच करने लगे थे।

सबूतों के अभाव में

जांच के नाम पर सही को गलत और गलत को सही साबित करने के लिए बदनाम पुलिस को इस बार मुंह की खानी पड़ी है। कोर्ट में सरकारी वकील के स्तर से सही पैरवी के आभाव में रिश्वत लेते गिरफ्तार पुलिस इंस्पेक्टर को जमानत मिल गई है। इंस्पेक्टर के थाने में रंगे हाथ गिरफ्तार होने के बावजूद साक्ष्यों के अभाव में जमानत मिलना प्रशासनिक व्यवस्था को आइना दिखाने को काफी है। जमानत मिलने के बाद एसएसपी ने साफ तौर पर इसके लिए सरकारी वकील के रवैये को जिम्मेदार ठहराया है। जिसको लेकर गृह विभाग समेत शासन के उच्चाधिकारियों से बात करने को कहा है। मामला थाना सेक्टर-20 के एसएचओ रहे मनोज पंत को रिश्वत लेने के मामले में जमानत मिलना है। जिसको लेकर पूरे शहर में चर्चाएं हो रही हैं। बताया गया है कि पुलिस इंस्पेक्टर की रंगे हाथ गिरफ्तारी के चलते जमानत मिलना आसान नहीं था। लेकिन सरकारी वकील ने न्यायालय में साक्ष्य सही तरह से प्रस्तुत नहीं किए। जिसके चलते उसे जमानत और पुलिस-प्रशासन को मुंह की खानी पड़ी है।

-बेदिल

आज के कार्यक्रम

सभा/संगोष्ठी

इंडिया हैबीटाट सेंटर : विज्ञान, तकनीक और नवोन्मेष नीति पर चर्चा, केजुरीना हॉल, सेंटर परिसर, लोधी रोड, शाम सात बजे।

संगीत

इंडिया हैबीटाट सेंटर : पखावज पर एकल संगीत, द स्टेन ऑडिटोरियम, सेंटर परिसर, लोधी रोड, शाम सात बजे।

epaper.jansatta.com

कोल्हापुर में रविवार को बाढ़ प्रभावित इलाके में सहायता कार्य में जुटे नौसेना कर्मी को राखी बांधती महिला।

शून्यकाल में उठे मुद्दे कार्रवाई के लिए मंत्रालयों को भेजे जाएंगे : लोकसभाध्यक्ष

नई दिल्ली, 11 अगस्त (भाषा)।

संसद में शून्यकाल में उठाए गए मुद्दों पर सरकार से जवाब नहीं मिलने की शिकायतों के बीच लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि पहली बार लोकसभा में शून्यकाल में उठाए गए सभी विषयों को आगे की कार्रवाई और उत्तर के लिए संबंधित मंत्रालयों को भेजने की पहल शुरू की गई है। संसद के दोनों सदनों में विभिन्न दलों के सांसदों की लंबे समय से यह शिकायत रही है कि शून्यकाल और विशेष उल्लेख के तहत उनके द्वारा उठाए गए विषयों एवं मुद्दों पर उन्हें सरकार से जवाब नहीं मिलता।

राज्यसभा में हाल ही में सपा सांसद जया बच्चन ने मांग की थी कि हम यहां सिर्फ बोलते हैं और सरकार से जवाब नहीं मिलता है। ऐसे में समयबद्ध तरीके से जवाब मिलना चाहिए। इसका कई सदस्यों ने समर्थन किया था। लोकसभा में आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन भी इस विषय को उठा चुके हैं । प्रेमचंद्रन का कहना है कि शून्यकाल के दौरान कई सदस्य अपने क्षेत्र और जनता से जुड़े लोक महत्व के विषय को उठाते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि सरकार इन बिंदुओं पर संज्ञान ले और इन विषयों पर की गई कार्रवाई से उन्हें अवगत कराए। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। बसपा के दानिश अली का भी कहना है कि सरकार को शून्यकाल में सदस्यों द्वारा उठाए गए विषयों पर जवाब देना चाहिए।

इस बारे में पूछे जाने पर लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला ने बताया, 'हाल में संपन्न सत्र में लोकसभा में शून्यकाल में उठाए गए सभी विषयों को आगे की कार्रवाई और उत्तर के लिए संबंधित मत्रालयों को संदर्भित कर दिया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है।' उन्होंने कहा कि पहले शून्यकाल में उठाए गए विषयों को संदर्भित नहीं किया जाता था। अब ऐसी पहल की गई है। सदस्यों द्वारा उठाए गए कई विषय राज्यों से संबंधित होते हैं तो ऐसे विषय अलग होते हैं। राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी शून्यकाल में उठाए गए विषयों के बारे में शिकायतों पर हाल ही में कहा था कि मंत्रियों को शून्यकाल में उठाए विषयों पर 30 दिनों में जवाब देना चाहिए। गौरतलब है कि लोकसभा में कार्यवाही का पहला घंटा (11 से 12 बजे) प्रश्नकाल कहलाता है जबकि राज्यसभा में कार्यवाही के पहले घंटे को शून्यकाल कहते हैं।

बरसाती नदी के तेज बहाव में दो युवक बहे

देहरादून, 11 अगस्त (भाषा)।

देहरादून के एक निजी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले दो युवक रविवार को बारिश के चलते उफनाई एक बरसाती नदी के तेज बहाव में बह गए।

पुलिस ने बताया कि एक युवक का शव बरामद कर लिया गया है जबकि दूसरे युवक की तलाश की जा रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, युवक नदी में पिकनिक मनाने गए थे और अचानक उसका जलस्तर बढ़ जाने के कारण वे उसके तेज बहाव में बह गए। सूचना मिलने पर राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एसडीआरएफ) की टीम मौके पर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया।

उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश के चलते गंगा और यमुना सहित उफनाई नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और भूस्खलन और पहाड़ी से पत्थर गिरने की घटनाओं के कारण प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों सहित दर्जनों मोटर मार्ग यातायात के लिए अवरूद्ध हो गए।

पिथौरागढ़-तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पिथौरागढ़ में दोबाट के पास, ऋषिकेश-गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग टिहरी जिले में आगराखाल के पास, ऋषिकेश-केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग रूद्रप्रयाग जिले में बांसवाडा के पास मलबा आने के कारण यातायात के लिए अवरूद्ध है।

उपराष्ट्रपति नहीं बनना चाहते थे नायडू, नानाजी देशमुख के रास्ते पर चाहते थे जाना

चेन्नई, 11 अगस्त (भाषा)।

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रविवार को कहा कि वह कभी उपराष्ट्रपति नहीं बनना चाहते थे, बल्कि भारतीय जनसंघ के नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता दिवंगत नानाजी देशमुख के पदचिह्नों पर चलते हुए रचनात्मक कार्य करना चाहते थे। नायडू ने उपराष्ट्रपति के रूप में अपने दो साल के कार्यकाल पर आधारित अपनी पुस्तक 'लिस्निंग, लर्निंग एंड लीडिंग' के विमोचन के मौके पर कहा, 'मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपसे सच कहूं तो मैं कभी उपराष्ट्रपति नहीं बनना चाहता था।' उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपनी इच्छा प्रकट की थी कि उनके दूसरे कार्यकाल में वह सरकार से हटना चाहते हैं, नानाजी देशमुख के पदचिह्नों पर चलना चाहते हैं और रचनात्मक कार्य करना चाहते हैं।

नायडू ने कहा, 'मैं उसके लिए योजना बना रहा था... मुझे खुशी थी कि मैं वह करूंगा... लेकिन वह नहीं हो पाया।' उन्होंने कहा कि उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के लिए कुछ नाम भी सुझाए थे। नायडू ने कहा कि पार्टी की संसदीय दल की बैठक के बाद अमित भाई (भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह) ने कहा कि पार्टी में सभी का मानना है कि मैं सबसे उपयुक्तव्यक्ति रहूंगा। मैंने कभी उसकी उम्मीद नहीं की थी। मेरी आंखों में आंसू थे, इसलिए नहीं कि मेरा मंत्री पद जा रहा था जिसे तो मैं कहीं न कहीं छोड़ने ही जा रहा था।' उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने सिर्फ इस वजह से अपनी संवेदना पर काबू पाया कि अगले दिन से वह भाजपा कार्यालय नहीं जा पायेंगे या पार्टी कार्यकर्ताओं से नहीं मिल पाएंगे। उन्होंने कहा कि वह आंदोलन (अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) के भविष्य को लेकर चिंतित थे, जिससे उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने कहा, 'मैं बहुत कम उम्र में इस आंदोलन से जुड़ा और पार्टी ने प्रधानमंत्री के पद को छोड़ कर सब कुछ दिया, वैसे भी मैं इस पद के लिए उपयुक्त नहीं था। मैं अपनी क्षमताओं और काबलियत को जानता हूं।'

मुख्यमंत्री पर फूटा दुर्घटना में हताहत बच्चों के परिवार वालों का गुस्सा

नई टिहरी, 11 अगस्त (भाषा)।

टिहरी जिले में कंगसाली गांव में पांच दिन पूर्व स्कूल वाहन दुर्घटना में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि देने तथा उनके परिजन से मिलने पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को रविवार को ग्रामीणों का गुस्सा झेलना पड़ा। मुख्यमंत्री रावत ने एक-एक लाख रुपए के चेक बच्चों के परिवार वालों को दिए लेकिन उन्होंने उसे लेने से इनकार कर दिया। गुस्साए परिवार वालों ने अपनी मांगों पर एक छह सूत्रीय ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा पर उन्होंने उस पर गौर नहीं किया इस पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगाए। इसके बाद देहरादून से कंगसाली गांव पहुंचे रावत केवल आधा घंटे में ही कार्यक्रम की इतिश्री कर वापस लौट गए। छह अगस्त को सुबह हुए इस दर्दनाक हादसे में स्कूली बच्चों से भरा वाहन गड्ढे में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 10 बच्चों की मौत हो गई तथा आठ अन्य घायल हो गए।

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उपक्रम)
पंजीकृत कार्यालयः सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017, भारत
फोन नं.: +91-11-29565666, फैक्स नं.: +91-11-26854000, वेबसाइटः www.ircon.org, ई-मेलः info@ircon.org
सीआईएनः L45203DL1976GOI008171

43वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर अवधि और रिमोट ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 43वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) **मंगलवार, 3 सितम्बर, 2019 को प्रातः 10.00 बजे एयर फोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रोतो पार्क, नई दिल्ली-110010** में आयोजित की जाएगी जिसमें सूचना में निर्धारित कार्यों का निष्पादन किया जाएगा। 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना कम्पनी के शेयरधारकों को उनके पंजीकृत पते/ई-मेल पते पर भेज दी गई है। एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइटः www.ircon.org पर 'निवेशक' खण्ड और कार्वीफिनटेक प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट https://evoting.karvy.com पर भी उपलब्ध है।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसरण में कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक **बुधवार, 28 अगस्त, 2019 से मंगलवार, 3 सितम्बर, 2019 तक (दोनों दिवस शामिल)** बंद रहेंगे। निदेशक मंडल द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार अंतिम लाभांश, यदि वार्षिक आम बैठक में घोषित हो जाता है, तो उन सदस्यों को **बुधवार, 18 सितम्बर, 2019** को भुगतान किया जाएगा जिनके नाम **27 अगस्त, 2019** को व्यवसाय घंटों की समाप्ति पर भौतिक शेयरों के संबंध में कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में और डिमेटिरियलाइज्ड शेयरों के संबंध में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किये गये लाभार्थी स्वामियों के विवरण में शेयरों के "लाभार्थी स्वामी" के रूप में शामिल होंगे।

कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में, कम्पनी एजीएम में निष्पादित किये जाने वाले प्रस्तावों के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है और इस संबंध में, कम्पनी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ('रिमोट ई-वोटिंग') सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कार्वीफिनटेक प्राइवेट लिमिटेड की सेवाएं ली हैं।

इसलिए सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

1. **रिमोट ई-वोटिंग 31 अगस्त, 2019 (प्रातः 9.00 बजे आईएसटी) प्रारंभ होगी और 2 सितम्बर, 2019 (सायं 5.00 बजे आईएसटी) बंद होगी।** उसके बाद कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल हटा लिया जाएगा और यह सुविधा बंद कर दी जाएगी।
2. एजीएम में स्क्रिप्ट ई-वोटिंग के लिए योग्यता के निर्धारण हेतु कट-ऑफ तिथि मंगलवार, 27 अगस्त, 2019 होगी। रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान, कट-ऑफ तिथि अर्थात् **मंगलवार, 27 अगस्त, 2019** को भौतिक प्रारूप या डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक ही अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से दे सकते हैं। सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार वोट देने के बाद, सदस्य उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते।
3. एजीएम की सूचना भेजने के बाद परंतु कट ऑफ तिथि या उससे पहले कम्पनी के अंशधारक अपना यूजर आईडी एवं पासवर्ड कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31-32, गाचीबावली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500 032, फोन नं. 040 6716 2222, ई-मेल आईडी: einward.ris@karvy.com, टोल फ्री नं. 18003454001 एवं फैक्स नं. 040 23420814 से प्राप्त कर सकते हैं।
4. सदस्यगण जो बैठक से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट देते हैं, वह बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन वह दोबारा वोट नहीं कर सकते। बैठक के स्थान पर सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है, वे बैलेट पेपर के माध्यम से अपना वोट दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोटिंग की सुविधा एजीएम के स्थान पर उपलब्ध नहीं होगी।
5. ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए श्री सचिन अग्रवाल, प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव, मैसर्स अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स, कम्पनी सचिव को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

सदस्यों से आग्रह है कि एजीएम की सूचना में मुद्रित रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित निर्देशों को भली-भांति पढ़ लें। यदि ई-वोटिंग के संबंध में कुछ प्रश्न हों तो, कृपया कार्वी की वेबसाइट https://evoting.karvy.com पर उपलब्ध हेल्प एंड एफएक्यू सैक्शन को देखें और किसी अन्य पूछताछ के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे श्री एस. वी. राजु, उप महाप्रबंधक, कार्वीफिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31-32, गाचीबावली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500 032, से पदनामित ई-मेल आईडी: einward.ris@karvy.com या निम्नलिखित फोन नं. 040 6716 2222, 18003454001 (टोल फ्री) एवं फैक्स नं. 040 23420814 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

कृते इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
हस्ता./-
रितु अरोड़ा
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 11.08.2019

जम्मू-कश्मीर में पुलिस, कानून व्यवस्था केंद्र के नियंत्रण में होगी

नई दिल्ली, 11 अगस्त (भाषा)।

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कानून एवं व्यवस्था और पुलिस का नियंत्रण उपराज्यपाल के माध्यम से सीधे केंद्र के हाथों में रहेगा जबकि भूमि वहां की निर्वाचित सरकार के अधीन एक विषय होगा। अधिकारियों ने रविवार को यह बात कही।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर को बांटने संबंधी विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी थी जिससे दो केंद्र शासित प्रदेश...जम्मू-कश्मीर और लद्दाख 31 अक्तूबर को अस्तित्व में आएंगे। भूमि को लेकर अधिकार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की निर्वाचित सरकार के पास रहेंगे। ऐसा दिल्ली के उलट होगा जहां भूमि पर नियंत्रण उपराज्यपाल दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के जरिए रखते हैं।

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में एक उपराज्यपाल होंगे और उसकी विधानसभा में सीटों की संख्या 107 होगी जिसे परिसीमन कवायद से 114 तक बढ़ाया जा सकता है। विधानसभा की 24 सीटें खाली रहेंगी क्योंकि ये सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में पड़ती हैं। दिल्ली और पुडुचेरी में पुलिस और कानून एवं व्यवस्था को उपराज्यपाल के माध्यम से सीधे केंद्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दोनों ही केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी विधानसभा हैं।

भूमि पर नियंत्रण से संबंधित मामले जिसमें भूमि अधिकार, कृषि भूमि का हस्तांतरण, भूमि सुधार और कृषि ऋण केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की निर्वाचित सरकार के अंतर्गत होंगे। आकलन और राजस्व संग्रहण सहित भूमि राजस्व, भूमि रिकार्ड रखरखाव, राजस्व उद्देश्य के लिए सर्वेक्षण और राजस्व का हस्तांतरण भी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की निर्वाचित सरकार के अधिकार क्षेत्र में आएगा।

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पुलिस, कानून एवं व्यवस्था और भूमि के मामले उपराज्यपाल के सीधे नियंत्रण में होंगे, जहां का प्रशासन केंद्र उपराज्यपाल के जरिए संभालेगा। कानून के तहत लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। नवगठित दोनों केंद्र शासित प्रदेश नियत दिन 31 अक्तूबर को अस्तित्व में आएंगे।

उसी दिन से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए साझा हाई कोर्ट होगा।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) जैसी अखिल भारतीय सेवाएं उपराज्यपाल के नियंत्रण में होंगी न कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की निर्वाचित सरकार के नियंत्रण में। ये सेवाएं और एसीबी दो प्रमुख मुद्दे हैं जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल नीत दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच बार-बार टकराव होता रहा है।

बिहार : शहीद दिवस पर अमर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि

पटना, 11 अगस्त (भाषा)।

बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को शहीद दिवस के अवसर पर 11 अगस्त 1942 को शहीद हुए 'आजादी के मतवाले' सात सेनानियों को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

चौहान और नीतीश ने शहीद दिवस के अवसर पर सात अमर शहीदों - उमाकांत प्रसाद सिंह, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगतपति कुमार, देवी प्रसाद चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह - की कुर्बानियों को याद किया और उन्हें नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की।

पटना में शहीद स्मारक परिसर में रविवार को आयोजित एक राजकीय समारोह के दौरान चौहान और नीतीश ने इन अमर शहीदों को नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी।

हाथी के हमले में दो लोगों की मौत

कोरबा (छत्तीसगढ़), 11 अगस्त (भाषा)।

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में अलग-अलग घटनाओं में हाथी ने दो लोगों को रौंद डाला, जिससे उनकी मौत हो गई। मरने वालों में एक महिला भी शामिल है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

संभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) भानु प्रताप सिंह ने बताया कि मवेशियों के साथ प्रतापपुर के जंगल में गए सोमनाथ कोडकू (45) का शुक्रवार को हाथी से सामना हुआ था।

कोडकू प्रतापपुर के ही रहने वाले थे। यह स्थान कोरबा से करीब 200 किलोमीटर की दूर है।उन्होंने बताया कि हाथी ने पहले कोडकू को सूंड में लपेटकर जमीन पर पटक दिया और फिर उन्हें पैरों से कुचल कर मार डाला। कोडकू जब घर नहीं लौटे तब कुछ स्थानीय लोगों ने वन विभाग से संपर्क किया, जिन्होंने तलाश अभियान चलाया।सिंह ने बताया कि शनिवार सुबह जंगल में उनका शव मिला।

कांग्रेस एक परिवार से आगे नहीं बढ़ पाई : शिवराज

भुवनेश्वर, 11 अगस्त (भाषा)।

वरिष्ठ भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को कहा कि पिछले आम चुनाव में वंशवाद की राजनीति नकार दी गई लेकिन कांग्रेस ने इससे कोई सीख नहीं ली और वह अब भी चाहती है कि पार्टी का नेतृत्व राहुल गांधी और सोनिया गांधी करें। चौहान ने कहा कि भाजपा ने एक मिसाल कायम की क्योंकि उसके नेता स्वाभाविक रूप से पार्टी में उभरे जबकि कांग्रेस एक परिवार से आगे नहीं बढ़ पाई।

भाजपा उपाध्यक्ष ने यहां पत्रकारों से कहा, 'मैंने सोचा कि कांग्रेस चुनावी नतीजों से सीखेगी लेकिन वह अब भी एक परिवार पर ही निर्भर है। यह हैरानी भरा है कि सीडब्लूसी अब भी चाहती है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी पार्टी का नेतृत्व करें।' गौरतलब है कि कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्लूसी) ने शनिवार को सोनिया गांधी को पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया। जब तक एआइसीसी स्थायी अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर लेती तब तक सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष रहेंगी।

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वंशवाद, परिवार और जाति की राजनीति से चल रही पार्टियों को आम चुनावों में उत्तर प्रदेश और बिहार समेत हर जगह हार मिलीं। उन्होंने कहा कि लोगों ने पश्चिम बंगाल में भी तुष्टिकरण की राजनीति को नकार दिया और

> ● कहा, पिछले आम चुनाव में वंशवाद की राजनीति नकार दी गई लेकिन कांग्रेस ने इससे कोई सीख नहीं ली और वह अब भी चाहती है कि पार्टी का नेतृत्व राहुल गांधी और सोनिया गांधी करें।

भाजपा के राष्ट्रवाद और विकास के एजंडे को चुना। चौहान ने कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस योग्य, सक्षम और प्रतिभावान नेताओं की कमी का सामना कर रही है। अगर वह लोकतांत्रिक तरीके से नेता नहीं चुन पाती तो पार्टी को कोई भी नहीं बचा सकता।

राहुल गांधी को 'रणछोड़' बताते हुए भाजपा नेता ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद उन्होंने एक पलायनवादी की तरह व्यवहार किया। उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की शिकस्त के बाद 25 मई को पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में कोई भी पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को याद नहीं करता क्योंकि वह गांधी परिवार से ताल्लुक नहीं रखते थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया लेकिन सोनिया और राहुल गांधी की 'मां-बेटे की जोड़ी' ने सब कुछ अपने नियंत्रण में रखा।

कांग्रेस पर देश में कई समस्याओं के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाते हुए चौहान ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को लाकर गुनाह किया था। उन्होंने कहा, 'नेहरू की ऐतिहासिक गलती को अब अनुच्छेद 370 को खत्म करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुधारा है।'

दिल्ली पुलिस
शांति सेवा न्याय

स्वतंत्रता दिवस 2019

बहादुर सेवा के लिए सलाम
आपका सहयोग

Public visiting the Independence Day 2019 function at the Red Fort are requested not to bring the following prohibited items:
जनता से अनुरोध है कि लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस 2019 के समारोह में निम्नलिखित वर्जित वस्तुएं साथ में न लाएं:

Prohibited Items		वर्जित वस्तुएं	
Photo/फोटो	Particulars / विवरण	Photo/फोटो	Particulars / विवरण
	Eatables खाने-पीने की चीजें		Cigarettes, Bidies, Lighter सिगरेट, बीड़ी, लाईटर
	Bag, Briefcase थैला, ब्रीफकेस		Alcohol, Perfumes, Spray शराब, इत्र, स्प्रे
	Radio, Transistor, Tape Recorder, CD, DVD, MP3 Players रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेपरिकॉर्डर, सीडी, डीवीडी, एमपी3 प्लेयर		Dagger, Sword, Cutting Material, Sharp/Pointed Edged Material, Screw Drivers नुकीला हथियार, चाकू, पेंचकस
	Camera, Binocular, Handycam कैमरा, दूरबीन, हैण्डीकैम		Umbrella, Replica Fire Arms, Toy Gun or Toys छाता, आग्नेयास्त्र, खिलौना पिस्तौल और खिलौने
	Thermos Flasks, Water Bottles, Cans थर्मस, पानी की बोतल, कैन		Knives, Scissors, Razors, Blades, Wire, Pluckers चाकू, कैंची, रेज़र, ब्लेड, तार, प्लकर
	Inflammable Items, Match Boxes ज्वलनशील पदार्थ, दियासलाई		Arms & Ammunition, Fireworks, Crackers Explosive etc. हथियार और गोला बारूद, पटाखे आदि
	Various Electronic Gadgets, Devices e. g. I-Pad, I-Pod, Palm Top/Laptop, Computer, Tablets, Power Bank etc. विभिन्न इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे आई-पैड, आई-पोड, पाम टॉप/लैपटॉप, कम्प्यूटर, टैब्लेट, पावर बैंक इत्यादि		Avoid keeping Mobile Phones, Remote Controlled Car Keys as it may delay your entry due to checking मोबाईल फोन, रिमोट कंट्रोल कार चाबी रखने से बचें क्योंकि इससे जांच के दौरान आपके प्रवेश में देरी हो सकती है।

Any unidentified object, if noticed, may be brought to the notice of the nearest Security Personnel.
यदि, कोई लावारिस वस्तु दिखाई दे, तो निकटतम सुरक्षाकर्मी के नोटिस में लाएं।

Please co-operate with the police for searching/frisking.
कृप्या तलाशी देने में पुलिस के साथ सहयोग करें।

Please be alert to your surroundings.
कृप्या अपने आस पास नज़र रखें।

पुलिस आयुक्त दिल्ली को ई-मेल करें: cp.amulyapatnaik@delhipolice.gov.in
लिखें: पुलिस आयुक्त दिल्ली को पोस्ट बॉक्स नं. 171, जीपीओ, नई दिल्ली पर

DP/9134/19

तुरंत पुलिस सहायता के लिए कॉल करें 100
पुलिस को सूचना देने के लिए कॉल करें 1090

जनसत्ता

12 अगस्त, 2019

सकारात्मक समझौता

पूर्वोत्तर लंबे समय से अशांत है। वहां कुछ अलगाववादी संगठन और कई जातीय संगठन सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगातार चुनौतियां पेश करते रहे हैं। इन संगठनों पर कई बार लगाम कसने के लिए कड़े कदम उठाए गए, तो कई बार बातचीत के जरिए उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास भी हुए, मगर कोई उल्लेखनीय सकारात्मक नतीजा नहीं निकल सका। ऐसे में त्रिपुरा के एक विद्रोही समूह का केंद्र सरकार के साथ समझौते में हिंसा का रास्ता छोड़ने का संकल्प लेना और संविधान में विश्वास जताना आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से नई उम्मीद जगाता है। बताते चलें कि शनिवार को केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार और सबीर कुमार देबवर्मा के नेतृत्व वाले नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्विप्रा; एनएलएफटी-एसडी ने हस्ताक्षर किए। इस समूह के अट्ठासी सदस्यों ने हथियार डाल कर मुख्यधारा में शामिल होने का संकल्प लिया। इस संगठन पर तीन सौ से ऊपर हिंसक घटनाओं के मामले दर्ज हैं। इस पर गैरकानूनी गतिविधियां निरोधक कानून के तहत प्रतिबंध लगा हुआ था। अब इसके साथ समझौते के बाद सरकार इनके आवास, शिक्षा और पुनर्वास संबंधी सुविधाएं जुटाएगी। इस समझौते से पूर्वोत्तर में सक्रिय दूसरे विद्रोही और अलगाववादी संगठनों के भी मुख्यधारा में लौटने की उम्मीद जगी है।

पूर्वोत्तर के मणिपुर, त्रिपुरा और नगालैंड में कई अलगाववादी संगठन सक्रिय हैं। इनके असंतोष की बड़ी वजह वहां विकास योजनाओं पर ध्यान न दिया जाना है। छिपी बात नहीं है कि ये राज्य लंबे समय से उपेक्षित रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी बुनियादी सुविधाओं का वहां घोर अभाव है। इसलिए वे अलग होने की मांग करते हुए हिंसा का रास्ता अख्तियार करते रहे हैं। हालांकि हथियार के बल पर उन्हें मुख्यधारा में लाने और भारतीय संविधान में विश्वास जताने पर विवश करने की कोशिशें भी हुईं, कुछ संगठनों के साथ संघर्ष विराम के समझौते भी हुए, पर विकास कार्यक्रमों को ठीक से लागू न किए जा सकने की वजह से उनका असंतोष बार-बार फूटता रहा। इन संगठनों के असंतोष का शिकार ज्यादातर वहां तैनात सुरक्षा बल होते रहे हैं। चूंकि पूर्वोत्तर के इलाके दुर्गम हैं, वहां विद्रोही संगठनों पर नजर रखना सुरक्षा बलों के लिए चुनौती भरा काम रहा है। इन संगठनों का गुस्सा उन राजनेताओं पर भी फूटता रहा है, जो केंद्र के साथ निकटता बनाते रहे हैं। मगर अब शायद इन अलगाववादियों को यह समझ आने लगा है कि मुख्यधारा में शामिल होकर ही विकास कार्यक्रमों को आकार दिया जा सकता है। त्रिपुरा के विद्रोही संगठन एनएलएफटी के समझौते से यही संकेत मिलता है।

पूर्वोत्तर के विद्रोही संगठनों का मन बदलने के पीछे कुछ वजहें साफ है। इस इलाके में विद्रोह की वजह विकास गतिविधियां संचालित न होने के अलावा केंद्र के साथ वहां के लोगों का कोई संवाद न रहना भी रही है। केंद्र सरकार ने इस तरफ ध्यान केंद्रित किया। खासकर त्रिपुरा में 2015 में केंद्र सरकार ने एनएलएफटी के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू किया। उसके बाद से इस संगठन ने किसी हिंसक घटना को अंजाम नहीं दिया। इसी तरह मणिपुर और नगालैंड के दूसरे संगठनों के साथ भी बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। एनएलएफटी के साथ हुए समझौते के बाद केंद्र सरकार ने कहा है कि वह त्रिपुरा सरकार की विकास योजनाओं संबंधी रूपरेखा पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। इसी तरह पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों में भी विकास गतिविधियां तेज की गई हैं।

बाढ़ का कहर

इस बार महाराष्ट्र, गुजरात से लेकर कर्नाटक और केरल तक में बाढ़ से जो तबाही मची है उससे यह तो साफ है कि मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी के बावजूद सरकारों ने बचाव के शायद ही कोई पर्याप्त उपाय पहले से किए हों। पिछले चार दिनों में इन राज्यों में हुई भारी मानसूनी बरसात ने ऐसा कहर बरपाया कि ज्यादातर जगहों पर राष्ट्रीय राजमार्ग तक पांच-छह फीट पानी में डूब गए। गांव के गांव जलमग्न हैं। हल्दी की खेती के लिए मशहूर महाराष्ट्र के सांगली जिले की हालत तो बहुत खराब है। इस जिले के कई गांव बीस-बीस फुट पानी में डूब गए हैं। इन राज्यों में बाढ़ से मरने वालों का सरकारी आंकड़ा दो सौ से ऊपर है। बेघरों की तादाद तो लाखों में है। सांगली और कोल्हापुर जिलों में बाढ़ के पानी की निकासी बढ़ाने के लिए कर्नाटक ने अलमाटी बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़ा है। गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोबर बांध के तीस में से छब्बीस गेट खोलने पड़ गए। हालत यह है कि केरल के चौदह, कर्नाटक के अठारह, महाराष्ट्र के ग्यारह और गुजरात के सात जिले भयानक बाढ़ की चपेट हैं और इन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया चुका है। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां पहली बार बाढ़ आई है। हालांकि सभी सरकारों ने बचाव और राहत कार्य शुरू तो किए हैं लेकिन वे ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहे हैं। ऐसे में ज्यादातर बाढ़ग्रस्त इलाकों, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में लोग बाढ़ के पानी में फंसे हैं।

ऐसा नहीं है कि बाढ़ कोई अनायास ही आई हो। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी। इस बात का अनुमान शायद सरकार को नहीं रहा होगा कि लगातार मूसलाधार बारिश से नदियां उफन कर बड़े इलाकों में फसलों को अपनी चपेट में ले लेंगी। हालात इसी से बिगड़े। सांगली में तो पांच-छह घंटे की भारी बारिश में समंदर जैसे हालात बन गए। अभी समस्या यह है कि ज्यादातर राज्यों में लोगों को बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों से सुरक्षित निकालने का भी बंदोबस्त नहीं हो पाया है। जाहिर है राज्यों के पास बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के स्थायी और पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं।

हालांकि एनडीआरएफ की टीमें लगी हैं लेकिन पानी में फंसे लोगों की तादाद लाखों में है। नौ सेना और वायुसेना के हेलिकॉप्टर इन इलाकों में खाने के पैकेट और दवाइयां गिरा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा खतरा पानी में फंसे लोगों की जान का है। असम के तैंतीस जिले बाढ़ की चपेट में हैं और पिछले चार दशकों में वहां पहली बार इतनी भयानक बाढ़ आई है। राज्य में 1980 में बाढ़ नियंत्रण बोर्ड बनाया गया था लेकिन आज तक सरकार ने ऐसे कोई स्थायी उपाय नहीं किए जो राज्य को हर साल आने वाली बाढ़ से बचा सकें। बिहार के भी कई जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। समस्या यह है कि हम पिछली घटनाओं से कोई सबक नहीं लेते। पिछले साल केरल को बाढ़ के जिस विकराल रूप का सामना करना पड़ा था उससे हमने कुछ नहीं सीखा। सवाल है कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए ठोस योजनाएं क्यों नहीं बनाई जातीं? सरकारें इसे एक फौरी और मौसमी संकट मान कर चलती हैं। इस वक्त ज्यादातर बाढ़ ग्रस्त राज्यों के पास ठोस आपदा प्रबंधन प्रणाली नहीं है। वरना लोग जैसा संकट झेलने को मजबूर हैं वैसा शायद नहीं होता।

कल्पमेधा

प्राय: संकट काल विजय के साथ ही आता है।

-नेपोलियन

इतिहास में भी झांकना होगा

शीतलाल सिंह

सरदार वल्लभभाई पटेल निश्चित रूप से देश के बड़े नेताओं में थे और यह कहना कि पंडित नेहरू ने जम्मू-कश्मीर के मामले में उनकी नहीं चलने दी थी और उन्होंने अपनी इस नियति को स्वीकार कर लिया था, नेहरू के साथ पटेल के नायकत्व का भी अपमान है। इतिहास गवाह है कि उन्हें आजीवन पंडित नेहरू का विश्वास प्राप्त रहा था।

जम्मू-कश्मीर को संविधान के अनुच्छेद 370 से मुक्ति दिलाने और दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के केंद्र सरकार के फैसले के समर्थन या विरोध के प्रश्न पर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस बिखर-सी गई है। अनुच्छेद 370 को खत्म करने और इसके स्थान पर नया संशोधित अनुच्छेद लाने संबंधी संकल्प (संवैधानिक प्रस्ताव) पर चर्चा के दौरान लोकसभा में कांग्रेस के एक नेता द्वारा यह पूछे जाने पर कि जब यह मामला संयुक्त राष्ट्र में है तो द्विपक्षीय या आंतरिक मामला कैसे हो सकता है और इससे संबंधित निर्णय कैसे लाभकारी हो सकते हैं, तो इस पर कांग्रेस अध्यक्ष बहुत नाराज हुए। गौरतलब है कि इस सिलसिले में सत्तापक्ष द्वारा निरंतर कहा जाता रहा है कि आजादी के बाद पांच सौ इकसठ देशी रियासतों का सफलतापूर्वक विलय तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की देन है लेकिन जम्मू-कश्मीर का मामला प्रधानमंत्री के तौर पर खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे और उन्हीं के कारण हमें इस राज्य की विशेष स्थिति और अनुच्छेद-370 का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, उन्हीं की वजह से 1954 में अनुच्छेद-35 ए का भी उदय हुआ, जिससे कश्मीर के मूल निवासियों की पहचान की तिथि निर्धारित हुई। लेकिन यह कथन न पूरी तरह दुरुस्त है, न तथ्य।

सच्चाई यह है कि 15 अगस्त, 1947 तक जम्मू-कश्मीर भारत में शामिल ही नहीं हुआ था। उसने पाकिस्तान के निकट रहने की इच्छा प्रकट की थी और उससे दो समझौते भी किए थे। लेकिन पाकिस्तान समर्थित कबाइली आक्रमण के बाद उसे अस्तित्व रक्षा के लिए भारत से मदद मांगनी पड़ी। उस वक्त भी कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने शासक बने रहने की अपनी इच्छा जताई थी। इसी कारण कश्मीर के संबंध में विशेष व्यवस्था करनी पड़ी और मामले में संयुक्त राष्ट्र का भी दखल हुआ, जिसने वास्तविक नियंत्रण रेखा खींच कर उसकी रक्षा के लिए हो रही भारत-पाक भिड़ंत को सीमित करके दोनों को अलग-अलग रहने का निर्देश दिया था।

यहां समझने की बात यह है कि भारत उस वक्त महाराजा हरि सिंह की सैन्य मदद की मांग नहीं मानता तो समूचा जम्मू-कश्मीर पहले कबाइलियों के और फिर पाकिस्तान के कब्जे में चला जाता। तब उसका जो हिस्सा अभी भारत के पास है, वह भी नहीं होता। यह जानना दिलचस्प होगा कि महाराजा हरि सिंह को कश्मीर का राज अपने पिता गुलाब सिंह से उत्तराधिकार में मिला था, जबकि उनके पिता ने उसे एक करोड़ रुपए में अफगानिस्तान से खरीदा था। इस सौदे की, जिसमें गुलाब सिंह केवल पचहत्तर लाख रुपए ही दे पाए थे, पुष्टि राजधानी दिल्ली के राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्थित अभिलेखों से की जा सकती है। साफ है कि उन दिनों जम्मू-कश्मीर के वास्तविक सत्ताधीश महाराजा हरि सिंह ही थे और उन्होंने कश्मीर को भारत में कुछ शर्तों के तहत ही शामिल करना स्वीकार किया तो उनकी अवज्ञा नहीं की जा सकती थी। आज भी उन्हें अमान्य नहीं ठहराया जा सकता। न ही ठहराया जा रहा है।

सरदार पटेल के नेतृत्व में पांच सौ इकसठ रियासतों के सफल एकीकरण और विलय पर जाएं तो उनमें हैदराबाद और जूनागढ़ दो ऐसी रियासतें थीं जो भारत में शामिल होने को राजी नहीं थीं। इनमें हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई के बावजूद भारत ने यह सिद्धांत छोड़ा नहीं था कि वह रियासतों की जनता की इच्छा को ही निर्णायक मानता है। इसीलिए जम्मू-कश्मीर के महाराजा का विलय पत्र उसके तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड माउंटबैटन के समक्ष पेश किया गया तो जनता की इच्छा पर तकिया रखते हुए उन्होंने उसको अस्थायी रूप से ही स्वीकार किया। इससे जुड़े प्रश्न बाद में संयुक्त राष्ट्र में भी उठे, जहां भारत के रक्षा मंत्री कृष्णमेनन के साथ सात दिन चली बहस के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा था, 'इस शानदार बहस के लिए धन्यवाद। लेकिन आपने जहां-जहां हैदराबाद कहा है, वहां कश्मीर और जहां कश्मीर कहा है, वहां हैदराबाद रख दीजिए, तो आपके तर्क लागू नहीं होते।'

प्रसंगवश, इंग्लैंड की संसद ने भारत के विभाजन का निर्णय किया तो उसके दोनों टुकड़ों का क्षेत्र हिंदू-मुसलमान के नाम पर नहीं बल्कि इस आधार पर तय किया था कि जहां कांग्रेस जीती है, वह भारत और जहां मुसलिम लीग जीती है, वह पाकिस्तान होगा। इसीलिए पूरब और पश्चिम में दो पाकिस्तान बने, जबकि पख्तूनिस्तान भारत के हिस्से में आया। लेकिन भारत को लगा कि उसके लिए अपनी मुख्य भूमि से अति दूर पख्तूनिस्तान का शासन चलाना आसान नहीं होगा, तो उसने जनमत संग्रह के बहाने उससे मुक्ति पा ली। वहां के कांग्रेसी नेता खान अब्दुल गफ्फार खां (सीमांत गांधी) ने इसका विरोध भी किया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ और जनमत संग्रह के परिणामों के अनुसार उसे पाकिस्तान को सौंप दिया गया। इस सबके लिए स्वाभाविक तौर पर उन्हें ही दोषी ठहराया जाएगा, जो उस समय सत्तारूढ़ थे। लेकिन उस वक्त देश की रचना, निर्माण और व्यवस्था संचालन के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि जम्मू-कश्मीर या अन्य प्रश्नों पर जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल की असहमतियों को दरकिनार करके फैसले किए। ऐसा होता तो क्या पटेल उनके मंत्रिमंडल में बने रहते?

हम जानते हैं कि जम्मू-कश्मीर में धारा-370 की विशेष व्यवस्था से देश के अन्य भाग प्रभावित नहीं हो रहे थे। इसके बावजूद जो सत्ताधारी नेता कश्मीर संबंधी स्थितियों के लिए पंडित नेहरू को ही दोषी ठहराना चाहते हैं, उनका अपना मूल्यांकन हो सकता है लेकिन जब नेहरू आजादी की लड़ाई लड़ या कश्मीर को भारत के साथ जोड़ रहे थे, तब उनके पुरखे खुद को राजनीति से परे और सांस्कृतिक संगठन कह कर शतुर्मुर्ग बने हुए थे।

दूसरे पहलू पर जाएं तो देश में अब तक सत्रह वर्षों तक गैर-कांग्रेसी सरकारें रह चुकी हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी जम्मू-कश्मीर के उस हिस्से को भारत में शामिल करने के प्रयत्न नहीं किए, जो पाक कब्जे में है, जबकि महाराजा हरि सिंह ने भारत में पूरे कश्मीर का विलय किया था। इसके चलते भारतीय कश्मीर छोटे से क्षेत्र तक सीमित होकर रह गया है। यकीनन, उसे साथ रखने की इच्छा सभी भारतवासियों की है, लेकिन विडंबना यह कि देश के सत्ताधीश जब भी नीतिगत रूप से वास्तविक स्थितियों का परीक्षण करते हैं, उसे अपनी राजनीतिक पसंद और नापसंद से जोड़ देते हैं। सरदार वल्लभभाई पटेल निश्चित रूप से देश के बड़े नेताओं में थे और यह कहना कि पं. नेहरू ने जम्मू-कश्मीर के मामले में उनकी नहीं चलने दी थी और उन्होंने अपनी इस नियति को स्वीकार कर लिया था, नेहरू के साथ पटेल के नायकत्व का भी अपमान है। इतिहास गवाह है कि उन्हें आजीवन पंडित नेहरू का विश्वास प्राप्त रहा था।

असहमतियां और मतभेद हर काल में होते रहे हैं। इसे यों समझ सकते हैं कि आज अनुच्छेद 370 खत्म करने को लेकर केंद्र सरकार के समर्थन में भी लोग हैं और विरोधी भी। यह और बात है कि देश का बड़ा हिस्सा सरकार के फैसले के पक्ष में खड़ा दिखेगा। ऐसे में राजनीतिक मतभेदों की बिना पर किसी पार्टी या नेता या सरकार के खिलाफ अभियान उचित नहीं कहा जा सकता।

आंसुओं की दुनिया

सूर्यप्रकाश चतुर्वेदी

दुनिया मेरे आगे

किसी शायर ने कहा है- 'यों ही आंखों में आ गए आंसू, जाइए आप, कोई बात नहीं।' कविता और शायरी में चीजों को कमतर करके देखना या बढ़ा-चढ़ा कर पेश करना या अनदेखा करने का चलन है। दरअसल, आंखों में यों ही आंसू नहीं आते। आंसुओं के आने का कोई सबब होता है, कोई वजह होती है। हर आंख में आंसू आ जाने की वजह दूसरों से अलग होती है।

कुछ लोग हैं जिनकी आंखों में दूसरों का दुख-दर्द या तकलीफ देख कर आंसू आ जाते हैं। ये आंसू उन्हें दुःखी लोगों के करीब ले जाते हैं और वे उनके साथ जुड़ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें अचानक ही बहुत खुशी मिलने पर भर आती हैं। यानी अधिक खुशी मिलने पर भी आंखों से आंसू झरने लगते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी सतत् उपेक्षा देख कर द्रवित हो उठते हैं और इस कारण उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो कुछ अपना सम्मान होते देख कर या तरीफ सुन कर इतने विह्वल हो जाते हैं कि उनकी आंखों से जार-जार आंसू बहने लगते हैं। खुद को असहाय या हताश पाकर भी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हंसते-हंसते रो देते और रोते-रोते हंस देने वाले भी मैंने देखे हैं। लेकिन कलात्मक रुझान वाले लोग अच्छी कलाकृति देखने या अच्छी अभिव्यक्ति या प्रस्तुति पाने पर रोने लगते हैं। बनार्ड शॉ करते थे कि अगर कोई चीज उनकी आंखों को आंसुओं से भर देती है तो वह है किसी भाव का सुंदर तरीके से अभिव्यक्त किया जाना। एक सुंदर वस्तु अगर सुंदर तरीके से अभिव्यक्त की जाए तो उसे देख कर किसी भी साहित्य अनुरागी की आंखों से आंसू झरने लगेंगे। फिर भले वह चित्र हो या नृत्य, गायन या कविता, शायरी। मृत्यु के समय भी लोग रोते हैं, पर वे आंसू दुख के होते हैं।

रोना कितना जरूरी है, यह हम सभी जानते हैं। टेनिसन की कविता 'होम दे ब्राट हर वॉरियर डेड' में जब मृत योद्धा की दुखी पत्नी काफी देर तक चुप रहती है तो उसे रुलाने की कोशिश की जाती है, ताकि वह सामान्य हो सके। यानी आंख में आंसू आना परिस्थिति, मनोस्थिति और व्यक्ति के अपने स्वभाव और मानसिकता पर निर्भर करता है। रोना एक सहज और स्वाभाविक मानवीय प्रक्रिया है। आंसू दिल की गहराई से महसूस किए गए भाव से फूटते हैं।

ऐसी स्थिति भी बनती है जब दुख के अतिरेक में यानी अत्यधिक दुख की स्थिति में अधिक रोते-रोते आंसू भी सूख जाते हैं और आंखें बिना पानी की नदी जैसी हो जाती हैं। इस स्थिति को खुमार बाराबंकवी ने अपने शेर में बखूबी बयान किया है- 'रफ्तार-ए-गम का जोर नहीं है जो था मगर, अब अश्क ही नहीं है बहाने के वास्ते।' यह गम यानी तकलीफ की इंतिहा है। आपने खलनायक और खलनायिकाओं द्वारा शरारत की खातिर बहाए जाने वाले नकली आंसू भी देखे ही होंगे। किस खूबसूरती से वे नजर बचा कर आंसुओं को हाथ की उंगली से पोंछ कर जमीन पर छिड़कते हैं और बताते हैं कि असलियत क्या है। लेकिन हम ऐसे नकली आंसुओं का भी जिक्र क्यों करें? बेहतर होगा हम अपने आप और सहज रूप से आंखों में आने वाले शुद्ध आंसुओं तक ही सीमित रहें जो इंसान की संवेदना के परिचायक हैं।

अंतर्मन और नैसर्गिक रूप से किसी स्मृति घटना से प्रेरित होकर उमड़ने वाले आंसुओं का भी अपना स्वभाव और भौतिक विशेषताएं हैं। स्वाद की दृष्टि से आंसू पसीने की मानिंद खारे और नमकीन होते हैं। जो पसीने का स्वाद जानता है, वह आंसुओं का स्वाद भी जानता ही है। लंबे समय तक रोते रहने वालों की आंखें सूजती तो हैं ही, उनकी पलकों के बाहर आसपास सफेद परत भी जम जाती हैं। यों आंसू जरूरी भी हैं। कम से कम आंखें साफ और उजली हो जाती हैं। कुछ लोग यह भी करते हैं कि रोने से फेफड़ों की कसरत हो जाती है।

रोने से दिल हल्का होता है, दिमाग का भारीपन दूर होता है और मनुष्य सामान्य हो जाता है। दूसरों के साथ बांटने से निजी भारीपन तो दूर होता ही है, व्यक्ति की सामाजिक चेतना का भी विस्तार होता है। आंसुओं की भी अपनी दुनिया है। जिस व्यक्ति का दिल जितना कोमल होता है, वह उतना ही ज्यादा रोता है। वह बेहिचक सार्वजनिक रूप से अपनी संवेदना प्रकट करता है। वह यह नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे। मैंने बड़े बड़े अफसरों, नेताओं, कलाकारों और विद्वानों को विभिन्न मौकों पर सार्वजनिक रूप से रोते हुए देखा है।

आंसुओं की क्षमता असीमित है। एक आंसू बहुत कुछ क्या, सब कुछ कह देने की क्षमता रखता है। बस समझ की गहराई और संवेदनशीलता चाहिए। किसी शायर ने कहा भी है- 'एक आंसू कह गया सब हाल दिल का, मैं समझा था ये जालिम बेजुबां है।' जो कुछ रोकर आंसुओं के माध्यम से कहा जा सकता है वह अच्छे से अच्छा वक्ता घंटों बोल कर भी नहीं बता सकता।

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

बिगड़ती सेहत

भारत में स्वास्थ्य पर कुल व्यय अनुमानित जीडीपी का 5.2 फीसद है। जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय पर निवेश केवल 0.9 फीसद है। यह रकम गरीबों और जरूरतमंद लोगों के लिए कहीं से भी पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। जबकि ऐसे जरूरतमंदों की तादाद कुल आबादी की करीब तीन चौथाई है। सार्वजनिक स्वास्थ्य बजट का बड़ा हिस्सा परिवार कल्याण पर खर्च होता है। भारत की पचहत्तर फीसद आबादी गांवों में रहती है। फिर भी कुल स्वास्थ्य बजट का केवल दस फीसद हिस्सा ही इस क्षेत्र को दिया जाता है। देश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। ज्यादातर सरकारी अस्पतालों की हालत दयनीय है। संक्रामक रोगों से ग्रस्त मरीज भी अस्पताल के बाहर खुले और गंदे में रहने को मजबूर है। भारत में स्वास्थ्य पर निजी खर्च अठहत्तर फीसद के लगभग है। इसका अर्थ यह हुआ कि मात्र बाईस फीसद चिकित्सा खर्च ही सरकार के खाता में आता है। हमारे यहां स्वास्थ्य पर लोगों का निजी खर्च भी दुनिया भर में सबसे अधिक है। अगर देश के हर नागरिक तक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुंचाना है तो सरकार को यह जिम्मेदारी लेनी होगी और इसके लिए खर्च की व्यवस्था कर-ढांचे से ही करे। राजनीति से ऊपर उठ कर सरकारें अगर चाहे तो आम आदमी की सेहत सुधार सकती है। इसके लिए सिर्फ इच्छाशक्ति चाहिए।

● *अजीत कुमार गौतम, गोरखपुर*

साफ है सरकार का रुख

यह सही है जब महाराजा हरी सिंह कश्मीर के शासक थे, तब पाकिस्तानी कबाइलियों ने अचानक हमला करके कश्मीर का कुछ हिस्सा कब्जा कर लिया था। तभी से पाकिस्तान उसे अपना बताता आ रहा है। यह अच्छी बात है कि केंद्र सरकार ने पीओके के संबंध में संसद में अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। पाक अधिकृत कश्मीर न केवल भारत का है बल्कि वहां के लोग गुलाम कश्मीर को भारत में शामिल करने के पक्ष में भी आ रहे हैं। पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार होते रहते हैं। इसकी वजह वहां होने वाला नागरिकों का शोषण और दमन है। गिलगित और बलूचिस्तान पर पाकिस्तान ने 17 मार्च 1947 को सेना के बूते कब्जा कर लिया था। तभी से वहां राजनीति अधिकारों की मांग करने वालों का दमन किया जा रहा है।

● *रितेश उपाध्याय, संत कबीर नगर*

साहसिक कदम

अनुच्छेद 370 को संशोधित कर केंद्र सरकार ने एक साहसिक कदम उठाया है जो वाकई सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति को दर्शाता है। हालांकि इस प्रक्रिया की संवैधानिकता और वैधता पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। परंतु विपक्ष को यह भूलना नहीं चाहिए कि ऐसे संवेदननशील राष्ट्रीय मुद्दे का विरोध उनका ही घर जला देता है।

कश्मीर का नागरिक अपने को भारतीय मानता है या नहीं, मुद्दा बस इतना ही है। कश्मीरी अगर कश्मीरियत को भारतीय पहचान के ऊपर रखते हैं तो इन कदमों का कोई मतलब नहीं रह जाता। राष्ट्रीयता किसी में पैदा नहीं कराई जाती बल्कि ये तो स्वतस्फूर्त होती है। सरकार को चाहिए कि कश्मीरी लोगों से खुल कर संवाद करे और उनका भरोसा जीते। धीरे-धीरे ही सही, यदि सार्थक प्रयास किए जाएं तो अवश्य ही भारतीयता की भावना ही कश्मीर समस्या का अंतिम समाधान है। संवाद और नागरिक स्वंतत्रता तत्काल बहाल नहीं हुई तो विभाजनकारी शक्तियां क्षेत्रवाद के नाम पर पुनः हिंसा भड़काने में संकोच नहीं करेंगी।

● *अनूप जैन, दिल्ली विवि*

आदिवासियों का भला

आदिवासी समाज भारतीय समाज का अभिन्न हिस्सा है और इसी ने प्राचीन संस्कृति, संस्कारों और परंपराओं को जीवित भी रखा है। ग्रामीण हाट बाजारों की रौनक इन्हीं से होती है। निमाड़ क्षेत्र के सारे व्यापार अधिकतर इसी समाज से जुड़े हुए हैं। आज बढ़ती आधुनिकता में इस समाज के लिए आवश्यकता है प्राचीन पंरपरा, संस्कृति और वेशभूषा के संरक्षण की। आदिवासियों की दशा सुधारने के दावे तो बहुत किए जाते हैं लेकिन होता कुछ नहीं दिखता। वर्तमान में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा शत्रु शराब है, जिसके कारण असमय ही लाखों परिवार दरिद्रता के गाल में समा जाते हैं, अधिकतर नौजवान युवा नशे की वजह से ही सड़क हादसों शिकार हुए है। आवश्यक है पारंपरिक ताड़ी को उपयोग में लाकर शराब पर प्रतिबंध लगाया जाए।

● *मंगलेश सोनी, मनावर (धार)*

साइबर ठगी का जाल

इस साइबर युग में चाहे लोगों को सौ से ज्यादा फायदे होंगे लेकिन साथ ही साइबर ठगी के संकट से भी जूझना पड़ रहा है। इंटरनेट पूरी तरह से सुरक्षित है और ये हमारी जानकारी किसी को नही देता, यह कहना अब पूरी तरह से झूठ साबित हो गया है। अगर ऐसा है तो कैसे लोगों के साथ इंटरनेट के माध्यम से ठगी और जालसाजी हो रही है। पंजाब में छह महीने में साइबर ठगी के पांच सौ से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। आपको भले ही पेटीएम या क्रेडिट कार्ड से लेनदेन करना आसान लगता होगा, पर यह दिनोंदिन खतरनाक साबित हो रहा है। हाल में पंजाब के मुख्यमंत्री की पत्नी के साथ साइबर ठगों ने तेईस लाख की ठगी कर ली। हालांकि यह मामला हाई प्रोफाईल था तो पुलिस जल्द हरकत में आ गई। लेकिन आन आदमी की शिकायत पर इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं होती। बहुत बार देखा गया है कि पुलिस बड़े लोगों के मामले जल्दी ही निपटा देती है परंतु हम आम लोगों को अपने ही पैसों के लिए पुलिस के पास न जाने कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं।

● *जानवी बिट्टल, जलंधर*

देश की 70 प्रमुख प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों के 2881 पद खाली

नई दिल्ली, 11 अगस्त (भाषा)।

देश की 70 प्रमुख प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों के 2881 पद रिक्त हैं। सरकार का कहना है कि जब भी कोई पद रिक्त होता है तब संबंधित प्रयोगशाला या संस्थान में वैज्ञानिकों के खाली पदों को भरने के लिए नियमों के अनुरूप कदम उठाए जाते हैं।

संसद के हाल में संपन्न सत्र के दौरान लोकसभा में राम चरण बेहरा ने देश के शीर्ष वैज्ञानिक संस्थानों में रिक्त पड़े वैज्ञानिकों के पदों का संस्थान वार ब्योरा मांगा था। उन्होंने पिछले पांच वर्षों में देश में महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने की पहल के बारे में भी जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया था कि देश की 70 प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों के 2881 पद रिक्त हैं। इसमें सीएसआइआर की पुणे स्थित राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों के 123 पद रिक्त हैं जबकि गोवा स्थित राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान में 100 पद, बंगलूर स्थित केंद्रीय चतुर्थ प्रतिमान संस्थान में 177, हैदराबाद स्थित भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान में 102 पद, कोलकाता स्थित भारतीय रसायन जीव विज्ञान संस्थान मे 77 पद, नई दिल्ली स्थित जीनोम एवं समेकित जीव विज्ञान संस्थान में 84 पद और जम्मू स्थित भारतीय समेकित चिकित्सा संस्थान में 95 पद रिक्त हैं। सीएसआइआर मुख्यालय में वैज्ञानिकों के 92 पद रिक्त हैं।

वैज्ञानिकों के पदों के रिक्त रहने की समस्या पर भौतिकीविद एवं कोलकाता विश्वविद्यालय के एप्लायड फिजिक्स संकाय के पूर्व व्याख्यता प्रो. सौरव पाल कहते हैं कि युवा नौकरी की तलाश में भाग रहे हैं, लेकिन शोध में आगे बढ़कर अपना भविष्य सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वे देश में वैज्ञानिक को रोल मॉडल नहीं बना पा रहे हैं। एक दौर था जब हम डॉ. अब्दुल कलाम और डॉ. सीवी रमन जैसे वैज्ञानिकों को देख शोध में आगे बढ़े थे। उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में इंस्पायर, इंप्रिट जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को जोड़ने का प्रयास कर रही है। इसके लिए साथ ही देश में हमें अपने रिसर्च ईको सिस्टम में सुधार करने की जरूरत है, तभी युवा आकर्षित होंगे।

मंत्री द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, सीएसआइआर के मैसूर स्थित केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिकों के 111 पद रिक्त हैं जबकि पिलानी स्थित केंद्रीय इलेक्ट्रानिक इंजीनियरिंग संस्थान में 92, लखनऊ स्थित केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान में 65, चेन्नई स्थित केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान में 50, नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान में 28, कोलकाता स्थित बोस संस्थान में 35, लखनऊ स्थित बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान में 25, बंगलूर स्थित भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान में 14 पद तथा मोहाली स्थित राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में वैज्ञानिकों के 92 पद रिक्त हैं। सीएसआइआर के रूड़की स्थित केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिकों के 50 पद तथा भोपाल स्थित उन्नत सामग्री एवं प्रसंस्करण अनुसंधान में 60 पद रिक्त हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में महिला वैज्ञानिक योजना के तहत 1800 से अधिक महिला वैज्ञानिकों एवं प्रौद्योगिकीविदों को सहायता प्रदान की गई है।

77 पद कोलकाता स्थित भारतीय रसायन जीव विज्ञान संस्थान में खाली हैं।

84 नई दिल्ली स्थित जीनोम एवं समेकित जीव विज्ञान संस्थान में खाली।

सवाल

- संसद के हाल में संपन्न सत्र के दौरान लोकसभा में राम चरण बेहरा ने देश के शीर्ष वैज्ञानिक संस्थानों में रिक्त पड़े वैज्ञानिकों के पदों का संस्थान वार ब्योरा मांगा था।
- उन्होंने पिछले पांच वर्षों में देश में महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने की पहल के बारे में भी जानकारी मांगी थी।

जवाब

- इसके जवाब में पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया था कि देश की 70 प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों के 2881 पद रिक्त हैं।
- इसमें बताया गया कि सीएसआइआर की पुणे स्थित राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों के 123 पद रिक्त हैं

अब नई तकनीक से सैनेटरी नैपकिन कचरे का निपटान

कोच्चि, 11 अगस्त (भाषा)।

हर साल देश में करीब 12 अरब सैनेटरी नैपकिन कचरे के रूप में लैंडफिल में समा रहे हैं और वैज्ञानिकों का कहना है कि यह कचरा पर्यावरण को एक गंभीर चुनौती है। इससे निपटने के लिए अब वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक विकसित की है, जिसके तहत सैनेटरी नैपकिन कचरे को आंशिक रूप से छांट कर उसका पर्यावरण अनुकूल तरीके से निपटान किया जाएगा।

महाराष्ट्र में स्थित 'पैडकेयर लैब्स' द्वारा विकसित इस तकनीक के तहत सैनेटरी नैपकिन कचरे को छांटकर उसका निपटान करने वाली मशीन का प्रोटोटाइप तैयार किया गया है लेकिन इसे अभी बाजार में पेश नहीं किया गया है। केरल सरकार की नई पहल 'केरल स्टार्टअप मिशन' के तहत पिछले दिनों कोच्चि में 'विमेन स्टार्टअप समिट 2019' का आयोजन किया गया। पैड केयर लैब्स (पीसीएल) द्वारा इसी सम्मेलन में इस तकनीक को पेश किया गया।

पीसीएल से जुड़े अंजिकिया धारिया ने बताया, नेशनल कैमिकल लैबोरेट्री के तहत पुणे में पैड केयर लैब्स को स्टार्टअप के तौर पर शुरू किया गया है और इस स्टार्टअप ने दुनिया की पहली ऐसी मशीन विकसित की है, जो सैनेटरी नैपकिन कचरे का पर्यावरण अनुकूल तरीके से कीटाणुशोधन करती है, उसे अलग करती है और उसका निपटान करती है। उन्होंने बताया कि इस मशीन से कचरा प्रबंधन की समस्या से छुटकारा पाया जा सकेगा। धारिया के अनुसार, 'देश भर के घरों में से एक साल में करीब 12 अरब सैनेटरी नैपकिन कचरे के रूप में लैंडफिल में जा रहे हैं। इन नैपकिन में जो प्लास्टिक इस्तेमाल की जाती है, वह प्राकृतिक तरीके से नष्ट नहीं होती, ऐसे में यह इसे इस्तेमाल करने वाली महिलाओं की सेहत के लिए ही एक बड़ा खतरा नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा है।'

> महाराष्ट्र में स्थित 'पैडकेयर लैब्स' द्वारा विकसित इस तकनीक के तहत सैनेटरी नैपकिन कचरे को छांटकर उसका निपटान करने वाली मशीन का प्रोटोटाइप तैयार किया गया है लेकिन इसे अभी बाजार में पेश नहीं किया गया है।

उन्होंने बताया, 'इससे पैदा हो रहे खतरे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये नैपकिन लैंडफिल में करीब 800 साल तक पड़े रहेंगे। ये ठोस कचरा श्रेणी में आते हैं और अगर इनका उचित निपटान नहीं किया जाए तो ये एचआइवी, एचबीवी तथा कई अन्य बीमारियों के वाहक बन सकते हैं।'

मैन्स्ट्रुअल हाईजीन एलायंस आफ इंडिया (एमएचएआइ) के अनुमान भारत में 33 करोड़ 60 लाख महिलाएं ऐसी हैं, जिन्हें माहवारी होती है और इनमें से 36 फीसद सैनेटरी नैपकिन का इस्तेमाल करती हैं। कुल 12 करोड़ 10 लाख महिलाएं सैनेटरी नैपकिन इस्तेमाल करती हैं।

बिजली चोरी करने वाले को 50 पेड़ लगाने का आदेश

नई दिल्ली, 11 अगस्त (भाषा)।

दिल्ली हाई कोर्ट ने बिजली चोरी के एक मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मुकदमे को बंद करने पर रजामंदी देते हुए उसे सामुदायिक सेवा के तौर पर 50 पेड़ लगाने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि पेड़ एक महीने के भीतर लगाए जाए और वह वन्य उपसंरक्षक (पश्चिम) को रिपोर्ट करें, जो उसे यहां केंद्रीय रिज रिजर्व वन, बुद्ध जयंती पार्क, वंदेमातरम मार्ग में 50 पेड़ लगाने का काम सौपेंगे।

न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने कहा, 'पौधे साढ़े तीन साल की आयु के पतझड़ वाली किस्म के होंगे और उनकी लंबाई कम से कम छह फुट होनी चाहिए। मिट्टी के प्रकार और भौगोलिक स्थिति के आधार पर डीसीएफ पौधरोपण के लिए उनके प्रकारों पर विचार करें।' अदालत ने व्यक्ति और डीसीएफ से उसके आदेश के अनुपालन पर एक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। उसने कहा कि डीसीएफ पेड़ लगाए जाने से पहले और उसके बाद की तस्वीरें लें और उसके हलफनामे के साथ दाखिल करें।

> न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने कहा, 'पौधे साढ़े तीन साल की आयु के पतझड़ वाली किस्म के होंगे और उनकी लंबाई कम से कम छह फुट होनी चाहिए।

अदालत ने व्यक्ति की उस याचिका पर यह आदेश दिया, जिसमें उसने बिजली चोरी के अपराध के लिए उसके खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती दी।

बिजली विभाग ने शिकायत दर्ज कराई थी कि व्यक्ति बिजली की चोरी करते हुए पाया गया। बिजली की एक तार उसकी दुकान के बाहर लगे सरकारी खंभे से सीधे जुड़ी हुई पाई गई। हाई कोर्ट ने व्यक्ति के खिलाफ आरोप तय करने वाले निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया और उसे बिजली कानून के तहत अपराध से मुक्त कर दिया। तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में देखते हुए और इस पर गौर करते हुए कि पक्षकारों ने अपने विवादों को सुलझा लिया है, अदालत ने कहा कि इस मामले का निपटारा कर दिया जाना चाहिए क्योंकि मुकदमा जारी रखने से कोई फलदायी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा।

बाढ़ में फंसे दो बच्चों को निकालने वाले कांस्टेबल की प्रशंसा

अमदाबाद, 11 अगस्त (भाषा)।

गुजरात में मोरबी जिले के कल्याणपुर गांव में आई बाढ़ के दौरान दो बच्चों को कंधे पर बैठाकर वहां से निकालने वाले एक पुलिस कांस्टेबल की मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत कई लोगों ने प्रशंसा की है। कांस्टेबल के इस बहादुरी भरे कार्य का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।

कांस्टेबल पृथ्वीराज सिंह जडेजा टंकारा पुलिस थाने में नियुक्त हैं। शनिवार को अन्य पुलिसकर्मियों के साथ वह कल्याणपुर गांव पहुंचे थे, जहां उन्हें पता चला था कि क्षेत्र में लगातार बारिश की वजह से गांव में आई बाढ़ में 17 बच्चों समेत 42 लोग फंसे हुए हैं।

पुलिसकर्मियों को जब पता चला कि पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है तो उन्होंने स्थानीय तैराकों और ग्रामीणों के साथ बचाव अभियान चलाया। वहां फंसे लोगों को निकालने के लिए उन्होंने अस्थायी नौका बनाई। हालांकि जडेजा ने वहां फंसे दो बच्चों को अपने कंधे पर बैठाकर ही वहां से सुरक्षित निकालने का फैसला किया।

पतंगसाजी

जम्मू में रविवार को स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए पतंगें बनाता युवक।

राजस्थान में भाजपा को जल्द मिल सकता है नया प्रदेशाध्यक्ष

जयपुर, 11 अगस्त (भाषा)।

राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को नया प्रदेशाध्यक्ष जल्द मिलने की संभावना है। पार्टी सूत्रों के अनुसार संसद का बजट सत्र समाप्त हो चुका है और अब केंद्रीय नेतृत्व इस पद पर नियुक्ति कर सकता है। इसी वर्ष 24 जून को मदन लाल सैनी के निधन के बाद से यह पद रिक्त है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार आगामी पंचायत एवं नगरपालिका चुनावों को देखते हुए पार्टी नए प्रदेशाध्यक्ष की घोषणा जल्द ही कर देगी। राज्य में दिसंबर में नगर निकायों एवं उसके बाद अगले साल शुरू में पंचायतों के चुनाव होने हैं।

स्थानीय मीडिया में भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष की पद की दौड़ में कई नाम सामने आ रहे हैं जिनमें सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, विधानसभा में प्रतिपक्ष उपनेता राजेंद्र राठौड़ तथा विधायक सतीश पूनिया, वासुदेव देवनानी व मदन दिलावर शामिल है। हालांकि पार्टी के स्थानीय नेता किसी भी तरह का कयास लगाने से बच रहे हैं। उनके अनुसार शीर्ष नेतृत्व यहां भी कुछ 'सरप्राइज' दे सकता है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने इस बारे में पूछे जाने पर कुछ दिन पहले कहा था, 'अभी तो हमारा सदस्यता पर ही जोर है। सदस्यता पूरी होने के बाद ही पार्टी का संविधान संगठन की चिंता करता है.. चुनाव भी बाद में ही होंगे।' उन्होंने कहा, 'सदस्यता अभियान के बाद सदस्यता सत्यापन आदि काम होगा। उसके बाद ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रदेश एवं जिला स्तर पर संगठनात्मक चुनाव उसके बाद ही होंगे।'

प्रदेश पार्टी पदाधिकारी प्रमोद वशिष्ठ ने बताया कि चुनाव के जरिए नियुक्ति पर प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल तीन साल के लिए होता है। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व द्वारा नियुक्ति किए जाने पर कार्यकाल की ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती। उल्लेखनीय है कि पार्टी के सदस्यता अभियान का पहला चरण 11 अगस्त को समाप्त हो रहा है। इसके बाद पार्टी सदस्यता सत्यापन का काम करेगी। वहीं राजधानी में पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी ने संगठनात्मक बदलाव की अटकलों के बारे में पूछे जाने पर मुस्कुराते हुए कहा, 'आप कुछ कयास लगा सकते हैं क्या?' याद रहे कि पिछले साल जब वसुंधरा राजे सत्ता में थीं, तो विधानसभा चुनाव से पहले अशोक परनामी द्वारा इस्तीफा दिए जाने के बाद यह पद लगभग ढाई महीने खाली रहा।

गोरखा समुदाय ने अनुच्छेद 370 पर सरकार के कदम का किया स्वागत

जम्मू, 11 अगस्त (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को रद्द किए जाने के बाद से जम्मू में रह रहे गोरखा समुदाय के लोगों को लगता है कि उन्हें अब स्थायी निवास प्रमाणपत्र मिलेगा, जिससे उनके बच्चे नौकरियों एवं पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकेंगे। उनके पूर्वज दशकों पहले डोगरा सेना के साथ मिल कर लड़ाई लड़ने के लिए नेपाल से जम्मू-कश्मीर आए थे। अब भी ज्यादातर परिवारों में कम से कम एक पूर्व सैनिक हैं, लेकिन उनका कहना है कि वे कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। गोरखा समुदाय के लोगों को विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनावों में वोट देने की इजाजत है जबकि वे तीन दशकों से स्थायी निवास प्रमाणपत्र, नामित किए जाने के जरिए विधानपरिषद में प्रतिनिधित्व, अनुसूचित जनजाति का दर्जा और अपने बच्चों के लिए सैनिक स्कूलों में पांच फीसद आरक्षण की मांग कर रहे हैं।

अगले साल अप्रैल में बहुमत के करीब होगा सत्तापक्ष

नई दिल्ली, 11 अगस्त (भाषा)।

केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा की अगुवाई वाले राजग को राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के कारण तमाम विधेयकों को पारित कराने में जो मशक्कत करनी पड़ रही है, उससे निजात पाने के लिए सत्तापक्ष को अगले साल अप्रैल में उच्च सदन की रिक्त हो रही 52 सीटों पर चुनाव का इंतजार है।

राज्यसभा

अगले साल दो एवं नौ अप्रैल को राज्यसभा में 15 राज्यों के 52 सदस्य सेवानिवृत्त होंगे। इनमें राजग के घटक दलों में 15 भाजपा, तीन जदयू और चार अन्नाद्रमुक के हैं। इसके अलावा राजग में शामिल नहीं होने के बावजूद सदन में सत्तापक्ष का साथ दे रहे बीजद के भी दो सदस्य इसी समय सेवानिवृत्त होंगे। वहीं, विपक्षी दलों में कांग्रेस के 13, तृणमूल कांग्रेस के चार और राकांपा के दो सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करेंगे।

गौरतलब है कि 245 सदस्यीय उच्च सदन में हाल ही में विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों के इस्तीफे के कारण आठ सीटें रिक्त हैं। भाजपा को रिक्त सीटों के लिए जल्द होने वाले उपचुनाव में भी पांच सीट जीतने का भरोसा है। इनमें उत्तर प्रदेश से सपा के तीन सदस्यों (नीरज शेखर, सुरेंद्र नागर और संजय सेठ) के इस्तीफे के बाद शेखर को भाजपा ने उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। समझा जाता है कि पिछले सप्ताह उच्च सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देने वाले असम से कांग्रेस के भुवनेश्वर कालिता और सपा छोड़ने वाले नेताओं को भी भाजपा उपचुनाव में उम्मीदवार बना सकती है। उच्च सदन में सपा के अब दस सदस्य बचे हैं।

राज्यसभा में भाजपा के सदस्यों की संख्या फिलहाल 78 है। सदन में बहुमत के लिए उसे 223 सदस्यों की जरूरत है। गत सप्ताह समाप्त हुए मानसून सत्र में 'तीन तलाक' और जम्मू- कश्मीर से जुड़े अहम विधेयकों पर सत्तापक्ष को बीजू जनता दल (बीजद), तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) और वाईएसआर कांग्रेस के प्रत्यक्ष समर्थन के अलावा सहयोगी जदयू, अन्नाद्रमुक तथा विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों की मतदान में अनुपस्थिति मददगार साबित हुई।

अप्रैल में रिक्त हो रही 52 सीटों में सर्वाधिक सात महाराष्ट्र, छह तमिलनाडु, पांच-पांच सीट पश्चिम बंगाल और बिहार, चार-चार सीट गुजरात और आंध्र प्रदेश तथा तीन-तीन सीट राजस्थान, ओड़ीशा और मध्य प्रदेश से शामिल हैं। इन राज्यों की विधानसभा में दलीय स्थिति को देखते हुए भाजपा, जदयू एवं बीजद को राज्यसभा में अपनी सीटें बरकरार रखने का भरोसा है। इसके इतर हरियाणा से खाली हो रही दोनों सीटों पर भाजपा की नजर है। इनमें अगले साल दो अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे इनेलो के राम कुमार कश्यप पहले ही भाजपा में शामिल हो चुके हैं जबकि विधानसभा में बहुमत को देखते हुए भाजपा, कांग्रेस की कुमारी शैलजा की रिक्त हो रही सीट अपनी झोली में डालने की कोशिश करेगी।

उधर, पश्चिम बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस का बहुमत होने के कारण पार्टी को राज्यसभा में रिक्त हो रही अपनी चारों सीटें बरकरार रखने का भरोसा है जबकि भाजपा, निर्दलीय सदस्य रीताब्रता बनर्जी की सीट वामदलों के पास जाने से रोकने की कोशिश करेगी। इसी प्रकार तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक को रिक्त हो रही अपनी चार और द्रमुक को एक सीट पर कब्जा बरकरार रखने का भरोसा है। दोनों दलों की नजर माकपा की रिक्त हो रही एक सीट (टीके रंगराजन) पर टिकी होगी। भाजपा को महाराष्ट्र, बिहार सहित कई अन्य राज्यों से भी बढ़त मिलने की उम्मीद है।

राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के कारण तमाम विधेयकों को पारित कराने में जो मशक्कत करनी पड़ रही है, उससे निजात पाने के लिए सत्तापक्ष को अगले साल अप्रैल में उच्च सदन की रिक्त हो रही 52 सीटों पर चुनाव का इंतजार है। इसके बाद उन्हें बहुमत मिलने की पूरी उम्मीद है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस का बहुमत होने के कारण पार्टी को राज्यसभा में रिक्त हो रही अपनी चारों सीटें बरकरार रखने का भरोसा है जबकि भाजपा, निर्दलीय सदस्य रीताब्रता बनर्जी की सीट वामदलों के पास जाने से रोकने की कोशिश करेगी।

15 राज्यों के 52 सदस्य अगले साल दो एवं नौ अप्रैल को राज्यसभा से सेवानिवृत्त होंगे।

15 भाजपा, तीन जदयू और चार अन्नाद्रमुक (राजग) के सांसद इसमें शामिल हैं।

13 कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस के चार और राकांपा के दो सदस्य भी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे।

सेनाध्यक्ष को एक लाख राखियां सौंपी छात्राओं ने

नई दिल्ली, 11 अगस्त (भाषा)।

स्कूल छात्राओं ने भारत के सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत को एक लाख हस्तनिर्मित राखियां भेंट कीं जो सियाचिन, जैसलमेर, नाथुला जैसे सीमांत क्षेत्रों पर तैनात जवानों के लिए भेजी जाएंगी। इन राखियों को तमिलनाडु, करूर के भरनी विद्यालय और देहरादून के आर्यन स्कूल की छात्राओं द्वारा बनाया गया। उत्तराखंड के पूर्व सांसद तरुण विजय की ओर से इस संबंध में जानकारी दी गई।

> सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने इस पहल का स्वागत किया।

सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने इस पहल का तहे दिल से स्वागत किया और कहा कि बच्चों द्वारा बनाई राखियां जवानों का मनोबल बढ़ाएंगी। यह राखियां तमिलनाडु से दिल्ली तक एअर इंडिया की ओर से निशुल्क लाई गईं। 'जवानों के लिए राखियां' अभियान उत्तराखंड के पूर्व सांसद तरुण विजय द्वारा दो वर्ष पहले शुरू किया गया था और डोकलाम, नाथुला घटनाक्रम के समय भी 50 हजार राखियां भेजी गईं थीं। तरुण विजय ने कहा कि अगले वर्ष वे थल सेना, वायु सेना और नौसेना के लिए पांच लाख राखियां देश भर से बनवाकर भेजने का लक्ष्य रखते हैं।

राहुल गए लेकिन कुर्सी पर जमी रहेगी उनकी युवा टीम

राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी संगठन में अगले कुछ महीनों तक बदलाव के आसार नहीं

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

लोकसभा की चुनावी हार के मद्देनजर कांग्रेस अध्यक्ष पद से राहुल गांधी की विदाई के बावजूद उनकी अगुआई में कायम हुई पार्टी के युवा नेताओं की टीम में फिलहाल किसी तब्दीली के आसार नहीं हैं। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के खास सिपहसलार समझे जाने वाले तमाम नौजवान नेता राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक अपनी-अपनी कुर्सियों पर जमे रहेंगे और अनुभवी नेताओं संग पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस कार्यसमिति की शनिवार देर रात हुई बैठक से पहले देश के तमाम प्रमुख पार्टी नेताओं ने एक स्वर में यह बात कह दी कि किसी भी सूरत में राहुल गांधी का इस्तीफा नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब प्रियंका गांधी अथवा सोनिया गांधी पार्टी की कमान संभालें। उसके बाद ही पी चिदंबरम ने सोनिया गांधी से पार्टी की कमान संभालने का आग्रह किया जिसका तमाम नेताओं ने समर्थन किया। बताते हैं कि इसके बाद सोनिया व प्रियंका थोड़ी देर के लिए कार्यसमिति की बैठक से बाहर चले गए और थोड़ी देर में वापस आकर सोनिया ने नई जिम्मेदारी संभालने पर अपनी सहमति दी।

सूत्रों ने बताया कि सोनिया गांधी के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पार्टी में हो रहे बिखराव को रोकना और नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए माहौल तैयार करना है। कहा तो यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी के इस प्रकरण के बाद यह भी स्पष्ट हो गया है कि संकट की इस घड़ी में पार्टी के तमाम नेता यह मानकर चल रहे हैं कि गांधी परिवार के पीछे हट जाने पर कांग्रेस में बिखराव को रोक पाना आसान नहीं होगा। ऐसे में चुनाव होने की सूरत में भी इसी परिवार के किसी सदस्य को नेतृत्व की जिम्मेदारी मिलने वाली है।

राहुल गांधी दिसंबर, 2017 में गुजरात चुनाव के समय कांग्रेस अध्यक्ष बने। गुजरात विधानसभा का चुनाव कांग्रेस भले ही मामूली अंतर से हार गई, लेकिन कई सियासी जानकारों ने गांधी के नेतृत्व और पार्टी की चुनावी रणनीति की तारीफ की। हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी आदि युवा नेताओं को जोड़कर उन्होंने गुजरात में पार्टी को एक मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया। इसी प्रकार राजस्थान में सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उन्होंने जो प्रयोग किया वह सफल साबित हुआ। कांग्रेस सूबे में अपनी सरकार कायम करने में सफल रही। इसी प्रकार मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में उनकी युवा टीम की मेहनत रंग लाई।

राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई लेकिन पार्टी वहां भी अपनी गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब रही। 2018 के आखिर में हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत ने उनके नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं का विश्वास बढ़ाने का काम किया। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया हों अथवा यूपी में जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, राज बब्बर आदि नेता हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले रणदीप सुरजेवाला या सूबे के कांग्रेसी मुखिया अशोक तंवर हों, दीपेंद्र हुड्डा हों या कुलदीप बिश्नोई हों तमाम नेताओं ने अपने अपने स्तर पर बेहतरीन काम किया। यह दीगर बात है कि राहुल गांधी की अगुआई में कांग्रेस 2019 का चुनाव नहीं जीत पाई। वह 100 सीटों के आंकड़े के आसपास तक नहीं पहुंच पाई। वह 2014 के अपने 44 सीटों के आंकड़ों में महज कुछ सीटों की बढ़ोतरी कर पाई और उसे 52 सीटें मिलीं।

राहुल गांधी का कहना है कि वे अध्यक्ष पद पर नहीं होने के बावजूद पार्टी की मजबूती के लिए काम करते रहेंगे। समझा जा रहा है कि उनकी युवा टीम भी उनकी ही तरह पार्टी को आगे बढ़ाने में जुटी रहेगी।

भारत ने अपनी ओर से रोकी समझौता एक्सप्रेस

पेज 1 का बाकी

अधिकारियों के मुताबिक, 'पाकिस्तान द्वारा लाहौर से अटारी के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस को रद्द करने के फैसले को देखते हुए भारत ने दिल्ली और अटारी के बीच चलने वाली समझौता लिंक एक्सप्रेस ट्रेन को रद्द कर दिया है।'

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने कहा, 'लाहौर और अटारी के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस 14607/14608 को रद्द किए जाने के पाकिस्तान के फैसले के परिणामस्वरूप दिल्ली से अटारी के बीच चलने वाली लिंक एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 14001/14002 भी रद्द की जाती है।' अधिकारियों ने बताया कि रविवार की सेवा के लिए दो यात्रियों ने टिकट बुक कराए थे। यात्रियों को किराए की रकम लौटाई जाएगी। जिन्होंने पहले से टिकट बुक करा रखे हैं, उन सबको पूरा रिफंड मिलेगा। अधिकारियों ने बताया कि रविवार की सेवा के लिए दो यात्रियों ने टिकट बुक कराए थे।

जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लेने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के सरकार के फैसले के बाद दोनों पड़ोसी देशों में तनाव बढ़ने के बीच पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन बंद कर दिया था। सबसे पहले पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस ट्रेन को स्थाई तौर पर रोक दिया था। उसने यह ट्रेन वाघा बॉर्डर पर लाकर छोड़ दी थी, जिसके बाद भारत ने अपने ड्राइवर और गार्ड को भेजा जो उसे भारतीय सीमा में लेकर आए थे।

पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख राशिद अहमद ने आठ अगस्त को इस्लामाबाद में एलान किया था कि रेल मंत्रालय ने समझौता एक्सप्रेस को स्थाई रूप से बंद करने का फैसला लिया है। पाकिस्तान ने यह फैसला जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के कई प्रावधानों को खत्म करने के विरोध में किया था। इसके अगले ही दिन पाकिस्तान ने जोधपुर-कराची के बीच चलने वाली थार एक्सप्रेस को बंद करने का एलान किया था।

मेट्रो कर्मचारी ने फेसबुक पर लाइव आकर की आत्महत्या

पेज 1 का बाकी

अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना का रहने वाला शुभांकर मकान नंबर-172, तेली वारा, शाहदरा में रह रहा था। शुभांकर ने दो माह पहले ही यह किराए का कमरा लिया था। सुबह करीब 9 बजे पुलिस को सूर्यकांत दास ने फोन कर जानकारी दी कि उसके एक दोस्त ने फोन कर बताया कि शुभांकर ने फेसबुक लाइव कर आत्महत्या कर ली है। मौके पर पुलिस की टीम दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई और शुभांकर को पास के अस्पताल में लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

अधिकारी ने बताया कि घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पर वह मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है, जिससे आत्महत्या का पूरा घटनाक्रम दिखाया गया था। सूर्यकांत ने अपने बयान में कहा है कि आकाश नामक एक अन्य दोस्त ने सुबह आठ बजे फेसबुक लाइव पर शुभांकर को आत्महत्या करते हुए देखा था। पुलिस को पता चला कि शुभांकर दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) में मेंटेनर के पद पर काम करता था।

रुपए में चवन्नी भी नहीं रह गई डाक टिकटों की बिक्री

पेज 1 का बाकी

के साधनों का इस्तेमाल किस तरह करते हैं?' उन्होंने कहा, 'अक्सर देखा गया है कि सोशल मीडिया के कई उपयोगकर्ता किसी पोस्ट पर खासकर नकारात्मक प्रतिक्रिया देने में बड़ी जल्दबाजी करते हैं। यह अधीरता उनके लिए बाद में तनाव और भावनात्मक उथल-पुथल का सबब बन जाती है, क्योंकि हर बात पर फौरन प्रतिक्रिया देने की आदत से मानवीय रिश्ते प्रभावित हो रहे हैं।'

गौरतलब है कि डाक टिकटों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए डाक विभाग 'माय स्टाम्प' योजना चला रहा है।
'माय स्टाम्प' निजी पसंद पर आधारित (पर्सनलाइज्ड) डाक टिकटों की शीट है। इस योजना के जरिए ग्राहक निर्धारित शुल्क चुकाकर डाक टिकट पर अपनी या अपने प्रियजन की तस्वीर अथवा धरोहर भवनों, उनके प्रतीक चिह्नों आदि की फोटो छपवा सकते हैं।

पाक में उच्चायुक्त बिसारिया लौटे

पेज 1 का बाकी

के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को निरस्त किए जाने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने राजनयिक संबंधों के स्तर को घटाते हुए बिसारिया को निष्कासित कर दिया था।

बिसारिया शनिवार को इस्लामाबाद से रवाना हुए और दुबई के रास्ते देश लौटे। पाकिस्तान ने बुधवार को ही बिसारिया को निष्कासित कर दिया था।

विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, बिसारिया दिल्ली वापस आ गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने राजनयिक संबंधों के स्तर को घटाने के फैसले पर फिर विचार करने के भारत के आग्रह को अनसुना कर दिया।

पाकिस्तान यह स्पष्ट कर चुका है कि वह अपने नवनियुक्त उच्चायुक्त मोइन उल हक को नई दिल्ली नहीं भेजेगा। पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त सोहेल महमूद को विदेश सचिव बनाए जाने के तीन महीने बाद हक की नियुक्ति की गई।

सीबीएसई : कक्षा 10 और 12 का परीक्षा शुल्क दोगुना

पेज 1 का बाकी

कार्य करता है। उन्होंने बताया कि पिछले साल तक सीबीएसई कई प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करता था जिनमें इंजीनियरिंग के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई-मेंस), मेडिकल के लिए राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) आदि करता था। इससे मिलने वाले धन से बोर्ड परीक्षाओं के उम्मीदवारों को कुछ आर्थिक सहायता दी जाती थी। अब इन परीक्षाओं का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी (एनटीए) करता है।

डॉक्टर भारद्वाज ने बताया कि बोर्ड परीक्षा प्रक्रिया बहुत विस्तृत प्रक्रिया है जिसमें काफी धन खर्च होता है। उनके मुताबिक बोर्ड के पास परीक्षा शुल्क व मान्यता शुल्क के अलावा और कोई कमाई का जरिया नहीं है। इसी वजह से हमें परीक्षा शुल्क में यह बढ़ोतरी करनी पड़ी है। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि सीबीएसई अन्य किसी भी बोर्ड के मुकाबले कम परीक्षा शुल्क लेता है।

सीबीएसई की ओर से सौ फीसद दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को परीक्षा शुल्क पहले से मिलने वाली छूट जारी रहेगी। जो विद्यार्थी अंतिम तारीख से पहले नई दर के अनुसार शुल्क जमा नहीं करेंगे उनका पंजीकरण नहीं होगा और उन्हें 2019-20 की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। स्थानांतरण शुल्क (माइग्रेशन फीस) भी 150 रुपए से बढ़ाकर 350 रुपए कर दिया गया है। विदेश स्थित सीबीएसई के स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को अब पांच विषयों के बोर्ड परीक्षा शुल्क के रूप में 10 हजार रुपए देने होंगे। पहले यह राशि पांच हजार रुपए थी। 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अतिरिक्त विषय के लिए इस श्रेणी के विद्यार्थियों को अब 1000 रुपए के बजाय 2000 रुपए का शुल्क देना होगा।

दिल्ली के एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए शुल्क 24 गुना बढ़ा

सीबीएसई ने दिल्ली के अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) विद्यार्थियों के लिए 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा शुल्क में 24 गुना वृद्धि की है। अब इस वर्ग के विद्यार्थियों को 50 के बजाय 1200 रुपए का शुल्क देना होगा। बोर्ड परीक्षा में अतिरिक्त विषय के लिए दिल्ली एससी/एसटी विद्यार्थियों को 300 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। पहले अतिरिक्त विषय के लिए इन वर्गों के विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता था।

पंजीकरण शुल्क भी दो गुना हुआ

10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को नौवीं कक्षा में और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए 11वीं कक्षा में पंजीकरण करना होता है। सीबीएसई ने पिछले हफ्ते फीस वृद्धि की अधिसूचना जारी की। इसके मुताबिक अब पंजीकरण शुल्क के रूप में सभी विद्यार्थियों को 300 रुपए का भुगतान करना होगा। पहले पंजीकरण शुल्क 150 रुपए था। जिन स्कूलों ने पुरानी व्यवस्था के तहत पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है, उन्हें विद्यार्थियों से फीस का अंतर वसूलने को कहा। पंद्रह अक्तूबर के बाद पंजीकरण के लिए 2000 रुपए विलंब शुल्क भी देना होगा।

370 हटने से खत्म होगा आतंकवाद : शाह

पेज 1 का बाकी

कोच पी गोपीचंद की टिप्पणी का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना बनाने के मुद्दे के दौरान संसद में हंगामेदार दृश्यों के बारे में कहा। शाह ने कहा कि लोगों की स्मृति में अभी भी उसकी यादें ताजा है । उन्होंने कहा, ''मुझे थोड़ी आशंका थी कि कहीं मैं भी तो नहीं इस तरह के हंगामेदार दृश्यों का हिस्सा हो जाऊंगा।'

उन्होंने नायडू के छात्र जीवन के समय की राजनीति और कश्मीर के संबंध में पार्टी की विचाराधारा को उनके समर्थन को भी याद करते हुए कहा कि एक बार एक साम्यवादी प्रोफेसर ने उपराष्ट्रपति से सवाल किया था कि वे ऐसे राज्य के लिए क्यों संघर्ष कर रहे हैं जिसे उन्होंने देखा ही नहीं। शाह ने कहा, 'इस पर नायडू ने जवाब दिया था कि एक आंख दूसरे आंख को भले देख नहीं सकती लेकिन उसका दर्द महसूस किया जा सकता है।

पाक में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा क्षतिग्रस्त

पेज 1 का बाकी

में तलवार लिए एक घोड़े पर बैठे दिखाई देते हैं। पुलिस ने इस मामले में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है और देश के ईशनिंदा कानून के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जम्मू-कश्मीर से विशेष दर्जा वापस लिए जाने को लेकर आरोपी दोनों व्यक्ति क्रोधित थे। संदिग्धों का संबंध कट्टरपंथी मौलवी मौलाना खादिम रिजवी के संगठन तहरीक-लब्बैक पाकिस्तान से है। लाहौर किले के मामलों के लिए जिम्मेदार 'द वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी' ने घटना पर हैरानी जताई और ईद के तुरंत बाद प्रतिमा की मरम्मत कराने की बात कही। उसकी प्रवक्ता तानिया कुरैशी ने कहा, 'यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम लाहौर किले में सुरक्षा बढ़ाएंगे ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो। प्रतिमा की मरम्मत का काम अगले सप्ताह किया जाएगा। एक बार मरम्मत होने के बाद इसे फिर से जनता के लिए खोल दिया जाएगा।

रतुल पुरी और उनके पिता का दिल्ली का बंगला, एफडीआइ राशि जब्त

पेज 1 का बाकी

रतुल पुरी के खिलाफ अगस्ता वेस्टलैंड सौदा मामले में एक गैरजमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया था। सीबीआइ के विशेष जज अरविंद कुमार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पुरी के खिलाफ एनबीडब्ल्यू के लिए दाखिल आवेदन को मंजूरी दे दी थी। अदालत ने हालांकि पुरी की तरफ से वकील विजय अग्रवाल की ओर से दाखिल पक्षकार बनाने के एक आवेदन को खारिज कर दिया था। अग्रवाल ने एनबीडब्ल्यू के आधार को चुनौती देते हुए एक अन्य आवेदन दाखिल किया। अदालत इस पर 13 अगस्त को विचार करेगी। रतुल पुरी अगस्तावेस्टलैंड सौदे में अपनी कंपनियों के माध्यम से कथित तौर पर रिश्वत लेने के आरोपों पर जांच के दायरे में हैं

कर्नाटक के बेलागावी में रविवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के ऊपर उड़ान भरता भारतीय वायु सेना का हेलिकॉप्टर।

सोनिया ने संभाली कमान, चुनावी राज्यों पर करेंगी मंथन

पेज 1 का बाकी

इन सभी राज्यों को लेकर फैसला लिया जाना है। ऐसे संकेत हैं कि पार्टी इस सप्ताह नए प्रदेश अध्यक्षों को लेकर निर्णय ले सकती है। हरियाणा के रोहतक में हुड्डा गुट की ओर से आगामी 18 अगस्त को रोहतक में होने वाली 'परिवर्तन रैली' बेहद अहम करार दी जा रही है। इसके माध्यम से हुड्डा पार्टी हाई कमान के सामने भी शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में बताए जा रहे २हैं। ऐसे में कोई ताज्जुब नहीं कि पार्टी इस प्रदेश को लेकर जल्दी फैसला कर ले।

पीओके में 150 आतंकियों के जुटने की खबर, सेना सतर्क

पेज 1 का बाकी

भारतीय सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। खुफिया इनपुट के मुताबिक लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और तालिबान के लगभग 150 आतंकी कोटली के निकट फागूश और कुंड शिविरों एवं मुजफ्फराबाद क्षेत्र में 'शवाई नल्लाह' और 'अब्दुल्ला बिन मसूद' शिविरों में इकट्ठे हुए हैं। जैश सरगना मसूद अजहर का भाई इब्राहिम भी पीओके में देखा गया है।

रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, इस समय घाटी में मौजूद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की है। बैठक में खुफिया ब्यूरो (आइबी) के निदेशक अरविंद कुमार, जम्मू एवं कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) दिलबाग सिंह और सेना के शीर्ष अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने इन सभी के साथ सुरक्षा रणनीति और आतंकी खतरे पर चर्चा की।

अनुराग ने बंद किया ट्विटर अकाउंट

पेज 1 का बाकी

हो जाएं और आपकी बेटी को ऑनलाइन धमकियां मिलने लगे तो फिर कोई भी बात नहीं करना चाहेगा। कोई वजह या कोई भी तर्क नहीं बचेगा। आवाज दबाने वाले शासन करेंगे और आवाज दबाना जीने का नया तरीका होगा। सबको यह नया भारत मुबारक हो और उम्मीद है कि आप सभी इसमें आगे बढ़ेंगे।' कश्यप ने लिखा, 'आपको खुशियां और तरक्की मिले। यह मेरा अंतिम ट्वीट है क्योंकि मैं ट्विटर छोड़ रहा हूं। जब मैं बिना डर के बोल नहीं सकता तो मैं बोलूंगा ही नहीं, गुड बाय।'

एनआरसी सेवा केंद्रों पर मुसलिमों की मदद कर रहे हैं हिंदू

गुवाहाटी, 11 अगस्त (भाषा)।

असम में इस महीने की शुरुआत में अहम नागरिक पंजीकरण (एनआरसी) पुनर्सत्यापन की सूचना मिलने के बाद से हजारों मुसलिम इसकी अंतिम समयसीमा खत्म होने से पहले एनआरसी प्रक्रिया को पूरा करने की जद्दोजहद में जुटे हैं, हालांकि इस काम में उन्हें हिंदुओं का भरपूर सहयोग मिल रहा है।

निचले असम के कामरूप, ग्वालपाड़ा और दक्षिण सलमारा जिलों के लोगों को तीन अगस्त को राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) का नोटिस मिला था और उन्हें 24-48 घंटे के भीतर 400 किलोमीटर दूर ऊपरी असम के शिवसागर, चराइदेव और गोलाघाट जिलों में स्थित एनआरसी सेवाकेंद्रों में उपस्थित होने के लिए कहा गया था।

पैसों की तंगी के कारण इतने कम समय में गरीब मुसलिमों का वहां पहुंच पाना मुश्किल था, ऐसे में उन्हें अपने सोने के जेवर या मवेशियों और फसलों को औने-पौने दाम में बेचना पड़ा।

जम्मू-कश्मीर में हालात शांतिपूर्ण, लोगों की मदद में जुटी सरकार

पेज 1 का बाकी

जरिए कश्मीरी लोग अपने रिश्तेदारों से ईद के मौके पर बातें कर सकेंगे। गृह मंत्रालय का कहना है कि अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाए जाने के बाद से घाटी में माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है।

ईद के मद्देनजर भोजन सामग्री की आपूर्ति दुरुस्त रहे, इसके लिए कश्मीर डिवीजन के अंतर्गत आने वाले 3,697 राशन घाटों में से 3,557 काम कर रहे हैं। गृह मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, सरकारी वाहनों के जरिए लोगों के घरों तक सब्जियां, एलपीजी, चिकन, अंडे आदि पहुंचाए जा रहे हैं। प्रशासन ने एक बयान जारी कर कहा, 'सरकार ने सभी जरूरी सामानों का स्टॉक जमा कर रखा है। सरकार के पास करीब 65 दिनों तक चलने भर का गेहूं, 55 दिनों तक चलने भर का चावल, 17 दिनों तक का मटन, एक महीने भर का चिकन, 35 दिन का केरोसिन तेल, एक महीने की एलपीजी और 28 दिन का पेट्रोल-डीजल का स्टॉक जमा है।'

अधिकारियों के मुताबिक, ईद के मद्देनजर करीब तीन सौ टेलिफोन बूथ बनाए गए हैं, जिसके जरिए आम लोग अपने रिश्तेदारों से बात कर सकेंगे। अलीगढ़ और अन्य जगहों पर दिल्ली में मौजूद रेजिडेंट कमिश्नर के जरिए लाइजन अधिकारी तैनात किए गए हैं, जो यहां रह रहे लोगों की कश्मीर घाटी में स्थित अपने परिवार से बात करवाने में मदद करेंगे। दूसरी तरफ, श्रीनगर स्थित सीआरपीएफ हेल्पलाइन ने रविवार को लोगों के लिए नया नंबर जारी किया। यह नंबर खासकर कश्मीर के उन लोगों के लिए है, जिन्हें अपने परिवार के लिए मदद चाहिए या जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म किए जाने के बाद जो मुश्किल में हैं। 'मददगार' हेल्पलाइन ने ट्विटर पर एक संदेश जारी करते हुए कहा कि लोग उसके मोबाइल नंबर 9469793260 पर किसी भी तरह के सहयोग या जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं। कश्मीर घाटी में कर्फ्यू के कारण इसका आधिकारिक नंबर 14111 काम नहीं कर रहा है।

कश्मीर के बाजारों में चहल-पहल की खबरें आ रही हैं। लोग बकरीद की खरीदारी कर रहे हैं। रियासी, रामबन और किश्तवाड़ जिलों में लोग खरीददारी में मशगूल हैं। श्रीनगर शहर में छह मंडियां बनाई गई हैं। इसके अलावा 2.5 लाख भेड़ें ईद-उल-अजहा के मौके पर कुर्बानी के लिए उपलब्ध कराई गई हैं।

राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राज्य के लोगों को ईद की मुबारकबाद दी है। राजभवन से जारी बयान के मुताबिक, राज्यपाल ने लोगों को ईद की मुबारकबाद देते हुए उनकी प्रगति की कामना की है। ईद के लिए कश्मीर में जो विशेष तैयारियां की गई हैं, उनका ब्योरा भी प्रशासन ने जारी किया है। कोषागार व बैंक इस अवधि के दौरान कार्य कर रहे हैं, यहां तक की छुट्टियों में भी। एटीएम ठीक से कार्य कर रहे हैं और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि नकदी नियमित आधार पर डाली जाए और लोग जरूरत के अनुसार नकदी निकाल रहे हैं।

हाजियों के सऊदी अरब से सुरक्षित व परेशानी मुक्त वापसी के लिए विशेष व व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिसके लिए उड़ानें 18 अगस्त से शुरू होंगी। सभी उपायुक्तों ने अपने नोडल अधिकारी नामित किए हैं, जो 18 अगस्त से हाजियों की सुविधा के लिए हवाईअड्डे पर तैनात होंगे। हाजियों की सुविधा के लिए हाजी हाउस व हवाईअड्डों पर स्पेशल हेल्पलाइन डेस्क की स्थापना की गई है।

उधर, केंद्र सरकार के एक आला अधिकारी ने कहा कि सोमवार को ईद-उल-अजहा के मौके पर कश्मीर में लोगों को मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाएगी। मोबाइल और लैंडलाइन फोन पर लगी रोक भी यथाशीघ्र हटा ली जाएगी। प्रशासन ने शुक्रवार को लोगों को स्थानीय मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाजत दी थी। हालांकि, घाटी में बड़ी संख्या में लोगों के एक स्थान पर जमा होने की इजाज/इत/इा नहीं दी गई।

गृह मंत्रालय के उच्च पदस्थ अधिकारियों के मुताबिक, कश्मीर में पिछले छह दिनों से एक भी गोली नहीं चली है। यह वहां सामान्य होते हालात का संकेत है। कश्मीर के आइजी एसपी पाणि ने भी कहा कि पिछले छह दिन में हमने एक भी गोली नहीं चलाई है। इस दौरान कुछ अंतरराष्ट्रीय मीडिया में इस तरह की खबरें चल रही हैं कि पुलिस ने घाटी में गोलीबारी की है, जो पूरी तरह गलत और भ्रामक हैं। घाटी में स्थिति शांत है, लोग सहयोग कर रहे हैं।

epaper.jansatta.com

हांगकांग में प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए

हांगकांग, 11 अगस्त (एपी)।

हांगकांग के दो हिस्सों में रविवार की दोपहर सड़कों पर उतरे लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने यातायात जाम कर दिया और अधिकारियों पर ईंटें फेंकी।

प्रदर्शनकारियों को शैम शुई पो क्षेत्र को छोड़ने की चेतावनी दी गई लेकिन उन्होंने इस चेतावनी की अनदेखी की। जिसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए। गैस मास्क पहने हुए प्रदर्शनकारी चेउंग शा वान में पुलिस स्टेशन के

बाहर एकत्र हो गए थे। हांगकांग में नौ सप्ताह से प्रदर्शन जारी हैं। गर्म मौसम और पुलिस की ओर से लगाई गई पाबंदी के बावजूद रविवार की दोपहर सैकड़ों प्रदर्शनकारी शहर के विक्टोरिया पार्क इलाके में इकट्ठा हुए।

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को विक्टोरिया पार्क में इकट्ठा होने की अनुमति दी है, लेकिन हांगकांग के पूर्वी हिस्से में मार्च निकालने का उनका अनुरोध ठुकरा दिया है। कई देश हांगकांग में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल इस्तेमाल करने का विरोध कर रहे हैं लेकिन चीन ने इन देशों की निंदा करनी शुरू कर दी है।

यरूशलम के धार्मिक स्थल पर इजराइली पुलिस और मुसलिमों के बीच संघर्ष, 14 घायल

यरूशलम, 11 अगस्त (एपी)।

यरूशलम के पवित्र स्थल के पास ईद-उल-अजहा की नमाज के दौरान मुसलिम नमाजियों और इजराइल की पुलिस के बीच रविवार को संघर्ष हो गया। फिलीस्तीन के चिकित्साकर्मियों ने बताया कि झड़प में कम से कम 14 लोग जख्मी हो गए जिनमें से एक की हालत गंभीर है। मुस्लिम इसे अल-अक्सा मस्जिद परिसर बताते हैं और यहूदी इसे टेंपल माउंट कहते हैं।

पुलिस ने बताया कि कम से कम चार अधिकारी घायल हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विवादित धर्म स्थल पर पिछले कुछ महीनों में पुलिस और नमाजियों के बीच हुए इसे भीषण संघर्ष के दौरान आंसू गैस के गोले छोड़े गए और ग्रेनेड की आवाज से यह स्थल दहल गया। यह झड़प इजराइल और फिलीस्तीन में तनाव बढ़ने के बीच हुई है। कुछ दिन पहले दक्षिण यरूशलम में एक इजराइली सैनिक के मारे जाने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। इजराइली सैनिकों ने गाजा सीमा बाड़ पार करने का प्रयास कर रहे चार फिलीस्तीनी आतंकवादियों को शनिवार को मार गिराया था।

पुलिस ने कहा कि हजारों मुस्लिम रविवार की सुबह नमाज के लिए यरूशलम पहुंचे। प्राचीन समय में इस स्थान पर मौजूद दो बाइबलिकल मंदिर तोड़े जाने के कारण यहूदी भी रविवार को शोक मना रहे हैं। यह यहूदियों के लिए सबसे पवित्र स्थल है और मुसलिमों के लिए तीसरा सबसे बड़ा पवित्र स्थान है। यह लंबे समय से इजराइल- फिलीस्तीन संघर्ष का केंद्र बिंदु रहा है। पवित्र स्थल के संरक्षक देश जोर्डन ने कहा कि उसने इजराइल को एक औपचारिक शिकायत भेजी है और इजराइल के गैर जिम्मेदाराना उकसावे की निंदा की है। जोर्डन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सुफियान अल कुदाह ने कहा कि अम्मान ने हिंसा के लिए पूरी तरह इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है।

रविवार तड़के बड़ी संख्या में फिलीस्तीनी परिसर के द्वार पर जमा हुए जब अफवाह फैल गई कि पुलिस यहूदी आगंतुकों को स्थल पर प्रवेश की इजाजत देगी। प्रदर्शनकारियों ने 'अल्लाहु अकबर' का उद्घोष किया और पुलिस पर पत्थर फेंके। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने परिसर में प्रवेश किया और स्टन ग्रेनेड व रबर कोटिंग वाली गोलियां दागीं। इजराइली पुलिस ने शुरुआत में यहूदी आगंतुकों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया था लेकिन संघर्ष होने के बाद उनका फैसला पलट दिया और उन्हें प्रवेश की अनुमति दे दी।

चीनी नेताओं के साथ वार्ता के लिए बेजिंग पहुंचे जयशंकर

बेजिंग, 11 अगस्त (भाषा)।

विदेश मंत्री एस जयशंकर चीनी नेतृत्व के साथ वार्ता के लिए तीन दिवसीय दौरे पर रविवार को बेजिंग पहुंचे। उनकी यात्रा के दौरान इस साल राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे के इंतजाम को अंतिम रूप देने सहित कई मुद्दों पर बातचीत होगी।

जयशंकर की यात्रा के दौरान चार सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद जयशंकर चीन का दौरा करने वाले पहले भारतीय मंत्री हैं। यह दौरा ऐसे वक्त भी हो रहा है, जब भारत ने जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करते हुए उसे दो केंद्रशासित क्षेत्रों में बांट दिया है। संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म करने के भारत के फैसले के बहुत पहले उनका दौरा तय हो चुका था। राजनयिक से विदेश मंत्री बने जयशंकर 2009 से 2013 तक चीन में भारत के राजदूत रहे थे। किसी भारतीय दूत का यह सबसे लंबा कार्यकाल था। चीनी नेतृत्व के साथ उनकी वार्ता की शुरुआत सोमवार को होगी। आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की गई है कि किन नेताओं के साथ उनकी बैठक होगी। वह चीनी स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री वांग यी के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। बाद में दोनों मंत्री सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संपर्क पर उच्च स्तरीय तंत्र की दूसरी बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। पहली बैठक पिछले साल नई दिल्ली में हुई थी। जयशंकर की यात्रा के दौरान चार सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। वांग के साथ उनकी वार्ता के दौरान राष्ट्रपति के इस साल दूसरी अनौपचारिक वार्ता के लिए दौरे के इंतजामों को अंतिम रूप देने के मुद्दे पर भी बातचीत होगी।

राजपक्षे ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए छोटे भाई के नाम का एलान किया

कोलंबो, 11 अगस्त (भाषा)।

श्रीलंका पोडुजना पेरामुना (एसएलपीपी) ने इस साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में पूर्व रक्षा मंत्री गोटाभया राजपक्षे के नाम की रविवार को घोषणा की। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के छोटे भाई गोटाभया (70) ने 2006 से 2009 के बीच लिट्टे के खिलाफ राजपक्षे के सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। राजपक्षे ने महीनों चली अटकलों पर विराम लगाते हुए रविवार को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए गोटाभया के नाम का एलान किया। ा उन्हें राजपक्षे परिवार की नई राजनीतिक पार्टी एसएलपीपी का नेतृत्व भी सौंपा गया। श्रीलंका में सितंबर के आखिर तक राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा करना और आठ दिसंबर से पहले चुनाव कराए जाना जरूरी है।

सऊदी अरब में ईद के जश्न का आगाज

मीना (सऊदी अरब), 11 अगस्त (एपी)।

सऊदी अरब में हजयात्रा के अंतिम चरण में शैतान को कंकड़ मारने की प्रथा में दुनिया भर से आए करीब 25 लाख हजयात्रियों ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही ईद-उल-अजहा के जश्न की शुरुआत हो गई। हज यात्रा सम्पन्न होने पर धार्मिक नवजागरण और पुनर्जन्म के प्रतीक के तौर पर पुरुषों ने अपने बाल मुड़वाए और महिलाओं ने बाल कटवाए।

यात्रा सम्पन्न होने पर पुरुष हजयात्री हज के दौरान पहने जाने वाले खास सफेद लिबास 'एहराम' की जगह अपने पुराने कपड़ों को पहन सकते हैं। मुसलिमों के लिए अपने जीवन में एक बार पांच दिन की हजयात्रा करना जरूरी होता है, अगर वे शारीरिक और आर्थिक रूप से इसे करने में सक्षम हैं। दुनिया भर में मुसलिम समुदाय के लोग हज के खत्म होने पर ईद का जश्न मनाते हैं। इसमें वे गरीबों को मांस भी बांटते हैं।

मीना में हज यात्रा के अंतिम चरण को पूरा करने के बाद मोहम्मद सालेह ने कहा, 'मैं सूडान से मक्का आया था, जहां मैंने हज की प्रथाओं में हिस्सा लिया।' मीना में हज के अंतिम चरण में हजयात्री शैतान के प्रतीकात्मक खंभे पर कंकड़ मारते हैं। सऊदी अरब ने कहा कि इस साल हज यात्रा के दौरान 160 से अधिक देशों से 18.5 लाख हजयात्री सऊदी अरब आए थे। सऊदी अरब से 6,34,000 लोगों ने हज यात्रा की जिनमें 70 फीसद यहां रहने वाले गैर सऊदी नागरिक थे। रविवार को शाह सलमान ने मीना की यात्रा कर वहां सुरक्षा इंतजामों और अन्य इंतजामों का जायजा लिया।

'नार्वे में मस्जिद में गोलीबारी आतंकी घटना की तरह'

ओस्लो, 11 अगस्त (एएफपी)।

नार्वे पुलिस ने रविवार को कहा कि ओस्लो में शनिवार को मस्जिद में हुई गोलीबारी को वह आतंकवादी घटना मान रही है, क्योंकि मामले का संदिग्ध घोर दक्षिणपंथी व अप्रवासी विरोधी दृष्टिकोण रखता है। इस बीच, पुलिस ने शनिवार शाम को बताया कि हमले के कुछ घंटों बाद बेइरम उपनगर में एक घर से संदिग्ध हमलावर की परिचित युवती का शव मिला। बेइरम में ही गोलीबारी हुई थी। जांचकर्ताओं ने युवती की मौत के संबंध में जांच शुरू कर दी है।

मस्जिद के इमाम इरफान मुश्ताक ने हमलावर को श्वेत युवक बताया जिसने काले कपड़े पहने हुए थे और उसने एक हेलमेट व बुलेटप्रूफ जैकेट भी पहन रखी थी। हमले के समय अल नूर इस्लामिक केंद्र में केवल तीन लोग ही मौजूद थे। मुश्ताक ने बताया कि बंदूकधारी को काबू करने वाले व्यक्ति की उम्र 75 वर्ष है और वह नमाज के बाद कुरान पढ़ रहा था।

अदन में हुई झड़पों में 40 मरे व 260 घायल

दुबई, 11 अगस्त (एएफपी)।

संयुक्त राष्ट्र ने रविवार को कहा कि यमन के दूसरे बड़े शहर अदन में सुरक्षा बलों और विद्रोहियों के बीच हुई झड़पों में 40 लोगों की मौत हुई है और 260 लोग घायल हैं।

संयुक्त राष्ट्र ने बयान में कहा कि अदन शहर में आठ अगस्त से शुरू हुई झड़पों में कई नागरिकों की मौत हो चुकी है। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक वहां 40 लोगों की मौत हुई है और 260 लोग घायल हैं।

भारतीय दूतावास, जॉर्ज वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में निशुल्क हिंदी कक्षाएं होंगी

वॉशिंगटन, 11 अगस्त (भाषा)।

अमेरिका में हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए यहां स्थित भारतीय दूतावास लोगों की मांग पर प्रतिष्ठित जॉर्ज वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए निशुल्क हिंदी की कक्षाएं संचालित करेगा। छह हफ्ते का गैर क्रेडिट हिंदी भाषा का परिचयात्मक पाठ्यक्रम 28 अगस्त से शुरू होगा।

साल के शुरुआत में दूतावास ने परिसर में एक घंटे की निशुल्क साप्ताहिक कक्षाएं संचालित की थीं। विश्वविद्यालय स्थित सिगुर सेंटर फॉर एशियन स्टडीज के निदेशक बेंजामिन डी हॉपकिंस और एसोसिएट निदेशक दीपा एम ओल्लापल्ली ने हाल में अमेरिका स्थित भारतीय राजदूत को लिखे पत्र में कहा था, 'यह इंगित करता है कि छात्रों में हिंदी भाषा पढ़ने के लिए भारी रुचि है।'

ईद मुबारक

यरूशलम में डोम ऑफ द रॉक के सामने ईद मनाते मुसलमान।

लीबिया में विस्फोट, संयुक्त राष्ट्र के तीन कर्मियों की मौत

बेनगाजी, 11 अगस्त (एपी)।

लीबिया के बेनगाजी शहर में शॉपिंग मॉल के बाहर विस्फोटकों से लदे एक वाहन में विस्फोट से संयुक्त राष्ट्र के कम से कम तीन कर्मियों की मौत हो गई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी।

देश में यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब युद्धरत पक्षों ने कहा था कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्तावित संघर्षविराम स्वीकार कर लिया है जिसका मकसद आगामी ईद-उल-अज़हा के मौके पर राजधानी त्रिपोली में हमले रोकना है। विस्फोट अरकान मॉल के पास हुआ जहां लोग ईद से पहले खरीदारी करने आए थे। बेनगाजी नगर निगम ने बताया कि हमला लीबिया में संयुक्त राष्ट्र सपोर्ट मिशन को निशाना बनाकर किया गया था। स्वास्थ्य अधिकारियों ने उनका नाम गोपनीय रखे जाने की शर्त पर बताया कि मृतकों में से एक लीबिया का नागरिक है। विस्फोट में नौ लोग घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतानियो गुतारेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने बयान में बताया कि घायलों में तीन संयुक्त राष्ट्र कर्मी हैं। उन्होंने कहा कि महासचिव शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हैं और सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।

चीन में चक्रवात से मरने वालों की संख्या हुई 33

बेजिंग, 11 अगस्त (भाषा)।

पूर्वी चीन के झेजियांग प्रांत में चक्रवात 'लेकिमा' से मरने वालों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है और 16 अन्य लापता हैं। चक्रवात के कारण पूरे क्षेत्र में हर ओर तबाही का मंजर है।

'लेकिमा' चक्रवात इस साल चीन में आया नौवां और सबसे शक्तिशाली चक्रवात है। शनिवार दोपहर को चक्रवात ने वेंलिंग शहर में दस्तक दी। इस दौरान 187 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं, और जोरदार बारिश हुई।

मरने वालों में अधिकतर योंगजिया काउंटी से हैं, जिसका प्रशासन वेनझोऊ सिटी देखता है। यहां मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन होने से नदी का मार्ग अवरुद्ध हो गया है। बैरियर झील उफान पर है, जिसके कारण आई बाढ़ में कई लोग बह गए।

राष्ट्रीय टेलीविजन 'सीजीटीएन' की खबर के अनुसार चक्रवात की चपेट में आने से 33 लोग मारे गए हैं और 16 लोग लापता हैं। सरकारी समाचार एजेंसी 'शिन्हुआ' ने प्रांतीय बाढ़ नियंत्रण मुख्यालय के हवाले से बताया कि करीब 10.8 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है और झेजियांग में रहने वाले करीब 50 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।

पाकिस्तान में बारिश से जुड़े हादसों में 28 मरे

कराची/पेशावर, 11 अगस्त (भाषा)।

पश्चिमोत्तर पाकिस्तान में मानसूनी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन की घटना में महिलाओं और बच्चों सहित 28 लोगों की मौत हुई है।

प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (पीडीएमए) के प्रवक्ता ने रविवार को बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के विभिन्न इलाकों में अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और बारिश संबंधी घटनाओं में कम से कम 12 लोगों की मौत हुई है जबकि 22 अन्य घायल हुए हैं। बाजौर और स्वात जिलों में तीन-तीन मौतें हुईं। एक-एक व्यक्ति की मौत निचला दीर, बुनेर,मालाकंद, शांग्ला, औरकजई और तोडघर जिलों में हुई। इनमें दो महिलाएं और दो बच्चे शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि चित्राल जिले में लवारी सुरंग का काम रहे चीनी इंजीनियरों की कॉलोनी अचानक आई बाढ़ में जलमग्न हो गई। हालांकि, इंजीनियरों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है।

वहीं ,कोहिस्तान जिले में कम से कम छह लोगों की मौत सिधु नदी में वाहन गिरने से हो गई। ये सभी गिलगित से निचला दीर जिला जा रहे थे। हादसा जांचल इलाके में हुआ। एक अधिकारी ने कहा कि कराची में शनिवार रात से से जारी मूसलाधार बारिश में दस लोगों की मौत हुई है और काफी नुकसान भी हुआ। पाकिस्तान के मौसम विभाग के अनुसार कराची में अब तक 150 मिमी बारिश दर्ज की गई है व रविवार रात को और बारिश होने की संभावना है।

किम की निगरानी में नए हथियार का परीक्षण : केसीएनए

सियोल, 11 अगस्त (एएफपी)।

उत्तर कोरिया की ओर से हाल में किए गए मिसाइल प्रक्षेपणों के बाद किम जोंग उन की व्यक्तिगत निगरानी में उनके देश ने एक और नए हथियार का परीक्षण किया है। देश के सरकारी मीडिया ने रविवार को यह जानकारी दी है।

उत्तर कोरिया ने यह परीक्षण ऐसे समय में किया है जब हाल में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि प्योंगयांग परमाणु निरस्त्रीरण पर वार्ता बहाल करना चाहता है। देश की आधिकारिक 'कोरियन सेंट्रल न्यूज एजंसी' (केसीएनए) ने शनिवार को किए गए प्रक्षेपण की जानकारी देते हुए यह नहीं बताया कि उत्तर कोरिया ने किस हथियार का परीक्षण किया। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में इसे परंपरागत हथियार विकसित करने के लिए किया गया परीक्षण बताया गया है। इससे पहले उत्तर कोरिया पिछले दो सप्ताह में चार बार मिसाइल प्रक्षेपण कर चुका है।

उत्तर कोरिया ने ये प्रक्षेपण अमेरिका-दक्षिण कोरिया युद्ध अभ्यास के विरोध में किए हैं। केसीएनए ने बताया कि किम ने परीक्षण को निर्देशित किया और उसकी निगरानी की है। किम ने परिणाम पर अत्यंत संतुष्टि जताई है।

सियोल में रक्षा अधिकारियों ने बताया कि हैमहंग के निकट शनिवार तड़के जिन प्रक्षेपास्त्रों का परीक्षण किया गया, वे छोटी दूरी की दो बैलिस्टिक मिसाइलें प्रतीत होती हैं जिन्होंने कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के बीच समुद्र में गिरने से पहले 400 किलोमीटर की दूरी तय की।

वार्ता आगे बढ़ने पर गनी ने विदेशी दखल को अस्वीकार किया

काबुल, 11 अगस्त (एपी)।

अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अपनी सरकार की भागीदारी के बगैर अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौता करीब होता देख रविवार को विदेशी दखल को अस्वीकार कर दिया।

राष्ट्रपति ने ईद उल-अजहा के पर्व पर रविवार को ऐसा कहा जब अमेरिका और तालिबान के वार्ताकार कतर में वार्ता में लगे हुए हैं। कतर में ही तालिबान का राजनीतिक कार्यालय है। गनी ने कहा कि अगले महीने होने जा रहा राष्ट्रपति चुनाव बेहद जरूरी है ताकि अफगानिस्तान के नेता के पास कई सालों की लड़ाई के बाद देश का भविष्य तय करने के लिए शक्तिशाली जनादेश होगा। उन्होंने कहा, 'हमारा भविष्य बाहर तय नहीं किया जा सकता है, चाहे वह हमारे मित्रों या पड़ोसियों का राजधानी शहर ही क्यों न हो। अफगानिस्तान की किस्मत का फैसला उसके घर में किया जाएगा। हम नहीं चाहते कि कोई हमारे मामले में दखल दे।' अमेरिकी राजदूत जलमय खलीलजाद चुनाव से हफ्तों पहले एक सितंबर तक शांति समझौता करना चाहते हैं। दोनों पक्षों के 20000 अमेरिकी और नाटो सैनिकों की वापसी पर राजी होने की संभावना है। बदले में तालिबान गारंटी देगा कि अफगानिस्तान अन्य चरमपंथी संगठनों का अड्डा नहीं होगा। वैसे कुछ जानकारियां सामने आई हैं लेकिन खलीलजाद और मुख्य तालिबान वार्ताकार मुल्ला अब्दुल गनी बरदार नवीनतम घटनाक्रम पर प्रक्रिया से संबद्ध देशों को अवगत कराने के लिए इन दिनों उन देशों की यात्रा कर रहे हैं। खलीलजाद ने ट्वीट किया, ' मैं आशा करता हूं कि यह आखिरी ईद है जब अफगानिस्तान में युद्ध की स्थिति होगी।' तालिबान ने अफगान सरकार के साथ वार्ता करने से इनकार करते हुए देश में 28 सितंबर को होने वाले चुनाव को दिखावा करार दिया था।

> हमारा भविष्य बाहर तय नहीं किया जा सकता है, चाहे वह हमारे मित्रों या पड़ोसियों का राजधानी शहर ही क्यों न हो।
>
> **अशरफ गनी**
> **अफगानिस्तान के राष्ट्रपति**

ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ देश के राजनीतिक वर्ग से निराश : रिपोर्ट

लंदन,11 अगस्त (भाषा)।

ब्रिटिश मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ठीक से शासन नहीं चला पाने की वजह से देश के राजनीतिक वर्ग से 'निराश' हैं।

93 वर्षीय महारानी को पारंपरिक रूप से सार्वजनिक तौर पर राजनीतिक मामलों में तटस्थ माना जाता है, लेकिन बताया जाता है कि उन्होंने जून, 2016 में ब्रेग्जिट पर जनमत संग्रह के बाद प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के इस्तीफे के बाद निजी कार्यक्रम में यह टिप्पणी की। 'द संडे टाइम्स' ने एक शाही सूत्र के हवाले से बताया कि उस घटना के बाद से ही महारानी की निराशा बढ़ी। अखबार ने इन सूत्र को 'निष्कलंक' करार दिया है।

सूत्र को उद्धृत करते हुए अखबार ने लिखा, 'मैं मानता हूं कि महारानी वास्तव में निराश हैं। मैंने उन्हें मौजूदा राजनीतिक वर्ग और उसकी सरकार चलाने में अक्षमता को लेकर उत्पन्न निराशा पर बात करते हुए सुना।' महारानी की राजनीति पर दुलर्भ बातचीत को सुनने का दावा करने वाले वरिष्ठ शाही सूत्र ने कहा, 'महारानी ने हमारे राजनीतिक नेतृत्व की गुणवत्ता पर नाराजगी और गुस्से का इजहार किया और यह निराशा बढ़ ही रही है।'

ऋषि कपूर ने किया अनुपम खेर की आत्मकथा का विमोचन

न्यूयॉर्क, 11 अगस्त (भाषा)।

अपने कॅरियर में करीब 500 फिल्में कर चुके 'पद्म भूषण' से सम्मानित अभिनेता अनुपम खेर की आत्मकथा का यहां न्यूयॉर्क में उनके मित्र व जाने-माने अभिनेता ऋषि, उनकी पत्नी नीतू कपूर और एनबीसी के कार्यक्रम 'न्यू एम्सटर्डम' के साथी कलाकारों ने विमोचन किया। खेर की आत्मकथा में उनकी नाकामियों, उन्हें नकारे जाने से लेकर अपने जीवन से मिले सबक का जिक्र है।

खेर की आत्मकथा 'लेसंस लाइफ टॉट मी, अननोविंगली' का शुक्रवार को न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास में आयोजित विशेष कार्यक्रम में विमोचन हुआ, जिसमें जाने माने अभिनेता के करीबी मित्रों और सहयोगियों ने हिस्सा लिया। किताब के विमोचन के दौरान वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए खेर ने कहा, 'मेरे जीवन में जो कुछ भी गलत हुआ, जो कुछ सही हुआ, यह आत्मकथा उसी का सार है।'

उन्होंने अपने जीवन की उन घटनाओं का जिक्र किया जिसने उनके कॅरियर को आकार दिया। खेर ने कहा कि यह आत्मकथा बेहद रोचक है क्योंकि इसमें उनकी सफलताओं के बारे में बात नहीं की गई है।

उन्होंने कहा, 'मेरे लिए सफलता बड़ी नीरस रही है, यह बिल्कुल एक आयामी होती है। नाकामी के कई आयाम होते हैं, यह बहुत अद्भुत चीज है। आज मैं जो कुछ भी हूं वह अपनी नाकामियों की वजह से ही हूं।' ऋषि न्यूयॉर्क में करीब एक साल से कैंसर का इलाज करा रहे हैं और खेर की किताब के विमोचन के दौरान इलाज के बाद पहली बार वह सार्वजनिक तौर पर नजर आए। पहले से बेहतर और स्वस्थ नजर आ रहे कपूर ने दर्शकों को बताया कि शुक्रवार को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। पत्नी नीतू कपूर के साथ आए कपूर ने कहा कि हालांकि वह खेर से कुछ साल बड़े हैं लेकिन उन दोनों ने साथ में जो पहली फिल्म की थी, वह यश चोपड़ा निर्देशित 1988 में आई 'विजय' थी, जिसमें खेर ने कपूर के दादा की भूमिका निभाई थी। कपूर ने कहा, 'कल को अभिनेता बनने के इच्छुक युवाओं के लिए यह अच्छी किताब है।' खेर ने भी किताब के विमोचन के लिए कपूर का आभार जताया।

विमोचन के दौरान 'न्यू एम्सटर्डम' के कलाकारों रेयान एगोल्ड, जेनेट मोंटगोमरी और डियर्डरे फ्रीएल और स्टार शेफ विकास खन्ना भी उपस्थित थे। खेर की किताब भारत में पांच अगस्त को जारी की गई और अमेरिका में यह 15 अक्टूबर को जारी की जाएगी। भारतीय महावाणिज्य दूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि अपने पूरे जीवन और कॅरियर में खेर ने खास अंदाज में लोगों के दिलों को छुआ है।

> खेर की आत्मकथा 'लेसंस लाइफ टॉट मी, अननोविंगली' का शुक्रवार को न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास में आयोजित विशेष कार्यक्रम में विमोचन हुआ, जिसमें जाने माने अभिनेता के करीबी मित्रों और सहयोगियों ने हिस्सा लिया।

सरकार अर्थव्यवस्था को गति देने के उपायों पर कर रही काम

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

सरकार अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए विभिन्न उपायों पर काम कर रही है। सरकार उन बिंदुओं पर गौर कर रही है जो आर्थिक वृद्धि की गति में रुकावट का कारण बन रहे हैं। इसके लिए उत्पादक क्षेत्रों को कोष की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने और सकल वृद्धि को प्रोत्साहन के उपाय किए जा रहे हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक जिस रणनीति पर काम हो रहा है उसमें जीएसटी दरों में कटौती का प्रस्ताव शामिल नहीं है। सरकार का मानना है कि कर दरें पहले से ही पूर्व के मुकाबले कम हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की उद्योग मंडलों, बैंकों, विदेशी व घरेलू निवेशकों समेत विभिन्न पक्षों के साथ बैठकों में मिली प्रतिक्रियाओं के आधार पर वित्त मंत्रालय इन उपायों को अंतिम रूप दे रहा है। पिछले कुछ दिनों में बैंक, एमएसएमई और वाहन समेत विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठकों में इन क्षेत्रों के लिए समस्या खड़ी कर रहे कुछ बिंदुओं को सामने रखा गया है।

वृद्धि को गति देने के लिए अड़चनों को जल्दी ही दूर किया जाएगा। इससे उद्योग जगत की विभिन्न साझा चिंताएं दूर होंगी। उद्योग जगत वृद्धि को गति देने के लिए उनके लिए कर्ज उपलब्धता सुनिश्चित करने, कर्ज लागत में कमी लाने और कुछ नीतियों को सरल बनाने पर जोर देता रहा है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए 7 फीसद वृद्धि का लक्ष्य रखा है और पहली तिमाही के आंकड़े इसी दिशा में हैं।

सूत्रों के मुताबिक सरकार जो कदम उठा रही है, उससे बजट में निर्धारित वृद्धि लक्ष्यों को हासिल करना मुश्किल नहीं है। वाहन उद्योग के जीएसटी में कटौती के बारे में सरकार का कहना है कि दरें पिछली कराधान व्यवस्था के मुकाबले कम हैं। ऐसे में कर दर में कटौती की गुंजाइश नहीं है। सरकार ने सामाजिक क्षेत्र की बाध्यताओं को पूरा करने व बुनियादी ढांचा विकास के लिए राजस्व लक्ष्य तय किए हैं। दरअसल, वाहन बिक्री में नरमी जीएसटी दर में कटौती के कारण नहीं बल्कि उद्योगों के चरणबद्ध तरीके से प्रदूषण के नवीनतम स्तर से संबंधित माडल पेश करने में प्रतिरोध है।

मासिक पेंशन योजना के लिए 15 अगस्त तक दो करोड़ किसानों को पंजीकृत करने का लक्ष्य

नई दिल्ली, 11 अगस्त (भाषा)।

साझा सेवा केंद्र (सीएससी) ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया ने प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पीएमकेएमवाइ) के तहत 15 अगस्त तक देशभर के दो करोड़ छोटे किसानों का पंजीकरण करने का लक्ष्य रखा है। सीएससी ई-गवर्नेंस सेवा देशभर में 3.5 लाख साझा सेवा केंद्रों का प्रबंधन करती है। पीएमकेएमवाइ की शुरुआत राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की थी। इस योजना के तहत पात्र किसानों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी।

सीएससी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश त्यागी ने रविवार को कहा कि मैंने सभी गांव स्तरीय उद्यमियों, जो भारत के गांवों में दो लाख से अधिक सीएससी चलाते हैं, हरेक को स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) तक कम से कम सौ छोटे किसानों को पंजीकृत करने को कहा है। हमारे सभी सीएससी स्वतंत्रता दिवस तक कम से कम दो करोड़ किसानों को पंजीकृत करने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता दिवस के दिन भी खुले रहेंगे। त्यागी ने कहा कि पंजीयन की प्रक्रिया बेहद आसान है। कोई भी किसान, जो योजना से जुड़ना चाहते हैं, अपने आधार कार्ड और बैंक पासबुक या बैंक खाते की जानकारी के साथ नजदीकी सीएससी जा सकता है। गांव स्तरीय उद्यमी, जो सीएससी का प्रबंधन करते हैं, किसान से सभी संबंधित दस्तावेज लेने के बाद ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया पूरी करेंगे।

कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय ने पीएमकेएमवाइ के तहत पंजीकरण के लिए सीएससी को शामिल किया है। सीएससी इलेक्ट्रानिक्स व आइटी मंत्रालय के तहत एक विशेष उद्देश्यीय उपक्रम है। त्यागी ने कहा कि अभिप्रमाणन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद पंजीकृत किसान को सूचित किया जाएगा और उसका पीएमकेएमवाइ पेंशन कार्ड व विशेष पेंशन खाता संख्या तैयार हो जाएगा। पीएमकेएमवाइ की घोषणा 2019-20 के बजट में की गई, जिसके तहत योग्य किसानों को 60 साल की उम्र के बाद तीन हजार रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी।

यह योजना देशभर में लागू की जा रही है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख सहित देशभर में दो हेक्टेयर तक भूमि रखने वाले किसान इस योजना को अपना सकते हैं। योजना को 18 से 40 साल के किसान अपना सकते हैं। यह स्वैच्छिक और भागीदारी वाली योजना है। इसमें किसानों को उनकी आयु के मुताबिक 55 से लेकर 200 रुपए तक का मासिक योगदान करना होगा। केंद्र सरकार भी उनके लिए बराबर की राशि का भुगतान करेगी। यह राशि उनके पेंशन कोष में जमा होगी और 60 साल की आयु पूरी होने पर उन्हें तीन हजार रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी।

किसान की पत्नी भी यदि अलग से पेंशन योजना को अपनाती है और उसमें अलग योगदान करती है तो वह भी तीन हजार रुपए पेंशन पाने की हकदार होगी। सेवानिवृत्ति आयु पूरी होने से पहले यदि किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी योजना को आगे जारी रख सकती है। यदि परिवार योजना को जारी नहीं रखना चाहता है तो किसान द्वारा किए गए कुल योगदान को ब्याज सहित उसकी पत्नी को दे दिया जाएगा।

नकदी संकट से जूझ रही बीएसएनएल का कंपनी ग्राहकों से बकाया वसूली पर जोर

नई दिल्ली, 11 अगस्त (भाषा)।

नकदी संकट से जूझ रही भारतीय संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने अपने कंपनी ग्राहकों से बकाए की वसूली के लिए आक्रामक तरीके से कदम उठाने की योजना बनाई है। दूरसंचार कंपनी अगले दो-तीन महीनों में 3,000 करोड़ रुपए से अधिक के बकाए में से बड़ी राशि की वसूली की उम्मीद कर रही है। बीएसएनएल यह कदम ऐसे समय उठा रही है जब कंपनी वित्तीय स्थिति को लेकर खासे दबाव में है। इसके कारण उसने इस साल दूसरी बार कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी की है। बीएसएनएल ने कर्मचारियों का जुलाई का वेतन पांच अगस्त को जारी किया था।

बीएसएनएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक पीके पुरवार ने कहा कि हमारा कंपनी ग्राहकों के ऊपर बकाया है जो 3,000 करोड़ रुपए से अधिक है। हम इसकी वसूली के लिए आक्रामक तरीके से कदम उठा रहे हैं। इस दिशा में हमें सफलता भी मिल रही है। पुरवार ने कहा कि पूरी बकाया राशि वसूली की समय सीमा बताना कठिन है, पर बीएसएनएल को अगले दो-तीन महीनों में उसमें से बड़ी राशि की वसूली की उम्मीद है।

कंपनी किराए से भी बढ़ी हुई आय प्राप्त करने की उम्मीद कर रही है। इस साल बीएसएनएल की किराए से करीब 1,000 करोड़ रुपए की आय पर नजर है। पिछली बार यह 200 करोड़ रुपए थी। इस योजना के तहत मौजूदा इमारतों के अधिक-से-अधिक उपयोग और ज्यादा जगह को पट्टे पर देने की योजना है। इसके अलावा बीएसएनएल सालाना करीब 200 करोड़ रुपए तक बचाने को लेकर 'आउटसोर्स' किए गए कार्यों को दुरुस्त करने पर भी काम कर रही है। कंपनी का मासिक आय और खर्च (परिचालन व्यय और वेतन) में 800 करोड़ रुपए का अंतर है।

दूरसंचार विभाग पुनरुद्धार पैकेज के रूप में बीएसएनएल और महानगर टेलीफोन निगम लि. (एमटीएनएल) के लिए राहत योजना तैयार कर रहा है। इस पैकेज में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, संपत्ति को बाजार पर चढ़ाने और 4-जी स्पेक्ट्रम का आबंटन शामिल है। इसके अलावा विभाग दोनों सार्वजनिक उपक्रमों को पटरी पर लाने के इरादे से उनके विलय पर भी काम कर रहा है। बीएसएनएल को 2018-19 में करीब 14,000 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान है। कंपनी को 2017-18 में 7,993 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था।

सात कंपनियों की बाजार हैसियत 87,966 करोड़ रुपए बढ़ी

नई दिल्ली, 11 अगस्त (भाषा)।

सूचकांक की शीर्ष दस में से सात कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में बीते सप्ताह संयुक्त रूप से 87,966 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक सर्वाधिक लाभ में रहे।

पिछले सप्ताह टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), एचडीएफसी, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक और आइसीआइसीआइ बैंक की बाजार हैसियत बढ़ी जबकि आरआइएल, आइटीसी और एसबीआइ को इस मामले में नुकसान उठाना पड़ा।

हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का बाजार मूल्यांकन 22,145.92 करोड़ बढ़कर 3,98,290.92 करोड़ रुपए पहुंच गया। एचडीएफसी बैंक की बाजार हैसियत 18,264.93 करोड़ की वृद्धि के साथ 6,23,892.08 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। एचडीएफसी का पूंजीकरण 15,148.15 करोड़ की बढ़ोतरी के साथ 3,81,619.34 करोड़ रुपए हो गया। टीसीएस की बाजार हैसियत 14,840.68 करोड़ बढ़कर 8,42,635.51 करोड़ रुपए हो गई।

इन्फोसिस का बाजार पूंजीकरण 6,335.19 करोड़ बढ़कर 3,39,372.78 करोड़ रुपए हो गया। आइसीआइसीआइ बैंक का बाजार मूल्यांकन 6,237.72 करोड़ की वृद्धि के साथ 2,71,360.08 करोड़ रुपए हो गया। कोटक महिंद्रा बैंक की बाजार हैसियत 4,993.29 करोड़ बढ़कर 2,92,866.47 करोड़ रुपए हो गया।

इसके विपरीत भारतीय स्टेट बैंक का बाजार पूंजीकरण 15,261.1 करोड़ घटकर 2,60,018.56 करोड़ रुपए और रिलायंस इंडस्ट्रीज की बाजार हैसियत 14,072.8 करोड़ की गिरावट के साथ 7,36,602.08 करोड़ रुपए हो गई। आइटीसी का बाजार पूंजीकरण 12,606.9 करोड़ घटकर 3,12,146.38 करोड़ रुपए हो गया। शीर्ष दस कंपनियों की रैंकिंग में टीसीएस शीर्ष पर रही। इसके बाद आरआइएल, एचडीएफसी बैंक, एचयूएल, एचडीएफसी, इन्फोसिस, आइटीसी, कोटक महिंद्रा बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक और एसबीआइ का स्थान आता है।

शेयर बाजार में बना रहेगा उतार-चढ़ाव

नई दिल्ली, 11 अगस्त (भाषा)।

शेयर बाजारों की चाल इस सप्ताह वृहत आर्थिक आंकड़े के साथ-साथ सरकार के आर्थिक वृद्धि को गति देने और कर मुद्दों के समाधान के लिए उठाए जाने वाले कदमों के कारण शेयर बाजारों में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। इस सप्ताह अवकाश के कारण कारोबारी दिवस कम होंगे। शेयर बाजार सोमवार को बकरीद और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बंद रहेंगे।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि आने वाले समय में निवेशकों की आर्थिक वृद्धि को गति देने और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के कर मुद्दों के समाधान के लिए सरकार की तरफ से उठाए जाने वाले कदमों पर नजर होगी। मंगलवार को बाजार पर औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े का असर देखने को मिल सकता है। यह आंकड़ा शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद जारी किया गया था। मुख्य रूप से खनन और विनिर्माण क्षेत्रों के कमजोर प्रदर्शन के कारण देश की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर जून में दो फीसद रही जो चार महीने का न्यूनतम स्तर है।

एक्सिस सिक्योरिटीज के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरुण ठुकराल ने कहा कि निवेशकों की धारणा से शेयर बाजारों में उतार-चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन इस बात पर नजर होगी कि सरकार मांग में नरमी से निपटने के लिए क्या कदम उठाएगी। मांग में कमी चक्रीय नरमी का संकेत देती है। सरकार के आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए किए गए उपायों का असर होता है, तो अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सकती है।

TRANSCORP INTERNATIONAL LTD.

Regd. Office:- Plot No. 3, HAF Pocket, Sec. 18A, Dwarka, Phase-II, New Delhi-110075
CIN: L51909DL1994PLC235697, Web-site: www.transcorpint.com, Phone: 91-11-30418901-05,
Fax: 91-11-30418906, e-mail: grievance@transcorpint.com

Extract of Unaudited Financial Results for the quarter ended 30th June 2019 (Rs. in Lakhs)

S.No.	Particulars	Standalone			Year	Consolidated	
		Quarter				Year	
		Ended	Ended	Ended	Ended	Ended	Ended
		30.06.2019	31.03.2019	30.06.2018	31.03.2019	30.06.2019	31.03.2019
		(unaudited)	(unaudited)	(unaudited)	(audited)	(unaudited)	(audited)
1	Total Income from Operations	58,118.02	38,053.28	34,525.17	146,816.38	58,313.52	147,550.45
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(93.63)	(666.29)	(154.58)	(1,141.58)	(102.55)	(1,271.95)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(93.63)	(666.29)	(154.58)	(1,141.58)	(102.55)	(1,271.95)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(64.42)	(533.94)	(101.08)	(849.92)	(74.96)	(985.92)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(63.18)	(544.61)	(101.17)	(855.80)	(78.92)	(907.32)
6	Equity Share Capital (of Rs. 2/- per share)	635.65	635.65	635.65	635.65	635.65	635.65
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year				5,175.33		5,415.69
8	Earnings Per Share (of Rs.2/- each) (for continuing and discontinued operations)						
	1. Basic:	(0.20)	(1.68)	(0.32)	(2.67)	(0.24)	(3.10)
	2. Diluted:	(0.20)	(1.68)	(0.32)	(2.67)	(0.24)	(3.10)

Notes:
1. The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee in its meeting held on 10th August 2019. The same has been approved and taken on record by the Board of Directors of the Company in its meeting held on 10th August 2019. The Statutory Auditor of the company has expressed an un-modified opinion on these financial results.
2. The above is an abstract of the detailed format of quarterly financial results filed with BSE under regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on BSE's website at www.bseindia.com and on the Company's website at www.transcorpint.com
3. The consolidated figures includes financials of the wholly owned subsidiaries of the company named Ritco Travels and Tours Private Limited and Transcorp Estates Private Limited for the quarter ended 30.06.2019
4. There are two wholly owned subsidiaries ie. Ritco Travels & Tours Private Limited & Transcorp Estate Private Limited. During the financial year 2018-19, the company opted not to present consolidated financial statements in the view of the option provided in the SEBI (LODR) Regulations, 2015 as amended from time to time. Accordingly, the corresponding figures for the immediately previous quarter and the figures for the corresponding quarter of the previous year could not be presented.
5. Previous year/period figures have been recasted and regrouped wherever necessary.

for Transcorp International Limited

Date: 10.08.2019
Place: Pushkar

-sd-
GOPAL KRISHAN SHARMA
DIN: 00016883
Managing Director

-sd-
SUBODH SUREKA
Chief Financial Officer

-sd-
Dilip Kumar Morwal
Group Company Secretary

नकली उत्पादों से देश को हर साल एक लाख करोड़ का नुकसान

नई दिल्ली, 11 अगस्त (भाषा)।

विभिन्न क्षेत्रों में नकली उत्पादों से देश को हर साल एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होता है। इसके बारे में पर्याप्त जागरूकता फैलाने, निगरानी करने और इसके खिलाफ समाधान विकसित करने की जरूरत है।

प्रमाणन उद्योग संगठन 'प्रमाणन समाधान सेवा प्रदाता संघ' (एएसपीए) ने यह बात कही। इस संगठन के 60 सदस्य हैं। संघ ने ब्रांड, आय और दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए प्रमाणन प्रौद्योगिकी और समाधान अपनाने पर जोर दिया। एएसपीए के अध्यक्ष नकुल पसरीचा ने कहा कि वर्तमान में नकली उत्पादों से देश को हर साल करीब 1.05 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। प्रमाणन समाधान, जागरूकता और निगरानी का सही तरीके से पालन कर अगर नकली उत्पादों पर 50 फीसद भी रोक लगा दी जाए जो देश को हर साल 50,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। नकली उत्पादों का नुकसान झेलने वालों में दवा क्षेत्र प्रमुख है। पसरीचा ने कहा कि सरकार को इस संबंध में पर्याप्त कदम उठाने की जरूरत है क्योंकि नकली दवाइयां आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा हैं।

'खाद्य तेल उद्योग की बेहतरी के लिए इसके आयात पर लगे अंकुश'

नई दिल्ली, 11 अगस्त (भाषा)।

वनस्पति तेल उद्योग का मानना है कि सरकार को घरेलू उद्योग और तिलहन किसानों की बेहतरी के लिए खाद्य तेलों के बढ़ते आयात पर अंकुश लगाने को लेकर ठोस कदम उठाने चाहिए।

उद्योग का सुझाव है कि सरकार खाद्य तेलों का आयात कम करने और तिलहन किसानों की आय बढ़ाने के लिए आयात शुल्क को तर्कसंगत बनाने के साथ-साथ आयातित तेलों पर ऊंची दर से माल व सेवा कर (जीएसटी) लगा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में खाद्य तेलों का आयात घटाकर शून्य करने की बात कही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जिस तरह दलहन का आयात कम करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रेरित किया गया, उसी तरह खाद्य तेलों के आयात को भी कम किया जा सकता है। इसके लिए किसानों को प्रेरित किया जाना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी खाद्य तेलों के आयात पर अंकुश लगाने पर जोर दिया है।

उद्योग का कहना है कि देश में खाद्य तेलों का आयात लगातार बढ़ता जा रहा है। 2017-18 में जहां 155-156 लाख टन का आयात हुआ था वहीं 2018-19 में यह बढ़कर 162 लाख टन तक पहुंच गया। यह हर साल बढ़ रहा है। खाद्य तेल आयात बिल 70 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। जिस गति से यह बढ़ रहा है उसे देखते हुए इसके एक लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाने का अनुमान है। किसानों के पास सरसों और सोयाबीन का स्टॉक अभी तक बिना बिके पड़ा है जबकि अगले कुछ महीनों में नई सोयाबीन की आवक होने लगेगी। पंजाब आयल मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील जैन का कहना है कि सरकार को वास्तव में यदि घरेलू स्तर पर तिलहन उत्पादन बढ़ाना है और किसानों को उनकी उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराना है तो सबसे पहले आयात पर अंकुश लगाना जरूरी है।

जैन ने सुझाव देते हुए कहा कि सोयाबीन, सनफ्लावर, रेपसीड पर आयात शुल्क को 35 फीसद से बढ़ाकर 45 फीसद कर दिया जाना चाहिए। इनके रिफाइंड तेल का आयात देश में नहीं होता है। कच्चे पॉम तेल पर आयात शुल्क को 40 फीसद से बढ़ाकर 45 फीसद किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कच्चे तेल के आयात पर 18 फीसद और आयातित रिफाइंड तेल पर 28 फीसद की दर से जीएसटी लगाया जा सकता है ताकि आयातित कच्चे तेल और रिफाइंड तेल में अंतर बना रहे। नेपाल से आयात होने वाले शुल्क मुक्त घी पर भी 28 फीसद की दर से जीएसटी लगाया जा सकता है। इससे घरेलू तेल-तिलहन उद्योग को काफी सहारा मिलेगा।

श्रीनगर में कारोबारियों को 1,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान

श्रीनगर, 11 अगस्त (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले प्रावधानों को खत्म करने और उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद लागू की गई पाबंदियों के कारण राज्य के कारोबारियों को करीब 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

कश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक सदस्य ने कहा कि प्रशासन की ओर से लागू पाबंदियों के कारण राज्य में जनजीवन ठप है। इससे कश्मीर में करीब 175 करोड़ रुपए रोजाना के हिसाब से कारोबारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि पाबंदियों के कारण लोग घरों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इस वजह से बेकरी और मवेशियों के डीलरों का कारोबार सबसे अधिक प्रभावित हुआ है।

एबीएम इन्टरनेशनल लिमिटेड

CIN NO. L51909DL1983PLC15585
पंजी. कार्यालयः 10/60, इंड. एरिया, कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110015
फोनः 011-41426055, **ईमेलः** vkgandhi@abmintl.in, वेबसाईटः www.abmintl.in
30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के स्टैंडएलॉन तथा समेकित अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरणों का सार

(रु. लाखों में)

विवरण	समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष
	30.6.2019 अनंकेक्षित	30.6.2018 अनंकेक्षित	31.3.2019 अंकेक्षित	30.6.2019 अनंकेक्षित	30.06.2018 अनंकेक्षित	31.03.2019 अंकेक्षित
	स्टैंडएलॉन		स्टैंडएलॉन	समेकित		समेकित
कुल राजस्व	2812.26	1982.00	7779.02	2812.26	1982.00	7779.02
विशिष्ट एवं असाधारण मदों तथा कर से पूर्व लाभ/(हानि)	(15.84)	(31.50)	(238.28)	(15.84)	(31.50)	(238.28)
एसोसिएट्स के लाभ/(हानि) का शेयर	-	-	-	-	-	(1.89)
असाधारण मदों एवं कर से पूर्व लाभ/(हानि)	(15.84)	(31.50)	(238.28)	(15.84)	(31.50)	(240.17)
कर से पूर्व लाभ/(हानि)	(15.84)	(31.50)	(238.28)	(15.84)	(31.50)	(240.17)
अनवरत प्रचालनों से अवधि के लिये लाभ/(हानि)	(15.84)	(31.50)	(176.71)	(15.84)	(31.50)	(178.60)
मदें जो लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकृत की जायेगी	(2.50)	(3.06)	(10.66)	(2.50)	(3.06)	(10.66)
अवधि के लिये कुल अन्य व्यापक आय/(हानि)	(2.50)	(3.06)	(10.66)	(2.50)	(3.06)	(10.66)
अवधि के लिये कुल व्यापक आय/(हानि)	(18.34)	(34.56)	(187.37)	(18.34)	(34.56)	(189.26)
प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	1176.00	1176.00	1176.00	1176.00	1176.00	1176.00
अन्य इक्विटी			200.11			200.11
आय प्रति इक्विटी शेयर (रु. 10/- प्रति का):						
1) मूल (रु. प्रति शेयर)	(0.16)	(0.29)	(1.59)	(0.16)	(0.29)	(1.61)
2) तरल (रु. प्रति शेयर)	(0.16)	(0.29)	(1.59)	(0.16)	(0.29)	(1.61)

टिप्पणीः
1. उपरोक्त स्टैंडएलॉन तथा समेकित अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 10 अगस्त, 2019 को अयोजित उनकी बैठक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित किये गये।
2. 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों की सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उदघाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत वांछित रूप में सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा की गई है। इन वित्तीय परिणामों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट इंड ए एस 34 अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग में निर्दिष्ट पहचान तथा मापन के सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है।
3. अलग से विवरण देने योग्य कोई खंड नहीं है।
4. आस्थगित कर समायोजन तथा ग्रैच्युईटी के प्रावधान का विचार वर्ष के अंत में किया जायेगा।
5. जहाँ भी जरूरी हुआ, पूर्व वर्ष/तिमाही के आँकड़े पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किये गये हैं।

निदेशक मंडल के लिये तथा उसकी ओर से
एबीएम इन्टरनेशनल लिमिटेड
हस्ता./-
(विरेन्दर कुमार गांधी)
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक
DIN: 00244762

तिथिः 10.08.2019
स्थानः नई दिल्ली

पीएनसी इन्फ्राटेक लिमिटेड

पंजीकृत. कार्यालय- एनवीसीसी प्लाजा, टावर-II, 4था तल, पुष्प विहार, सेक्टर-5, साकेत, नई दिल्ली-110017
CIN: L45201DL1999PLC195937, ईमेल: complianceofficer@pncinfratech.com, वेबसाइट: www.pncinfratech.com

30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों का सार

(रु. लाखों में) (ईपीएस को छोड़कर)

क्रम सं.	विवरण	स्टैण्डएलॉन			समेकित		
		समाप्त तिमाही (30.6.2019) अनंकेक्षित	समाप्त तिमाही (30.6.2018) (अनंकेक्षित)	समाप्त वर्ष (31.3.2019) अंकेक्षित	समाप्त तिमाही (30.6.2019) अनंकेक्षित	समाप्त वर्ष (30.6.2018) अनंकेक्षित	समाप्त वर्ष (31.3.2019) अंकेक्षित
1.	परिचालनों से कुल आय	1,33,527.22	75,339.37	3,13,991.10	1,59,933.39	93,804.31	382097.39
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	14,467.76	11,738.16	34,404.26	23,508.36	11,251.16	35897.51
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	14,467.76	11,738.16	34,404.26	23,508.36	11,251.16	35897.51
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	10,014.90	10,252.19	32,491.22	17,656.62	11,763.17	35066.52
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल]	9,991.21	10,242.09	32,396.45	17,827.14	11,750.72	35041.73
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	5,130.78	5,130.78	5130.78	5,130.78	5,130.78	5130.78
7.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाई गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)	-	-	2,06,389.02	-	-	197307.52
8.	आय प्रति शेयर (रु. 2/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) 1. मूलः 2. तरलः	3.90	4.00	12.67	6.96	4.58	13.70

टिप्पणीः
1) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल की गई तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट (www.bseindia.com, www.nseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाईट (www.pncinfratech.com) पर उपलब्ध है।
2) उपरोक्त स्टैण्डएलॉन/समेकित परिणामों जिसकी ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई, को 10 अगस्त, 2019 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए।

पीएनसी इन्फ्राटेक लि. के लिए
हस्ता.
चक्रेश कुमार जैन
प्रबंध निदेशक एवं सीएफओ
(DIN: 00086768)

स्थानः आगरा
तिथिः 10 अगस्त, 2019

epaper.jansatta.com

आयकर विवादों में अपील करने की मौद्रिक सीमा बढ़ी

मुकदमेबाजी घटेगी और प्रस्तावित प्रत्यक्ष कर संहिता को अपनाने में आसानी होगी : विशेषज्ञ

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

वित्त मंत्रालय ने आयकर विभाग के वास्ते कर विवादों को लेकर अपीलीय न्यायाधिकरण से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक विभिन्न मंचों में अपील दायर करने के मामलों में विवादित राशि की सीमा बढ़ा दी है। अब बढ़ी हुई राशि के मुताबिक ही विभाग मामले दायर कर सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे कर विवादों को लेकर मुकदमेबाजी में कमी आएगी और प्रस्तावित प्रत्यक्ष कर संहिता को अपनाने में आसानी होगी।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में विभाग की ओर से अपील करने की मौद्रिक सीमा को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया है। यानी अब अपीलीय न्यायाधिकरण में आयकर विभाग उन्हीं मामलों में अपील दायर कर सकेगा जिनमें विवादित कर मांग 50 लाख रुपए या उससे अधिक है। इससे कम राशि की संलिप्तता वाले मामले में अपील नहीं हो सकेगी। वहीं, हाईकोर्ट के मामले में यह सीमा दोगुनी बढ़ाकर एक करोड़ रुपए कर दी गई है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, उसमें अपील दायर करने के लिए कर विवादित वाले मामलों की सीमा एक करोड़ रुपए से बढ़ाकर दो करोड़ रुपए कर दी गई है। एक साल के भीतर मौद्रिक सीमा में यह दूसरी बढ़ोतरी है।

वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउंटेंट शिव कुमार गुप्ता के मुताबिक सीबीडीटी के इस कदम से अदालतों में भीड़ कम करने में मदद मिलेगी व आयकर विभाग को अधिक मूल्य वाले जटिल मामलों पर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद मिलेगी। मौजूदा आयकर कानून के तहत लंबित मामलों में कमी आने से नई प्रत्यक्ष कर संहिता को अपनाए जाने का रास्ता भी सरल होगा। कारोबार जगत ने कहा कि यह स्वागतयोग्य कदम है। कर प्रशासन ने जो सीमा बढ़ाई है, यह उसके पिछले चार- पांच साल के दौरान किए जा रहे उपायों के अनुरूप है। प्रशासन को विवादों को वापस लेने की योजना पर भी गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए। हाल में अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में इस तरह की योजना पेश की गई थी, इसी तरह की योजना प्रत्यक्ष कर मामले में भी लाई जा सकती है।

जबलपुर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रविवार को आयोजित मिनी मैराथन में भाग लेते लोग।

कराची में मीका की प्रस्तुति से भड़का विवाद

कराची, 11 अगस्त (भाषा)।

भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ने के बीच जाने-माने गायक मीका सिंह और उनके ट्रुप के कराची में एक अरबपति की बेटी की शादी में कार्यक्रम प्रस्तुत करने से विवाद पैदा हो गया है। बताया जाता है कि यह अरबपति पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ का करीबी है।

भारत ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छे 370 के अधिकतर प्रावधानों को सोमवार को खत्म कर दिया और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित क्षेत्रों में विभाजित कर दिया। इस पर पाकिस्तान ने कड़ा ऐतराज जताया है। पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने राजनयिक संबंधों को कम कर दिया है और कारोबारी संबंध को रोक दिया है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच समझौता एक्सप्रेस सेवा भी रोक दी गई है।

- मीका ने पाकिस्तान के एक अरबपति के बेटी की शादी में कार्यक्रम पेश किया था
- कार्यक्रम का वीडियो अपलोड होने पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने सरकार को घेरा
- भारतीय प्रशंसक भी खफा हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की

अखबार 'डेली जंग' के अनुसार मीका ने आठ अगस्त को कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। कार्यक्रम में शिरकत करने वाले लोगों के सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने के बाद पाकिस्तान में उनकी मौजूदगी का पता चला। विपक्षी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता सैयद खुर्शीद शाह ने कहा कि सरकार को निश्चित रूप से यह पता लगाना चाहिए कि ऐसे वक्त में जब भारत के साथ राजनयिक और कारोबारी संबंध स्थगित हैं तो भारतीय गायक और उनके 14 सदस्यीय ट्रुप को किसने सुरक्षा मंजूरी दी। शाह ने कहा, 'पाकिस्तान में इस वक्त भारतीय फिल्मों, नाटकों, कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा है और देश ने भारत सरकार के समक्ष अपना दृष्टिकोण साफ कर दिया है। अगर इससे पहले उन्हें वीजा मिले थे तो उन्हें उसे रद्द कर देना चाहिए।'

अखबार की खबर के अनुसार दुल्हा मीका का बहुत बड़ा प्रशंसक है और वह उनका लाइव परफॉर्मेंस देखना चाहता था। उसकी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए ससुराल वालों ने अपने संपर्क का इस्तेमाल करते हुए भारतीय बैंड को उच्च स्तरीय सुरक्षा मंजूरी व वीजा दिलवाया। मीका की इस प्रस्तुति के लिए उन्हें करीब 150,000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया गया।

पंजाबी गायक के इस कार्यक्रम से उनके भारतीय प्रशंसक भी खफा हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, 'देशद्रोही तुम्हे शर्म आनी चाहिए।' एक अन्य ने लिखा, 'मीका सिंह पाजी हम भारतीयों ने आपको बहुत प्यार दिया... और जब पाकिस्तान ने हमसे सारे संबंध तोड़ लिए हैं, सीमा पार से आतंकवादियों को भेज रहा है, हमारी चिंताएं बढ़ा दी हैं, ऐसे हालात में आप एक कार्यक्रम के लिए पाकिस्तान क्यों गए? क्या चंद रुपए आपके लिए भारत से बड़े हैं?'

एअर इंडिया को 2019 के पहले छह महीने में यौन उत्पीड़न की आठ शिकायतें मिलीं

नई दिल्ली, 11 अगस्त (भाषा)।

एअर इंडिया में साल के पहले छह महीने में कंपनी के अंदर यौन उत्पीड़न की आठ शिकायतें मिलीं जबकि 2018 में इस ऐसे मामलों की कुल संख्या 10 थी। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। इस साल 16 मई को एअर इंडिया के प्रमुख अश्विनी लोहानी ने एक संदेश भेजकर कर्मचारियों से कहा था कि कंपनी में अक्सर यौन उत्पीड़न के मामले देखे जा रहे हैं और एअरलाइन को ऐसे अपराधियों से बहुत सख्ती से निपटने की जरूरत है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के इस संदेश से एक दिन पहले ही 15 मई को एअरलाइन ने घोषणा की थी कि उसने एक कमांडर के खिलाफ यौन उत्पीड़न की एक महिला पायलट की शिकायत की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच बिठाई है। एक सूत्र ने कहा, '2018 के दौरान एअर इंडिया में यौन उत्पीड़न की कुल 10 शिकायतें दर्ज की गई थी। 2019 में एक जनवरी से लेकर एक जुलाई तक यौन उत्पीड़न की आठ शिकायतें मिली हैं।'

एक अन्य सूत्र ने रविवार को कहा कि एअर इंडिया हर ऐसी शिकायत से यथासंभव सख्ती से निपटता रहा है। एक महिला पायलट ने शिकायत दर्ज कराई थी कि हैदराबाद में पांच मई को उसका यौन उत्पीड़न किया गया, जहां वह कमांडर से प्रशिक्षण हासिल कर रही थी। उसके बाद उच्च स्तरीय जांच शुरू की गई थी।

एअर इंडिया के क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) अभय पाठक ने आरोपी को पत्र लिखकर कहा, 'जांच चलते रहने के समय निलंबन के दौरान आप बिना अनुमति एयर इंडिया लिमिटेड के परिसर में दाखिल नहीं होंगे।' पाठक ने कहा था, 'आप अधोहस्ताक्षरी की अनुमति के बगैर स्टेशन (दिल्ली) से नहीं जाएंगे।'

ठेके पर विनिर्माण में मिल सकती है सौ फीसद एफडीआइ को मंजूरी

नई दिल्ली, 11 अगस्त (भाषा)।

सरकार विदेशी निवेश आकर्षित करने के इरादे से ठेके पर विनिर्माण के क्षेत्र में 100 फीसद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) की मंजूरी देने के प्रस्ताव पर काम कर रही है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

मौजूदा विदेशी निवेश नीति के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में स्वतः मंजूरी मार्ग से 100 फीसद एफडीआइ की अनुमति है। विनिर्माता को भारत में विनिर्मित उत्पादों को बिना सरकार की मंजूरी के ई-वाणिज्य समेत थोक और खुदरा माध्यमों से बेचने की भी अनुमति है। उसने कहा, 'मौजूदा नीति में ठेके पर विनिर्माण के बारे में कुछ नहीं कहा गया है और इस बारे में चीजें स्पष्ट नहीं हैं। दुनिया भर में प्रौद्योगिकी क्षेत्र की बड़ी कंपनियां अनुबंध के आधार पर विनिर्माण को पसंद कर रही हैं। इसीलिए इस मामले में स्पष्टीकरण की जरूरत है और सरकार इस पर सकारात्मक रूप से विचार कर रही है।'

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय एक प्रस्ताव पर काम कर रहा है, जिसे जल्दी ही अंतिम रूप दिया जाएगा और मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा। इस बारे में डेलायट इंडिया के भागीदार रजत वाही ने कहा कि अगर सरकार इस कदम को मंजूरी देती है, इससे विनिर्माण क्षेत्र को गति मिलेगी।

उन्होंने कहा, 'यह एपल जैसी प्रौद्योगिकी आधारित कंपनियों के लिए स्वागत योग्य प्रस्ताव है।' वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विदेशी निवेश आकर्षित करने के इरादे से जुलाई में अपने बजट भाषण में विमानन, एवीजीसी (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स), बीमा और एकल खुदरा ब्रांड जैसे क्षेत्रों में एफडीआइ नियमों में ढील देने का प्रस्ताव किया था। भारत में एफडीआई 2018-19 में एक फीसद घटकर 44.36 अरब डॉलर रहा।

पिछले साल सरकार ने एकल खुदरा ब्रांड, गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनियों तथा निर्माण समेत विभिन्न क्षेत्रों के लिए एफडीआई नियमों में ढील दी थी। देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए बंदरगाह, हवाईअड्डा और राजमार्ग जैसे बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए अरबों डालर की जरूरत है। इस लिहाज से भारत में विदेशी निवेश काफी महत्त्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ने से देश का भुगतान संतुलन भी बेहतर रहता है और दूसरी वैश्विक मुद्राओं के समक्ष रुपये की कीमत को मजबूती मिलती है।

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने दी ईद की बधाई

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 11 अगस्त।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों को ईद उल जुहा की बधाई दी है।

राष्ट्रपति ने संदेश में कहा कि ईद उल जुहा का त्योहार प्यार, बंधुता और मानवता की सेवा का प्रतीक है। इस पवित्र मौके पर वे सभी नागरिकों खासकर भारत और विदेश में रह रहे मुसलिम भाइयों और बहनों को अपनी शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने कहा कि ईद उल जुहा प्यार, बंधुता और मानवता की सेवा का प्रतीक है। आइए हम इन सार्वभौम मूल्यों के लिए खुद को प्रतिबद्ध करें, जो हमारी समग्र संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। उपराष्ट्रपति नायडू ने भी उम्मीद जताई कि ईद का त्योहार शांति और सद्भाव के साथ मनाया जाएगा।

सेवा नियमित करने की मांग पर लाठीचार्ज

भोपाल, 11 अगस्त (भाषा)।

सेवा नियमित करने की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे मध्य प्रदेश विद्युत विभाग के अधीन चल रही बिजली वितरण करने वाली कंपनियों में आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे कर्मचारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने रविवार को यहां हल्का लाठीचार्ज किया।

Archies
The most special way to say you care
Visit us at: www.archiesonline.com

ARCHIES LIMITED
C-113, NARAINA INDUSTRIAL AREA, PHASE-I, NEW DELHI-110 028. TEL.: 41412222. FAX: 41410060.
REGD. OFFICE: 191F, SECTOR - 4, IMT MANESAR, GURUGRAM, HARYANA -122050. CIN: L36999HR1990PLC041175.
Web: www.archiesonline.com, Email: archies@archiesonline.com, Tel: +91 124 4966666, Fax: +91 124 4966650

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2019
(₹ in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended 30/06/2019 UNAUDITED	Quarter Ended 30/06/2018 UNAUDITED	Year Ended 31/03/2019 AUDITED
1	Total income from Operations	3133.74	3428.78	16136.44
2	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (before Exceptional and/or Extraordinary items)	(338.79)	(77.74)	72.67
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(338.79)	(77.74)	72.67
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(231.32)	(47.00)	72.61
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(233.83)	(46.68)	46.08
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of ₹ 2/- each)	675.62	675.62	675.62
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	9,814.14
8	Earning Per Share (of ₹ 2/- each)			
	(a) Basic (₹)	(0.68)	(0.14)	0.21
	(b) Diluted (₹)	(0.68)	(0.14)	0.21

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Unaudited Financial Results are available on the Stock Exchange websites viz www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company's website www.archiesonline.com.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD
sd/-
ANIL MOOLCHANDANI
(Chairman)
DIN- 00022693

Date: 10 August 2019
Place: Delhi

TINNA RUBBER AND INFRASTRUCTURE LIMITED
Registered Office : Tinna House No.6, Sultanpur, Mandi Road, Mehrauli, New Delhi-110030
Website: www.tinna.in, **email:** investor@tinna.in, Telephone No.:011-49518530 Fax no.:011-26807073
CIN:L51909DL1987PLC027186

EXTRACT OF THE UN AUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2019
(Rs. in lakhs)

S. No.	PARTICULARS	STANDALONE Quarter Ended 30-Jun-19 Unaudited	STANDALONE Quarter Ended 31-Mar-19 Audited	STANDALONE Quarter Ended 30-Jun-18 Unaudited	STANDALONE Year Ended 31-Mar-19 Audited	CONSOLIDATED Quarter Ended 30-Jun-19 Unaudited	CONSOLIDATED Quarter Ended 31-Mar-19 Audited	CONSOLIDATED Quarter Ended 30-Jun-18 Unaudited	CONSOLIDATED Year Ended 31-Mar-19 Audited
1	Total income from operations	3,234.00	3,118.55	3,161.37	12,970.99	3,234.00	3,118.55	3,161.37	12,970.99
2	Net profit/(loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	6.98	270.09	4.28	34.60	18.58	273.39	(18.23)	46.23
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	6.98	270.09	4.28	34.60	18.58	273.39	(18.23)	46.23
4	Net profit/(loss) for the period after Tax(After Exceptional and \ or Extra ordinary Items)	3.70	199.77	3.17	(15.35)	15.30	203.07	(19.34)	(3.72)
5	Total Comprehensive Income for the period (comprising profit/ (loss) for the period (after tax) and other comprehensive Income (after Tax)	4.46	187.25	8.31	(13,76)	15.88	190.37	(14.38)	(2.86)
6	Equity Share Capital (Face value of Rs.10/- each)	856.48	856.48	856.48	856.48	856.48	856.48	856.48	856.48
7	Other Equity				6,390.07				6272.23
8	Earning Per Share (Face value of Rs10/- each share) (for continuing and discontinued operation)								
	(a) Basic	0.04	2.33	0.04	(0.18)	0.18	2.37	(0.23)	(0.04)
	(b) Diluted	0.04	2.33	0.04	(0.18)	0.18	2.37	(0.23)	(0.04)

Note:-
1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly/ Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Yearly Financial Results are available on the Stock Exchange websites ie www.bseindia.com and on the company's website www.tine.in
2 The above financials results of Tinna Rubber And Infrastructure Limited ('the Company ') have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS)- 34 "Intrim Financial Reporting" as prescribed under Section 133 of the Companies Act,2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules,2015 and the Companies (Indian Accounting Standards) Rules,2016.
3 The Statutory Auditors have given a modified opinion on deferment of markeing,promotion and other expenses of Rs.46.92 lakhs. The company is part of circular economy where Old Tyre (Waste) is converted into reusable Crumb Rubber and value added products (Wealth). Company has first time participated in 2018-19 as sponsor in exhibitions in India and abroad to meet reputed customers at one platform and incurred expenses on lab test of product to make it of acceptable standards and other marketing and promotion expenses of these product. Benefits of these expenses would realize in next years as well. Hence company had carried forward Rs.53.62 lakhs as on 31.03.2019 to be amortised in next two years 2019-20 & 2020-21,Out of this Rs.6.70 lakhs has been amortised during the quarter & Rs.46.92 lakhs is carried forward and to be amortised in next 1 year and 3 quarters.
4 The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 10th August, 2019.

FOR TINNA RUBBER AND INFRASTRUCTURE LIMITED
Sd/-
Bhupinder Kumar Sekhri
Managing Director

Place : New Delhi
Date : 10th August, 2019

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India BOI
कृष्णा नगर शाखा
ए 1 / 11 कृष्णा नगर, दिल्ली-110051

कब्जा सूचना
अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का नं. 3) के तहत बैंक ऑफ इंडिया का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(4) के अधीन प्रदत्त शक्तियो के अंतर्गत कर्जदार श्री राहुल चौधरी, श्री पंकज चौधरी, श्रीमती मोनिका चौधरी और श्रीमती प्रिया सिंह, सभी निवासी : एसजे-81, शास्त्री नगर, गाजियाबाद को मांग सूचना दिनांकित 07.06.2019 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. 62,58,543.51 (रुपये बासठ लाख अट्ठावन हजार पाँच सौ तैतालीस पैसे इक्यावन मात्र) दिनांक 31.05.2019 तक भविष्य का ब्याज, आकस्मिक एवं अन्य प्रभार इत्यादि उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार/गारंटर राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमो के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक 08.08.2019 को लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार/गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन बैंक ऑफ इंडिया, कृष्णा नगर शाखा, दिल्ली के प्रभार वास्ते रु. रु. 62,58,543.51 (रुपये बासठ लाख अट्ठावन हजार पाँच सौ तैतालीस पैसे इक्यावन मात्र) दिनांक 31.05.2019 तक भविष्य का ब्याज, आकस्मिक एवं अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

साम्यिक बंधक सम्पत्ति प्लॉट नं. एसजे – 81, शास्त्री नगर, गाजियाबाद में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती सरोज देवी के नाम पर है। सरफासी एक्ट, 2002 के प्रावधानों के तहत

दिनांक : 08-08-2019, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

फार्म जी
रूचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण
[दिवाला और शोधन अक्षमता (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला रिजोल्यूशन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 36(1) के अंतर्गत]

संगत विवरण

1.	कॉर्पोरेट देनदार का नाम	बाउलवर्ड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट देनदार के गठन की तिथि	7 जून 2010
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट देनदार गठित/पंजीकृत है	कंपनी अधिनियम, 1956, कंपनी पंजीयक रा.रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा, नई दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U70200DL2010PTC203764
5.	कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय, यदि कोई हो, का पता	पंजीकृत कार्यालय : सी-23, ग्रेटर कैलाश एन्क्लेव, पार्ट-1, नई दिल्ली-110048 कॉर्पोरेट कार्यालय : डेक बाउलवर्ड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, सेन्ट्रल ब्लॉक, प्लॉट नं. 6, सेक्टर-127, नौएडा, उत्तर प्रदेश-201301
6.	कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में दिवाला प्रारंभ तिथि	8 फरवरी, 2019 (आदेश 14.02.2019 एनसीएलटी साइट पर उपलब्ध)
7.	रूचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	7 मई, 2019
8.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के अंतर्गत रिजोल्यूशन आवेदकों के लिए योग्यता की उपलब्धता	इसे ई-मेल boulevard.amitagcs@gmail.com पर मेल भेजकर प्राप्त किया जा सकता है
9.	धारा 29ए के अंतर्गत लागू अयोग्यता मानकों की उपलब्धता	इसे ई-मेल boulevard.amitagcs@gmail.com पर मेल भेजकर प्राप्त किया जा सकता है
10	रूचि की अभिव्यक्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि	31 अगस्त, 2019 (नया संशोधित) 26 जून, 2019 (संशोधित) 6 जून, 2019 (पिछला)
11	भावी रिजोल्यूशन आवेदकों की वैकल्पिक सूची जारी करने की तिथि	10 सितम्बर, 2019 (नया संशोधित) 05 जुलाई, 2019 (संशोधित) 15 जून, 2019 (पिछला)
12.	वैकल्पिक सूची के लिए आपत्ति जमा करने की अंतिम तिथि	15 सितम्बर, 2019 (नया संशोधित) 10 जुलाई, 2019 (संशोधित) 21 जून, 2019 (पिछला)
13.	भावी रिजोल्यूशन आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	25 सितम्बर, 2019 (नया संशोधित) 21 जुलाई, 2019 (संशोधित) 01 जुलाई, 2019 (पिछला)
14	भावी रिजोल्यूशन आवेदकों के लिए रिजोल्यूशन योजना हेतु सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स एवं अनुरोध जारी करने की तिथि	15 सितम्बर, 2019 (नया संशोधित) 10 जुलाई, 2019 (संशोधित) 21 जून, 2019 (पिछला)
15	रिजोल्यूशन योजना के लिए अनुरोध, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन एवं भावी जानकारी प्राप्त करने का तरीका	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला रिजोल्यूशन प्रक्रिया) करने विनियम, 2016 के विनियम 36ख(1) के अंतर्गत इसे प्राप्त करने के योग्य सभी भावी रिजोल्यूशन आवेदकों (पीआरए) को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में साझा किया जाएगा।
16	रिजोल्यूशन योजना जमा करने की अंतिम तिथि	15 अक्टूबर, 2019 (नया संशोधित) 05 अगस्त, 2019 (नया संशोधित) 20 जुलाई, 2019 (पिछला)
17	रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के लिए रिजोल्यूशन योजना जमा करने का तरीका	रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अर्थात् अमित अग्रवाल, एच-63, विजय चौक लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 को संबोधित करके मुहरबंद लिफाफे में डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से और उसके बाद पुष्टि के लिए ई-मेल किया जाएगा।
18	अनुमोदन के लिए न्यायिक प्राधिकरण के पास रिजोल्यूशन योजना जमा करने की अनुमानित तिथि	25 अक्टूबर, 2019 (नया संशोधित) 10 अगस्त, 2019 (संशोधित) 29 जुलाई 2019 (पिछला)
19	रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम एवं पंजीकरण संख्या	अमित अग्रवाल पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-02/IP-N00185/2017-18/10456
20	बोर्ड में पंजीकृत अनुसार रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम, पता एवं ई-मेल	अमित अग्रवाल, एच-63, विजय चौक लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 ईमेल आईडी : amitagcs@gmail.com
21	रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए उपयोग होने वाला पता एवं ई-मेल	अमित अग्रवाल, एच-63, विजय चौक लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 ईमेल आईडी : boulevard.amitagcs@gmail.com
22.	विस्तृत विवरण उपलब्ध है:	इसे ई-मेल boulevard.amitagcs@gmail.com पर मेल भेजकर प्राप्त किया जा सकता है
23.	फार्म जी के प्रकाशन की तिथि	12 अगस्त, 2019 (नया संशोधित) 14 जून, 2019 (संशोधित) 7 मई, 2019 (पिछला)

हस्ता/-
अमित अग्रवाल
पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-02/IP-N00185/2017- 18/10456
एच-63, विजय चौक लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
कृते बाउलवर्ड प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड
(12 अगस्त, 2019)

खबर कोना

स्कॉटलैंड में रविवार को लेडीज ओपन स्कॉटिश ओपन गोल्फ टूर्नामेंट में दक्षिण कोरिया की चेल्ला चोई।

भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमें ओलंपिक टैस्ट प्रतियोगिता के लिए रवाना

बंगलुरु, 11 अगस्त (भाषा)।

भारत की पुरुष और महिला हॉकी टीमें तोक्यो में 17 अगस्त से शुरू हो रही ओलंपिक टैस्ट प्रतियोगिता के लिए रविवार को रवाना हो गईं। भारत की पुरुष और महिला टीमों को इसी साल ओलंपिक क्वालीफाइंग प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लेना है। नवंबर में होने वाले क्वालीफायर से पहले दोनों टीमों को ओलंपिक टैस्ट प्रतियोगिता से अच्छा अनुभव मिलने की उम्मीद है। भारत की पुरुष टीम मेजबान जापान, न्यूजीलैंड और मलेशिया से खेलेगी जबकि महिला टीम को आस्ट्रेलिया, चीन और जापान का सामना करना है। भारतीय पुरुष टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि मेरा मानना है कि यह टूर्नामेंट युवाओं के पास छाप छोड़ने का अच्छा मौका है क्योंकि ओलंपिक क्वालीफायर के लिए टीम चयन से पहले हमारे ऊपर निगाहें रहेंगी। उन्होंने साथ ही कहा कि टैस्ट प्रतियोगिता से टीम को तोक्यो की परिस्थितियों को समझने का मौका भी मिलेगा जहां अगले साल ओलंपिक का आयोजन होना है। डिफेंडर ड्रैगफ्लिकर हरमनप्रीत ने कहा कि हम ओलंपिक क्वालीफिकेशन को लेकर सकारात्मक हैं। इस स्थल पर खेलने से हमें वहां की परिस्थितियों को समझने में मदद मिलेगी और हम टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने को लेकर उत्साहित हैं। महिला टीम की कप्तान रानी ने कहा कि आगामी टूर्नामेंट में उनकी टीम का लक्ष्य बेहतर रैंकिंग वाले आस्ट्रेलिया के खिलाफ उलटफेर भरी जीत दर्ज करने का होगा। रानी ने टीम की रवानगी से पूर्व कहा कि पिछले एक साल में हमने जापान और चीन के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया है लेकिन एक टीम जिसके खिलाफ हम अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं वह आस्ट्रेलिया है।

किसी भी स्थान पर बल्लेबाजी के लिए तैयार : अय्यर

पोर्ट ऑफ स्पेन, 11 अगस्त (भाषा)।

चौथे स्थान पर बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी के लिए भारतीय टीम प्रबंधन की तलाश जारी है। ऐसे में श्रेयष अय्यर ने कहा है कि वह किसी भी स्थान पर बल्लेबाजी के लिए तैयार हैं। वेस्ट इंडीज दौरे पर गई भारतीय टीम का हिस्सा अय्यर को दौरे पर अगले दो एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में लोकेश राहुल और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ियों की चुनौती का सामना करना होगा।पिछले कुछ समय से भारत के लिए समस्या बने चौथे क्रम के बारे में पूछे जाने पर अय्यर ने कहा कि हमें कोई जानकारी नहीं है। यह पूरी तरह से प्रबंधन का फैसला है। मैं जाकर यह नहीं कह सकता कि मुझे चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करनी है और वे मुझे इस स्थान पर रखें। ऐसा नहीं है। भारत विश्व कप तक के सफर के दौरान चौथे नंबर पर स्थायी बल्लेबाज नहीं ढूंढ पाया और यह तलाश मौजूदा दौरे पर तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के बाकी बचे दो मैचों में भी जारी रहेगी।

सौरभ वर्मा ने हैदराबाद ओपन खिताब जीता

हैदराबाद, 11 अगस्त (भाषा)।

मौजूदा राष्ट्रीय चैंपियन सौरभ वर्मा ने रविवार को यहां हैदराबाद ओपन बीडब्ल्यूएफ टूर सुपर 100 टूर्नामेंट के पुरुष एकल के फाइनल में सिंगापुर के लोह कीन यियू को हराकर खिताब अपने नाम किया तो वहीं महिला युगल के फाइनल में अश्विनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी की भारतीय जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा।

इस साल मई में स्लोवेनिया अंतरराष्ट्रीय के चैंपियन बने मध्य प्रदेश के 26 साल के इस खिलाड़ी ने शानदार खेल दिखाते हुए विश्व रैंकिग में 44वें स्थान पर काबिज कीन यियू को 52 मिनट तक चले मुकाबले में 21-13 14-21 21-16 से हराया।

यहां के गाचीबाउली इंडोर स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में जीत दर्ज करने के बाद सौरभ ने कहा, 'मैं इस सप्ताह अपने प्रदर्शन से काफी खुश हूं। पिछले दौर के मुकाबलों में मैंने संघर्षपूर्ण जीत दर्ज की और फिर फाइनल में भी अच्छा खेल दिखाया।' लउन्होंने कहा, 'पहला गेम जीतने के बाद मैं दूसरे गेम में भी आगे था लेकिन मैच जल्दी खत्म करने की कोशिश में मेरा ध्यान भटक गया। इससे विरोधी खिलाड़ी मुझ पर हावी हो गया और मेरे लिए वापसी करना मुश्किल हो गया। तीसरे गेम में मैंने रणनीति में बदलाव किया और इसका फायदा हुआ। मैं इस सप्ताह के अपने प्रदर्शन से खुश हूं।'

अश्विनी और सिक्की की शीर्ष वरीय महिला युगल जोड़ी हालांकि अपना पहला खिताब जीतने में नाकाम रही। भारतीय जोड़ी को बाएक हा ना और जंग क्यूंग युन की कोरियाई जोड़ी ने 21-17, 21-17 से हराया।

अश्विनी-सिक्की की जोड़ी उपविजेता

सौरभ वर्मा

सौरभ ने अच्छी शुरुआत करते हुए 6-2 और फिर 11-4 की बढ़त कायम कर आसानी से पहला गेम 21-13 से आपने नाम किया। दूसरे गेम में भी भारतीय खिलाड़ी ने 5-0 की बढ़त कायम की लेकिन कीन यियू ने पहले 10-10 से बराबरी की और फिर 14-13 की बढ़त हासिल की। कीन यियू ने इसके बाद लगातार पांच अंक बनाकर भारतीय खिलाड़ी को इस गेम में वापसी का मौका नहीं दिया।

एक-एक गेम अपने नाम करने के बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच तीसरे गेम में कड़ा मुकाबला हुआ जिसमें ब्रेक के समय सौरभ ने 11-10 की बढ़त हासिल की। ब्रेक के बाद वह कीन यियू पर बढ़त के फासले को अधिक करने में सफल रहे और 21-16 की जीत के साथ चैंपियन बने।

पिछले साल डच ओपन सुपर 100 और रूस ओपन सुपर 100 कर खिताब अपने नाम करने वाले सौरभ ने कहा कि उन्हें कोई वित्तीय मदद नहीं मिलती है और वे इन टूर्नामेंटों में अपने खर्चे पर खेलते हैं।

उन्होंने कहा, 'मेरे पास कोई प्रायोजक या मदद नहीं है। राष्ट्रीय चैंपियन बनने के बाद भी कुछ नहीं बदला। मैं अब भी टूर्नामेंटों में खेल रहा हूं लेकिन उन बातों को सोचने का कोई फायदा नहीं जो आपके हाथ में नहीं हो। मैं फिट रह कर अपने खेल पर ध्यान देना चाहता हूं।' भविष्य की प्रतियोगिताओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, 'मैं सितंबर में चीनी ताइपे ओपन (सुपर 300) और वियतनाम ओपन (सुपर 100) में खेलूंगा।'

विराट कोहली ने ठोका वनडे में 42वां शतक

पोर्ट आफ स्पेन, 11 अगस्त (भाषा)।

कप्तान विराट कोहली की रेकॉर्ड से भरी शतकीय पारी की मदद से भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में रविवार को यहां सात विकेट पर 279 रन बनाए।

कोहली ने 125 गेंदों पर 14 चौकों और एक छक्के की मदद से 120 रन बनाए। यह वनडे में उनका 42वां शतक है। उन्होंने इस बीच श्रेयस अय्यर (68 गेंदों पर 71) के साथ चौथे विकेट के लिए 125 रन जोड़े। वेस्टइंडीज की तरफ से कार्लोस ब्रेथवेट सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 53 रन देकर तीन विकेट लिए।

विराट कोहली

क्रिस गेल

खेल आगे बढ़ने के साथ पिच धीमी होती जा रही है और ऐसे में वेस्टइंडीज के लिये लक्ष्य तक पहुंचना आसान होगा। उसकी निगाहें **क्रिस गेल** पर टिकी रहेंगी जो 300 वनडे खेलने वाले पहले कैरेबियाई बल्लेबाज बन गए हैं। इस मैदान पर सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करने का रेकॉर्ड 272 रन का है। इन दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द करना पड़ा था। तीसरा और अंतिम मैच 14 अगस्त को इसी स्थान पर खेला जाएगा।

पहले ओवर में क्रीज पर उतरे कोहली शुरू से ही लय में दिखे। शिखर धवन (दो) की एक और नाकामी के बाद उन्होंने रोहित शर्मा के साथ दूसरे विकेट के लिए 74 रन जोड़े। इसमें रोहित का योगदान 34 गेंदों पर 18 रन का रहा। कोहली ने इस बीच 19वां रन बनाते ही वेस्टइंडीज के खिलाफ सर्वाधिक व्यक्तिगत रन का रेकॉर्ड अपने नाम किया। इससे पहले यह रेकॉर्ड पाकिस्तान के जावेद मियांदाद (1930) के नाम पर था। कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी 34वीं पारी में 2000 रन भी पूरे करके अपने साथी रोहित का रेकॉर्ड तोड़ा जिन्होंने आस्ट्रेलिया के खिलाफ 37 पारियों में मुकाम पाया था।

कोहली पिछली 11 पारियों का इंतजार खत्म करते हुए 112 गेंदों में अपना सैकड़ा पूरा किया। वेस्टइंडीज के खिलाफ यह उनका आठवां और कप्तान के रूप में छठा शतक है जो कि रेकॉर्ड है। अपनी पारी के दौरान सौरव गांगुली (11363) की रन संख्या पीछे छोड़ा।

अय्यर ने चौथे नंबर पर अपना दावा मजबूत किया। उन्होंने 49 गेंदों पर अपने करिअर का तीसरा अर्धशतक पूरा किया।

कोहली ने लांग आफ पर आसान कैच थमाया जिससे स्कोर चार विकेट पर 226 रन हो गया। इसके बाद भारतीय टीम बाकी बचे 8.3 ओवर में 53 रन ही जोड़ पाई और इस बीच उसने तीन विकेट भी गंवाए।

लगातार दूसरे खिताब पर नडाल की निगाहें

मोंट्रियल, 11 अगस्त (एएफपी)।

सेमी फाइनल में कोर्ट पर उतरे बगैर रफेल नडाल ने मोंट्रियल मास्टर्स के फाइनल में जगह बनाई जहां वह कनाडा में लगातार दूसरा एटीपी खिताब जीतने उतरेंगे। शीर्ष वरीय नडाल को एक दिन का अतिरिक्त आराम मिला जब गेल मोनफिल्स सेमी फाइनल मुकाबले से हट गए। फ्रांस के मोनफिल्स ने वर्षा से प्रभावित क्वार्टर फाइनल में स्पेन के आगुत को 6-4, 3-6, 7-6 से हराया था और इसके कुछ घंटों बाद ही उन्हें सेमी फाइनल में नडाल से भिड़ना था।

जीत के साथ सेरेना फाइनल में

टोरंटो, 11 अगस्त (एएफपी)।

सेरेना विलियम्स ने पहला सेट गंवाने के बाद वापसी करते हुए चेक गणराज्य की क्वालीफायर मेरी बोजकोवा को तीन सेट में हराकर डब्लूटीए टोरंटो टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई।

तीन बार की विजेता सेरेना ने बोजकोवा को सेमी फाइनल में 1-6, 6-3, 6-3 से हराया।

घुटने की दूसरी सर्जरी का फैसला मुश्किल था

एम्सटरडम, 11 अगस्त (भाषा)।

भारतीय टीम से बाहर चल रहे मध्यक्रम के बल्लेबाज सुरेश रैना ने कहा कि दूसरी बार घुटने का ऑपरेशन कराने का फैसला मुश्किल था। उन्हें पता था कि इसके कारण वह कुछ महीनों के लिए क्रिकेट से दूर हो जाएंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज रैना ने कुछ दिन पहले घुटने का ऑपरेशन कराया है। इस चोट के कारण वह पिछले सत्र से परेशान थे और इससे उबरने के लिए उन्हें कम से कम छह हफ्ते के कड़े रिहैबिलिटेशन से गुजरना होगा। इसके कारण वह महीने के अंत में शुरू होने वाले अधिकांश घरेलू सत्र से बाहर रहेंगे।

रैना ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'ईमानदारी से कहूं तो दूसरी बार घुटने का ऑपरेशन कराने का फैसला कड़ा था क्योंकि मुझे पता था कि इसके कारण मैं कुछ महीनों के लिए बाहर हो जाऊंगा। दर्द बढ़ गया था और मुझे पता था कि इससे बाहर निकलने का सिर्फ एक तरीका है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द ही अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा।

भारतीय जूनियर खिलाड़ियों को तीन स्वर्ण सहित छह पदक

पजार्जिक (बुल्गारिया), 11 अगस्त (भाषा)।

भारत के जूनियर बैडमिंटन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बुल्गारिया जूनियर अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में तीन स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य सहित कुल छह पदक जीते।

सामिया इमाद फारूकी ने महिला एकल फाइनल में रूस की दूसरी वरीय अनास्तासिया शापोवालोवा को कड़े मुकाबले में 9-21 21-12 22-20 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। एडविन जाय और श्रुति मिश्रा ने मिश्रित युगल के खिताबी मुकाबले में ब्रेंडन झी हाओ और एबिगेल हैरिस की ब्रिटेन की दूसरी वरीय जोड़ी को 21-14 21-17 से हराकर भारत को दूसरा स्वर्ण पदक दिलाया।

महिला युगल में तनीशा क्रास्तो और अदिति भट की भारतीय जोड़ी ने भी फाइनल में बेनगिसु एरसेटिन और जेहरा एर्डफम की तुर्की की शीर्ष वरीय जोड़ी को 21-15 18-21 21-18 से हराकर सोने का तमगा अपने नाम किया।

इशान भटनागर और विष्णुवर्धन की भारत की पुरुष युगल जोड़ी को हालांकि विलियम जोन्स और ब्रेंडन झी हाओ की ब्रिटेन की शीर्ष वरीय जोड़ी के खिलाफ फाइनल में 19-21 18-21 की हार के साथ रजत पदक से संतोष करना पड़ा।

INDIAN EXPRESS GROUP

NxtGen Infinite Datacenter presents

The Indian EXPRESS EXCELLENCE IN GOVERNANCE AWARDS

Entry by invitation only

21 AUG 2019 6:00 PM
NEW DELHI

CELEBRATING GOOD GOVERNANCE ACROSS INDIA'S DISTRICTS

HONOURING THE FINEST DISTRICT MAGISTRATES IN THE COUNTRY

The Indian Express Excellence in Governance Awards honours District Magistrates from across the country who are scripting the changing India story. Through their ideas, innovations— and implementation.

The awards celebrate best practices across the government, leadership and learning in a range of categories: Health to Inclusion, Technology to Education, Energy to Agriculture.

Special Guests

Shri Nitin Gadkari
Minister for Road Transport and Highways; Micro, Small and Medium Enterprises

Shri Ram Vilas Paswan
Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution

Shri Ravi Shankar Prasad
Minister for Law and Justice; Communications; Electronics and Information Technology

Shri Piyush Goyal
Minister for Railways; Commerce and Industry

Dr Jitendra Singh
Minister of State (Independent Charge), Development of North Eastern Region; Minister of State, Prime Minister's Office; Personnel, Public Grievances and Pensions; Atomic Energy; Space

eigawards.indianexpress.com #EIGAwards

The Indian EXPRESS JOURNALISM OF COURAGE

Banking Partner: ICICI Bank
Realty Partner: Funwal
University Partner: ICFAI Group
Healthcare Partner: Yashoda Super Speciality Hospitals, Kaushambi, Ghaziabad
Drive Partner: Volkswagen

Associate Partners: Kesari, Detox India, Namami Gange, नालको NALCO, IndianOil, 2019 Year of Solutions, MIDC, Joy e-bike, Bharat Petroleum, Petronet LNG

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 267, *हवाई शुल्क :* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।